R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 03
01 से 15 नवम्बर 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

एक्शन में मामा सकते में अफसरान

भ्रष्ट-कामचोर अधिकारियों, कर्मचारियों पर गिर रही गाज

जनता को भा रहा शिवराज का रॉबिनहुड वाला जोरदार अंदाज

मानव के आविर्भाव से बहुत पूर्व, पृथ्वी घने पेड़ों जंगलों एवं पुष्पावलियों से अपनी आदि भव्यता के साथ आच्छादित थी, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता था एवं प्राणि-जीवन की सृष्टि एवं सुरक्षा होती रहती थी। प्रकृति का मानव पर यह एक ऋण था। यह ऋण चुकाना है और अब पृथ्वी को भरापूरा एवं जंगलों को हराभरा रखने की बारी मानव की है ताकि प्रकृति और हमारा सह-अस्तित्व बना रहे और प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में जीवन सुरक्षित रहे। कोयले का वृक्षों से 400 करोड़ वर्षों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव, कोल इण्डिया ने वृक्षरोपण तथा भू-संवर्धन के माध्यम से खनन-कार्य के कारण वृक्षरहित बनी भूमि को पूर्वावस्था में लाने का संकल्प किया है। प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए कोल इण्डिया द्वारा अब तक हज़ारों-हज़ार हेक्टर भूमि में वृक्षरोपण किया जा चुका है।

कोल इण्डिया लिमिटेड

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है

इस अंक में

वल्लभगाथा

8 | सीएस को लेकर असमंजस

मप्र का अगला प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी तक नए मुख्य सचिव की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि नए मुख्य सचिव के लिए अभी भी...

राजपथ

10-11 | मिशन मोड में मप्र

मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस में रणनीति तैयारियां लगातार चल रही हैं। दोनों पार्टियों के रणनीतिकार 2023 में अपनी-अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।

योजना

15 | 80 फीसदी पदों पर होगी नई भर्ती

इस दिवाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, किसानों के साथ ही नौजवानों को भी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 1 लाख पदों पर होने वाली भर्ती में...

अपराध

18 | हनीट्रैप का जिन्न बाहर आया...

2019 में प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में हडकंप मचाने वाले बहुचर्चित हनी ट्रैप केस का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। पिछले दो वर्ष से शांत पड़े इस मामले में अब ईडी की एंट्री हुई है। दरअसल इस मामले में करोड़ों रुपए की ब्लैकमेलिंग की गई थी। बताया जाता है...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में कुछ अलग अंदाज से सरकार चला रहे हैं। चौथी पारी शुरू करते ही वे एंग्री यंगमैन की भूमिका में आ गए। कभी वे मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कभी अफसरों को डांट फटकार रहे हैं। ये उनकी नई पहचान बन गई! सौम्य, सहज और मिलनसार स्वभाव वाले शिवराज का ये नया चेहरा समझ से परे है। इस बार एक्शन वाले रोल में हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि सरकार बदली-बदली सी नजर आ रही है।

19

36

44

45

राजनीति

30-31 | खड़गे के नेतृत्व में...

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के वैसे ही परिणाम सामने आए, जैसे अपेक्षित थे। आशा के अनुरूप मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसान जीत दर्ज की। उनकी जीत का प्रमुख कारण रहा यह अलिखित संदेश कि वह गांधी परिवार की पसंद हैं। इस संदेश की पुष्टि तभी हो गई थी...

राजस्थान

35 | राजस्थान बना राजनीति...

कांग्रेस में मुख्यमंत्री के विवाद के चलते राजस्थान देशभर में चर्चा का गढ़ बना हुआ है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम और फिर राजस्थान में 25 सितंबर को विधायकों के इस्तीफों ने राजस्थान को गपशप का केंद्र बना दिया। पूरे देश की निगाहें राजस्थान पर हैं, क्योंकि...

बिहार

37 | कब आएगी बिहार में बहार

ऐसे कई सवाल हैं, जो आज तक अनसुलझे हैं और उन्हें सुलझाने के लिए जो आत्मबल चाहिए, वहां के राजनीतिज्ञों में उसकी घोर कमी है। ये अपनी कुर्सी पाने से पहले जनता को गफलत में रखते हैं और सत्तासीन हो जाने के बाद उनका दुख जानने, उनकी उम्मीदों...

6-7 अंदर की बात
39 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

हादसों से कब सबक लेंगे हम...?

किसी शायर ने लिखा है...

किसे ख़बर थी कि ये वाकिया भी होना था
कि खेल-खेल में इक हादसा भी होना था

दुर्घटनाएं अनिश्चित होती हैं, कब, कहां किस रूप में घट जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अमूमन इंसान ऐसी परिस्थियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन सच यह भी है कि इंसान होने के डर से कभी हंसना बंद नहीं करता, कल मर जाना है यह सोचकर कोई आज में जीना छोड़ नहीं देता। लेकिन हादसों से सबक लेना जरूरी है। जब कभी हादसा होता है तो शासन-प्रशासन से लेकर आम आदमी उससे सबक लेने की बात कहता है, लेकिन समय के साथ हम सबकुछ भूल जाते हैं। हमारी इसी भूल का नतीजा है गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने का हादसा। इससे पहले जब 21 जुलाई 2001 में काढालुंडी रिवर रेल ब्रिज, केरल (57 मौतें), 10 सितंबर 2002 में रफीगंज रेल ब्रिज, बिहार (130 मौतें), 29 अक्टूबर 2005 में वेलिगोंडा रेलवे ब्रिज, आंध्र प्रदेश (114 मौतें) में हादसे हुए तो इनसे सबक लेने की बात कही गई। लेकिन 30 अक्टूबर 2022 को घटित हादसे ने यह दिखा दिया कि हम पुराने हादसों को भूल गए थे। गुजरात के मोरबी में क्षमता से पांच गुना अधिक लोगों के चढ़ने और सेल्फी लेने की होड़ में मच्छु नदी पर बना ऐतिहासिक झूलता पुल (केबल पुल) टूट गया और 132 लोगों की मौत हो गई। पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, मगर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त करीब 500 लोग थे। मृतकों में 50 महिलाएं व बच्चे भी हैं। मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा गुजरात की एक प्रतिष्ठित कंपनी ओरेवा ग्रुप के पास थी। बता दें कि ओरेवा ग्रुप वही कंपनी है जो घर-घर में मौजूद अजन्ता ब्रांड की घड़ियों का निर्माण करती है। ओरेवा ग्रुप को कंपनी के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी 15 वर्षों के लिए दी गई थी। इसी वर्ष मार्च में ब्रिज के पुनरुद्धार के लिए इसे बंद कर दिया गया था। इसे बीते 26 अक्टूबर को ही गुजराती नववर्ष के मौके पर दोबारा खोला गया था। ब्रिज की सैर के लिए कंपनी लोगों से 17 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क भी वसूल रही थी। सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा संभालने वाली मोरबी स्थिति ओरेवा ग्रुप अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी प्रचलित है। कंपनी दीवार घड़ियों से लेकर ई-बाइक्स और इलेक्ट्रिकल बल्ब तक का निर्माण करती है। हादसे के बाद कंपनी लोगों के निशाने पर आ गई है। पुल का मेंटेनेंस कार्य हासिल करने से पहले कंपनी ने दावा किया था कि वह नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से पुल को इस रूप में विकसित करना चाहती है जिससे दीवार घड़ियों के निर्माण के लिए पहले से मशहूर मोरबी को एक नई पहचान मिले। इस भयानक हादसे ने मोरबी के लोगों कों फिर से एक दर्दनाक घटना की याद दिला दी थी। यह हादसा मच्छू नदी के डैम टूटने से हुआ था। 11 अगस्त 1979 को लगातार बारिश और स्थानीय नदियों में बाढ़ के चलते मच्छु डैम ओवरफ्लो होकर टूट गया और 15 मिनट में ही डैम के पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। देखते ही देखते मकान और इमारतें गिर गईं थी, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 1439 लोगों और 12,849 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई थी। ऐसी न जानें कितनी मौतें हर साल होती हैं, लेकिन हम हादसों से सबक नहीं लेते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 3, पृष्ठ-48, 1 से 15 नवंबर, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

परिवारवाद की बेल

प्रदेश से लेकर देशभर की राजनीति में परिवारवाद की बेल लंबी है। भाजपा हो या कांग्रेस सभी पार्टियों में परिवारवाद देखने को मिलता है। 2023 में मप्र के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी संतानों को टिकट दिलाने की फिराक में हैं।

● **सोमेश कटारिया,** मंदसौर (म.प्र.)

आदिवासियों पर नजर

मप्र की राजनीति के केंद्र में इस समय आदिवासी हैं। चुनाव के लिए आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति से बेचैन कांग्रेस ने अब आदिवासियों को कांग्रेस से जोड़े रखने की प्लानिंग पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई थी।

● **विजय सोलंकी,** भोपाल (म.प्र.)

सड़कों का जाल

मप्र में शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन सड़कों पर होने वाले गड्ढे परेशानी का सबब बनते रहते हैं। ऐसे में जर्जर सड़कों का पेंचवर्क कराने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला लागू करने की मंशा बनाई है। सरकार का यह कदम सराहनीय है।

● **गुंजन शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

मप्र में चुनाव प्रचार

मप्र इस समय राजनीति का हॉटस्पॉट बना हुआ है। केंद्र की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हर पार्टी का नेता मप्र की दहलीज पर प्रचार-प्रसार कर रहा है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय भी दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही मप्र में वोट की राजनीति करने आए थे। मप्र में भाजपा की सरकार है। मौजूद वक्त में यहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की यहां 230 सीटें हैं। अगले साल नवंबर 2023 में यहां विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहां अगले साल नवंबर से पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है। सभी पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी केंद्रीय संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

● **जितेंद्र सूर्यवंशी,** राजगढ़ (म.प्र.)

कांग्रेस दिखाए मजबूती

कांग्रेस इस समय चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। केंद्र की राजनीति से लेकर अन्य कई राज्यों में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल दिया है। वर्तमान समय में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। अब इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास एक मौका है कि वे ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरकर भले ही जीत न दर्ज कर पाए लेकिन कम से कम विपक्ष के तौर पर तो खड़ी रहे। आने वाले साल भी चुनावी साल के रूप में नजर आने वाले हैं। इसमें भी कांग्रेस को मजबूती दिखानी होगी।

● **प्रिया सोनवाल,** सीहोर (म.प्र.)

गरीबों को मिलेगा आशियाना

मप्र में एंटी माफिया अभियान में राज्य शासन ने भू-माफिया, गुंडों और आदतन अपराधियों के विरूद्ध सख्त रुख अपनाते हुए दो साल में 15 हजार 397 एकड़ से अधिक राजस्व, नगरीय निकाय और वन भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही 6105 एकड़ निजी और अन्य विभागों की भूमि भी मुक्त कराई गई है। मुक्त कराई गई भूमि की कीमत 18 हजार 146 करोड़ रुपए है। अब इन जमीनों पर सरकार गरीबों के आशियाने बनवाएगी। सरकार की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है।

● **अंकिता पिल्लई,** शिवपुरी (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बढ़ती तल्खी

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्तों की तल्खी लगातार बढ़ रही है। कभी नीतीश को बिहारी पृष्ठभूमि वाले पीके इतने भा गए थे कि अपनी पार्टी का पदाधिकारी बना दिया था। मंत्री जैसी सरकारी हैसियत भी दी थी। भरोसा कायम रहता तो शायद राज्यसभा भी भेज देते। लेकिन दोनों में अनबन हुई और पीके ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया तो समीकरणों का रसायन बिगड़ गया। अब पीके ने नया शिगूफा छोड़ा है। उनका दावा है कि नीतीश अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं। वे फिर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसके पीछे संपर्क सूत्र पीके ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह को बताया है। दरअसल, भाजपा से गठबंधन टूट जाने के बाद भी हरिवंश ने उपसभापति पद से इस्तीफा नहीं दिया। वे कह चुके हैं कि वे अपने दायित्व का निर्वाह नीतीश की सहमति से ही कर रहे हैं। उधर जनता दल (एकी) के महासचिव केसी त्यागी ने पीके के बयान को गलत बताया है और सफाई दी है कि नीतीश खुद घोषित कर चुके हैं कि वे भाजपा के साथ आइंदा नहीं जाएंगे। पीके का भाजपा हितैषी होने का नीतीश का आरोप बेबुनियाद लगता भी नहीं। एक तो पीके कभी भी भाजपा पर वार नहीं करते। दूसरे, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेरिका छोड़कर भाजपा की चुनावी रणनीति बनाने ही तो वापस आए थे वे अपने देश।

दीदी का पैतरा

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कमजोर कर अपनी जड़ें जमाने की भाजपाई कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। अलबत्ता भाजपा खुद ही ममता बनर्जी को कोई न कोई ऐसा मुद्दा थमा देती है, जिसका सियासी फायदा उठाने में दीदी चूकती नहीं। वैसे तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में पुरजोर ताकत लगाने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से भाजपा का मनोबल कमजोर हुआ था। पार्टी को दूसरा नुकसान तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं की घर वापसी की होड़ से हुआ था। देश के बाकी राज्यों में कांग्रेसी जिस तरह लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कुछ उसी तरह का नजारा पश्चिम बंगाल में दिखता है। फर्क है तो बस इतना कि वहां पार्टी छोड़ने वाले भाजपाई हैं और उनका रुझान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की तरफ है। दो पाटन के बीच फंस गए हों जैसे। भाजपा में रहते हैं तो पश्चिम बंगाल की पुलिस पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ती है, भाजपा छोड़ते हैं तो सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजंसियों का भूत पीछे लग जाता है। लेकिन, ममता को भाजपा ने नया मुद्दा दादा के तिरस्कार से दिया है। दादा यानी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल जाने पर भी गांगुली की जगह रोजर बिन्नी बन गए बीसीसीआई के अध्यक्ष।

प्रियंका की बढ़ेगी जिम्मेदारी

राहुल गांधी के नेतृत्व में बीते एक महीने से जारी कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' के चलते कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों के भीतर होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। चर्चा है कि प्रियंका इन दोनों प्रदेशों के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। क्योंकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों 'भारत जोड़ो यात्रा' में व्यस्त हैं। चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी दोनों प्रदेशों के चुनाव में मुख्य प्रचारक होंगे। जानकारों की मानें तो प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती हैं। उनके गुजरात चुनाव प्रचार कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पार्टी ने वीरभद्र सिंह की पत्नी और तीन बार की सांसद प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार का खराब प्रदर्शन अहम मुद्दे हैं। पार्टी इन मुद्दों को पूरी शिद्दत से उठा रही है। हालांकि पार्टी सूत्रों की मानें तो राहुल हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे।

फिर पीएम के हनुमान बनेंगे चिराग!

बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के अलग होने के बाद से ही भाजपा अपने संगठन और सहयोगियों को लेकर चिंता में है। बताया जा रहा है कि जल्द ही भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही एक बार फिर चिराग पासवान भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं। कुछ समय पहले पार्टी ने विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया है और उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि संगठन में फेरबदल किया जाएगा। पार्टी संगठन के साथ-साथ भाजपा सहयोगी दलों की तलाश में भी लगी है। चर्चा है कि भाजपा अपने तमाम पुराने सहयोगी दलों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी का पशुपति पारस गुट भाजपा के साथ है और खुद पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हालांकि इस गुट को लेकर भाजपा के नेता बहुत आश्वस्त नहीं हैं। यह सबको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन नीतीश कुमार की पार्टी की पहल पर हुआ था और उसका मकसद चिराग पासवान को अलग-थलग करना था।

टीआरएस में मनमुटाव

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पुरानी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के रूप में नई पार्टी लॉन्च कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की लॉन्चिंग तो हो गई लेकिन कुछ नेताओं के मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस भव्य कार्यक्रम में उनकी बेटी कविता अनुपस्थित रहीं जिससे सियासी अटकलें तेज हो गईं हैं। कहा जा रहा है कि कविता न केवल इस हाई-प्रोफाइल इवेंट से गायब थीं, बल्कि उनका नाम आगामी मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए टीआरएस के प्रभारी की सूची से गायब होने के चलते भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केसीआर के घर में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कहा जाने लगा है कि जल्द ही पार्टी के दो फाड़ हो सकते हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में पहला कदम है।

...फिर मनेगी दिवाली

प्रदेश में प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम करने की जिम्मेदारी उठाने वाला बोर्ड इन दिनों खुद इतना प्रदूषित है कि वहां कार्यरत कर्मचारी हाय-तौबा मचाए हुए हैं। बताया जाता है कि जबसे इस बोर्ड की कमान 1993 बैच के एक आईएएस अधिकारी ने संभाली है, तब से यहां उनकी मनमानी के कारण अधिकारी-कर्मचारी परेशान हैं। साहब की मनमानी का आलम यह है कि यहां के अधिकारी-कर्मचारी तीज-त्यौहारों की खुशियां भी नहीं मना पा रहे हैं। इस संदर्भ में उनका कहना है कि जब साहब की विदाई होगी, तभी हम दिवाली मनाएंगे। दरअसल, साहब ने विभाग में ऐसा तांडव मचाकर रखा है कि उनकी करतूतों से हर कोई हतोत्साहित है। साहब ने विभाग की कमान संभालते ही यहां अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने 80 कर्मचारियों को 20:50 के फॉर्मूले पर नौकरी से बाहर कर दिया। हालांकि कर्मचारी कोर्ट चले गए और वहां से स्टे लेकर आ गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। साहब यहीं नहीं रुके और उन्होंने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन नियम को निरस्त करा दिया। साहब की इन मनमानियों से विभाग में अफरा-तफरी का माहौल है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि साहब अपने मातहतों को नीचा दिखाने और उन्हें परेशान करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते हैं। फाइलें लेकर पहुंचने वाले अफसरों को फटकार के साथ ही फाइलें फाड़ भी देते हैं।

काम के न काज के...

यह लोकोक्ति तो आपने सुनी ही होगी कि काम के न काज के...दुश्मन अनाज के। इस लोकोक्ति को इन दिनों प्रदेश के एक बड़े विभाग के बड़े साहब सार्थक कर रहे हैं। गौरतलब है कि साहब जबसे इस विभाग के मुखिया बने हैं, उनकी हरकतों से सब परेशान हैं। आलम यह है कि विभाग के मंत्री को तो वे तनिक भी भाव नहीं देते हैं। कई बार इनकी भर्राशाही और लालफीताशाही के कारण सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। लेकिन उसके बाद भी साहब की हरकतें कम नहीं हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कहने को तो विभाग को साहब चला रहे हैं, लेकिन सारा काम सचिव कर रहे हैं। साहब इन दिनों बस एक ही काम में जुटे हुए हैं, वह है लक्ष्मी संग्रह।

बताया जाता है कि साहब ने इंजीनियरों से उगाही शुरू कर दी है। वे इंजीनियरों को खुद फोन लगाते हैं और उनसे चढ़ावे की मांग करते हैं। साहब की इन करतूतों से विभाग में उनके अधीनस्थ जो अन्य आईएएस अधिकारी हैं, वे काफी नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि साहब अकेले ही सबकुछ डकार रहे हैं। साहब की हरकतों की वजह विभाग में उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई है। अधिकारी हो या कर्मचारी सभी साहब के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए हैं।

बर्बाद कॉम्प्लेक्स को जीवन देने की कोशिश

बड़ी उम्मीद के साथ एक कंपनी ने राजधानी के हृदय स्थल पर एक बड़ा कमर्शियल एवं आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाया था। कंपनी को उम्मीद थी कि यह कॉम्प्लेक्स उन्हें आबाद कर देगा। इसके लिए कंपनी ने मंत्रियों और अधिकारियों को खूब पैसे भी बांटे। लेकिन उसी दौरान निर्मित हुए एक अखबार के मॉल ने उक्त कंपनी के सपने पर पानी फेर दिया। इसका असर यह हुआ कि उक्त कंपनी का कॉम्प्लेक्स पूरी तरह फ्लॉप हो गया। भव्य और आकर्षक साज-सज्जा के साथ बने इस कॉम्प्लेक्स में जिन लोगों ने निवेश किया है, वे भी पछता रहे हैं। कंपनी द्वारा निर्मित इस कॉम्प्लेक्स को बर्बाद होने से बचाने के लिए मप्र हाउसिंग बोर्ड आगे आया। लेकिन उसके अफसरों ने इसे नया जीवन देने के लिए इतने कड़े नियम बना डाले कि उससे कॉम्प्लेक्स को कोई फायदा मिलता नहीं दिखा। बार-बार के प्रयोग से आज स्थिति यह हो गई है कि इस कॉम्प्लेक्स की लीज निरस्तीकरण की तैयारी होने लगी है। ऐसे में इस कमर्शियल एवं आवासीय कॉम्प्लेक्स को उबारने के लिए एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के सुपुत्र आगे आए हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस मॉल के कारण इस कॉम्प्लेक्स की दुर्दशा हुई है, उस कॉम्प्लेक्स में रिलायंस डिजिटल की फ्रेंचाइजी लेकर कारोबार कर रहे साहब के सुपुत्र लीज को 2 साल और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके इस कॉम्प्लेक्स को जीवन मिल सके। अब देखना यह है कि आईएएस अधिकारी के सुपुत्र इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं।

तिकड़ी की मिलीभगत

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सहित तीन अफसरों के बन रहे मकान चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल, उपरोक्त तीनों अफसर एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। इसलिए इन्हें प्रशासनिक वीथिका में तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। यह तिकड़ी एक साथ अपना-अपना मकान बनवा रही है। सूत्रों का कहना है कि किसी के ईंट, किसी के सीमेंट और किसी के सरिये से बन रहे इन तीनों मकानों में एसेसरीज भी एक जैसी लग रही है। इसलिए ये तीनों मकान चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि इन मकानों में से एक के स्वामी लोक निर्माण विभाग में साहब हैं। इन साहब ने तीनों मकानों में एक जैसी एसेसरीज लगाने का प्लान बनाया है और इसके लिए बकायदा अपने विभाग में सामान सप्लाई करने वाले सप्लायरों पर दबाव बनाकर सामान मंगवाया है। बताया जाता है कि तीनों अधिकारी मिलजुल कर एक ही तरह की डिजाइन को फाइनल करते हैं और उसके बाद उसके लिए सप्लायरों के पास डिमांड भेज देते हैं।

मुझसे रहम की उम्मीद न करें

हमेशा शांत और सहज दिखने वाले 2009 बैच के आईएएस अधिकारी जब उखड़ते हैं तो उनके सहयोगी कंपकंपा जाते हैं। साहब जब से प्रदेश के सबसे संपन्न जिले के कलेक्टर बने हैं जिले की रंगत ही बदल गई है। इसकी वजह यह है कि जब कोई अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम करता है तो साहब उनकी पीठ थपथपाने में भी देर नहीं करते हैं। वहीं जरा सी लापरवाही पर सबक सिखाने से भी नहीं चूकते। गत दिनों उन्होंने जिले के अफसरों को बैठक में हिदायत देते हुए कहा कि हाल ही में अपर कलेक्टर पर हुई कार्रवाई से अंदाजा लगा लो कि मुख्यमंत्री जरूरतमंदों की मदद को लेकर कितने सख्त हैं। मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। काम नहीं किया तो दंड मिलेगा। बैठक में कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारियां याद दिलाईं। पहले काम नहीं किया, इसलिए मुख्यमंत्री को अभियान छेड़कर जरूरतमंदों की मदद करना पड़ रही है। यह सारी योजनाएं आज से नहीं पहले से संचालित हैं, लेकिन कर्मचारियों की कामचोरी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री की फटकार भी सुननी पड़ रही है।

इस पखवाड़े प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका (मंत्रालय) में कई तरह की उथल-पुथल देखने को मिली। जहां नए सीएस को लेकर असमंजस का दौर जारी है, वहीं अफसरों और मंत्रियों के बीच खींचतान जोरों पर है। वहीं कई मंत्रियों के बेलगाम बोल चर्चा में रहे।

सीएस को लेकर असमंजस

मप्र का अगला प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी तक नए मुख्य सचिव की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि नए मुख्य सचिव के लिए अभी भी अनुराग जैन सबसे आगे हैं। वहीं गत दिनों उन्होंने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सपरिवार मुलाकात की तो उनके सीएस बनने की संभावना प्रबल हो गई है। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही है कि सरकार वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को एक्सटेंशन दे सकती है। दरअसल इस सबंध में पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही निर्भर करता है कि वे मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि दिलाते हैं या फिर किसी नए अधिकारी को उनकी जगह देखना चाहते हैं। दरअसल इकबाल सिंह को गुजरात की तर्ज पर एक साल के लिए सेवावृद्धि मिल सकती है। अगर बैंस का एक्सटेंशन नहीं होता है तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सचिव प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अनुराग जैन व अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान में से किसी एक को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावनाएं अधिक बनी हुई हैं। अनुराग जैन मुख्यमंत्री के पसंदीदा अफसर तो पहले से ही माने जाते रहे हैं, साथ ही वे मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव भी रह चुके हैं। यह बात अलग है कि केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह उन्हें वापस प्रदेश में भेजे या नहीं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में भी माना जाता है। वे प्रधानमंत्री कार्यालय में भी संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। इसकी वजह से माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार कहीं आने वाले समय में सचिव वित्त भी बना सकती है। इसकी वजह से उनका केंद्रीय कैबिनेट सचिव बनने की रास्ता खुल सकता है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि शायद ही वे वापस लौटने में रूचि लें। इस स्थिति में माना जा रहा है कि मोहम्मद सुलेमान को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। सुलेमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद खास अफसरों में गिने जाते हैं। इसकी वजह है उनकी कार्यशैली। सुलेमान को सीएस बनाने के लिए गुजरात के उद्योगपति भी सिफारिश कर सकते हैं। पूर्व सीएस अवनि वैश्य के लिए इसी तरह की सिफारिश एक राजनीतिक पार्टी के महासचिव ने की थी।

नए कमिश्नर्स की खोज

विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले सरकार अधिकारियों की जमावट का खाका तैयार कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर को भी बदलने पर विचार कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाना। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किए हुए लगभग दो साल हो गए हैं। बताया जाता है कि सरकार की मंशानुसार इन दो सालों में दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रभावी नहीं रहा है। इसलिए प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों इस बात की सुगबुगाहट है कि सरकार भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर और इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र को बदल सकती है।

संघ के काम धड़ाधड़

प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बताए जा रहे काम सपाटे से हो रहे हैं। बताया जाता है कि इसके लिए सत्ता और संगठन ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित कर रखा है। इसका असर यह हो रहा है कि संघ के पदाधिकारियों द्वारा जो भी काम विभागों या अफसरों को बताए जा रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करके काम बताने वाले को बकायदा सूचित भी किया जा रहा है। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि कई अधिकारी संघ के माध्यम से अपना काम कराने में अधिक रूचि ले रहे हैं।

सिंधिया समर्थक मंत्रियों से सब नाराज

एक तरफ सरकार चुनावी मोड में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों की बदजुबानी, भर्राशाही, तानाशाही से अफसरशाही के साथ ही नेता भी परेशान और नाराज हैं। सत्ता और संगठन को जिस मंत्री ने सबसे अधिक पसोपेश में डाला है, वह हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। उन्होंने परिवहन विभाग को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है, जब इस विभाग को मंत्री चला रहे हैं, जबकि पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह विभाग काम करता था। दूसरे हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। इनकी विभाग के अफसरों से पटरी नहीं बैठ रही है। वहीं इनकी बेलगामी से सरकार की छवि धूमिल हुई है। इनके कई कामों पर सीएस ने भी सवाल उठाए हैं। तीसरे हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। इनकी मनमानी के कारण इंदौर के सारे नेता इनसे असंतुष्ट चल रहे हैं। ये इंदौर में भाजपा के नेताओं पर ग्रहण की तरह हावी हैं। चौथे हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। इन्होंने इन दिनों चप्पल उतार दी हैं। यही नहीं वे कहते फिर रहे हैं कि मैं तो अधिकारविहीन मंत्री हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वे सरकार और पार्टी के लिए भले ही मुसीबत बने हुए हैं, लेकिन जनता से लगातार जुड़े हैं।

● **सुनील सिंह**

शीतकालीन सत्र में होगी आर-पार की लड़ाई...

मप्र में राजनीति में नवंबर-दिसंबर का महीना उठापटक वाला रहने वाला है। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले होने वाले शीतकालीन सत्र में जहां एक तरफ सत्र हंगामेदार होने की संभावना है, वहीं इसी सत्र में कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।

पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को दी है। सिंह ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस अविश्वास प्रस्ताव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाला मुख्य मुद्दे होंगे। उधर भाजपा भी कांग्रेस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी शीतकालीन सत्र में मप्र में कोई बड़ा खेला हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ कांग्रेस तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस काम में पूर्व विधायक पारस सकलेचा सहयोग कर रहे हैं। विधायकों से भी भ्रष्टाचार संबंधी प्रमाणिक जानकारियां मांगी जा रही हैं। कांग्रेस विधायक दल ने वर्ष 2013 में शिवराज सरकार के विरुद्ध आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई थी। इसके पहले वर्ष 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर चार दिन सदन में चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। अभी तक सरकार के ऊपर तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो चुका है। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से अधिक है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि से हर व्यक्ति परेशान है। अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। कारम बांध में जिस तरह अधिकारियों की ठेकेदारों से मिलीभगत की बात सामने आई है, उसे मुद्दा बनाया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज, पुलिस भर्ती घोटाला, ओबीसी आरक्षण सहित अन्य विषयों को लेकर भी पार्टी स्तर पर तैयारी की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में जैविक खाद के वितरण की गड़बड़ी को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अभी तक दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाई है। पहले वर्ष 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर चार दिन सदन में चर्चा हुई थी। उसके बाद जुलाई 2013 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जो उप नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह चतुर्वेदी के भाजपा में चले जाने से गिर गया था। इसके बाद 2013 से 2018 के बीच विधानसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। अब अगले साल विधानसभा के चुनाव होना है जिसके चलते कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है जिसकी बिंदुबार तैयारी की जा रही है। इस बार भिंड से ही आने वाले डॉ. गोविंद सिंह को अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियां बेच रही है। प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है जो इस वित्तीय वर्ष के अंत में सवा 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से अधिक है। सरकारी विभागों में एक लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। 2013 से अब तक आम जनता के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। गैस सिलेंडर अब 1053 रुपए का हो गया है। पेट्रोल की कीमतें 40 और डीजल 75 फीसदी तक महंगा हो गया है। सरसों तेल 200 रुपए किलो और आटा 40 रुपए प्रति किलो हो गया है। प्रदेश में ई-टेंडरिंग घोटाले की परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। कारम डेम फूट गया, अन्य नए बने बांधों की हालत जर्जर है। पुल, पुलिया उखड़ रही हैं। व्यापमं के बाद प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाले समेत अन्य घोटाले हुए हैं। प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के चलते अब तक प्रदेश में 52 फीसदी आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।

● **विकास दुबे**

जुटाए जा रहे हैं तथ्य

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार को घेरने के लिए तथ्य जटाए जा रहे हैं। इसे लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को इसमें कुछ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। उधर, पार्टी के विधायकों से कहा गया है कि वे भ्रष्टाचार से जुड़े प्रामाणिक मुद्दे दें, ताकि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव में शामिल किया जा सके। पूर्व विधायक पारस सकलेचा भी इस काम में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने बताया कि हम मानसून सत्र में ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया था कि मानसून सत्र की अवधि कम से कम 20 दिन रखी जाए। सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया था। इसमें पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और फिर सरकार अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर पास करा लिया गया। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए समय नहीं बचा। अब विधानसभा के नवंबर-दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। यदि तब भी सरकार सत्र की अवधि पर्याप्त नहीं रखती है तो सदन में ही धरना दिया जाएगा।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इस कारण इस समय मप्र पूरी तरह मिशन मोड़ में नजर आ रहा है। दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि 2023 में उनकी सरकार बने। इसके लिए रोज नई रणनीति और नई चुनावी नीति बनाई जा रही है। भाजपा की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व भी मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। हालांकि चुनावी तैयारी में कांग्रेस पीछे है, लेकिन पार्टी जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर तक जमावट करने में जुटी हुई है।

मिशन मोड में मप्र

मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस में रणनीति तैयारियां लगातार चल रही हैं। दोनों पार्टियों के रणनीतिकार 2023 में अपनी-अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों पार्टियों ने मिशन 2023 के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया है। इसके तहत भाजपा ने पिछले चुनाव में हारी 103 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा को पुराने नेता याद आए हैं। यानी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए बड़ी जमावट की है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस एक सैकड़ा से अधिक सीटों पर समीकरण साधेगी।

मिशन 2023 में 200 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही भाजपा 2018 में हारी 103 विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सीटों को मजबूत करने के लिए भाजपा की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व संगठन मंत्रियों, वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ चुनिंदा विधायकों को एक-एक सीट सौंप दी गई, ताकि ये वहां जाकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें और जो लोग किसी कारण से संगठन से दूर हो गए हैं, उन्हें भी एक्टिव करें। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा वहां मैदानी स्तर पर और मेहनत करें। सीटों के साथ बूथ का ग्रेड ए, बी, सी एवं डी तय करने को भी कहा गया है।

भाजपा ने 2018 में हारी हुई सीटों को आकांक्षी नाम दिया गया है, जिनके प्रभारी तय हो गए हैं। इनमें 6 पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ, आशुतोष तिवारी, जितेंद्र लिटोरिया, केशव सिंह भदौरिया, पूर्व प्रदेश पदाधिकारी विनोद गोटिया, विधायक राजेंद्र शुक्ला आदि शामिल हैं। इन प्रभारियों को काम सौंपा गया है कि जिलों में यदि मोर्चे, प्रकोष्ठ समेत अन्य कोई पद खाली है तो भरा जाएगा। कांग्रेस से भाजपा में आए हारने वाले विधायकों के क्षेत्रों में निष्क्रिय हो चुके कार्यकर्ताओं को समझाना। जो घोषणाएं होनी है और जिनके काम शुरू कराने है, उनका फीडबैक देना। शर्मा व राव ने कहा कि हर सीट के बूथ पर 10 प्रतिशत वोट कैसे बढ़ सकते हैं, इसकी रणनीति तैयार करें। राव ने कहा कि हर बूथ का एक्शन प्लान होना चाहिए। तभी वोट शेयर बढ़ेगा। इसके लिए कौन से कदम उठाना है, उसकी जानकारी पार्टी को दें।

यही नहीं मिशन-2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने कांग्रेस के कब्जे वाली 96 विधानसभा सीटों को छीनने के लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का इन सीटों पर विशेष फोकस रहेगा। सभी सीटों पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। उनकी निगरानी में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को घेरने की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा उन 7 सीटों पर भी भाजपा फोकस कर रही है, जिन पर सपा-बसपा और निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे। 230 सीटों वाली मप्र विधानसभा में भाजपा के पास 127 सीटें हैं। वहीं, कांग्रेस के कब्जे में 96 और अन्य के पास 7 सीटें हैं। भाजपा इस तैयारी में है कि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के प्रति नाराजगी का वह फायदा उठा ले। इसी उद्देश्य से भाजपा ने कुल 103 सीटों पर चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

उपचुनाव वाली सीटों पर घमासान की स्थिति

पार्टी सूत्रों का कहना है कि आंतरिक सर्वे और पंचायत चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिला है उसमें पार्टी के आधा सैकड़ा से अधिक विधायकों की स्थिति चिंताजनक है। इनमें उपचुनाव में जीतने वाले विधायक भी हैं। ऐसे में उपचुनाव वाली 32 में से ज्यादातर सीटों पर टिकट को लेकर सबसे ज्यादा जद्दोजहद की स्थिति बनेगी। क्योंकि कई सीटों पर पुराने नेता संकेत दे चुके हैं, निकाय चुनाव में खुलेआम बगावत के दृश्य सामने आ चुके हैं इसलिए पार्टी भी यह बात जानती है कि कार्यकर्ताओं पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। यही वजह है कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सभी 65 हजार बूथों को मजबूत और 10 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने की मुहिम शुरू की है। ग्वालियर, डबरा, बमोरी, सुरखी, सांची, सांवेर, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, भांडेर, करैरा, पोहरी, अशोकनगर, मुंगावली, अनूपपुर, हाटपिपल्या, बदनावर, सुवासरा, नेपानगर, मांधाता एवं दमोह में उपचुनाव हुए थे। इनमें से 22 सीटें सिंधिया के समर्थन में खाली हुई 3 अन्य बाद में रिक्त जौरा, आगर, ब्यावरा, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर सीटों पर विधायकों के निधन होने से उपचुनाव की नौबत आई। 32 में से 11 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई।

उधर, कांग्रेस प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में प्रवेश की नई तारीख आई है। यात्रा महाराष्ट्र से बुरहानपुर जिले में 20 नवंबर तक प्रवेश करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने गत दिनों बैठक में यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस काम में 70 विधायकों को लगाया गया है। हर एक काम का एक प्रभारी बनाया गया है जो सभी सरकारी परमिशन से लेकर खाद्य व्यवस्था और यात्रियों के रुकने का इंतजाम करेंगे। इन प्रभारियों को 30 अक्टूबर को यात्रा स्थल पर ले जाया जाएगा।

मप्र में यात्रा की कमान खुद कमलनाथ ने अपने हाथों में ले ली है जो यात्रा के इंचार्ज पीसी शर्मा के साथ रोजाना समीक्षा करेंगे। चार घंटे चली बैठक में दिग्विजय सिंह ने खासतौर पर आवश्यक निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को सरकार से सभी परमिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रचार-प्रसार का काम अशोक सिंह को सौंपा गया है। सज्जन सिंह वर्मा को आम सभाएं आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक संजय शुक्ला और नीरज दीक्षित खान पान की व्यवस्था देखेंगे। विशाल पटेल और संजय शर्मा को यात्रियों के रुकने के लिए लॉजिस्टिक प्रबंध किए जाने का काम सौंपा गया है। सभाओं के लिए मंच कहां बनाए जाएंगे, रवि जोशी और बालमुकुंद गौतम इसकी जानकारी कमलनाथ को बताएंगे। अजय सिंह मॉनिटरिंग, निलय डागा और सुभाष सोजतिया परिवहन देखेंगे। मिशन 2023 की तैयारी में जुट कांग्रेस मप्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेगी। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पार्टी के रणनीतिकारों को भारत जोड़ो यात्रा को मप्र में भव्य बनाने की रणनीति बनाई है। राहुल गांधी की इस यात्रा में मप्र से 5 उपयात्राएं जुड़ेंगी। इन उपयात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा में ये सभी उपयात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगी। मप्र के 52 जिलों में कांग्रेस की भारत जोड़ो की उपयात्राएं 35 दिन में 6021 किमी की यात्राएं करेंगी। यह उपयात्राएं बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में समाहित हो जाएंगी। यह 230 विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगी।

मप्र में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक और विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता उपयात्राएं निकाल रहे हैं। इसके लिए जिला प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। विधायक और पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी इन यात्राओं में पदयात्रा करेंगे। मप्र के अलग-अलग जिलों और विधानसभाओं में निकलने वाली उपयात्राओं में शामिल होने वाले नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि वे कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करने में सक्षम हैं। जानकारी के अनुसार जो पांच उपयात्राएं निकाली जाएंगी, उनमें से बालाघाट से शुरू होने वाली उपयात्रा सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल हरदा होते हुए खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगी। बड़वानी से खरगोन तक आएगी और उपयात्रा में जुड़ जाएगी। वहीं अनूपपुर से उपयात्रा शुरू होकर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, देवास होते हुए इंदौर में जुड़ेगी। अलीराजपुर से शुरू होकर झाबुआ, धार होते हुए इंदौर में जुड़ेगी। शहडोल से उपयात्रा शुरू होकर उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, रायसेन, सीहोर, शाजापुर होते हुए उज्जैन में जुड़ेगी। भोपाल से सीहोर, कुरावर, पचोर, खुजनेर, नलखेड़ा, सुसनेर में जुड़ेगी। जबकि जावद (नीमच) से शुरू हुई यात्रा मल्हारगढ़, मंदसौर, रतलाम, खाचरोद होते हुए उज्जैन में जुड़ेगी। भानपुरा (मंदसौर) से शुरू हुई यात्रा सुवासरा, महिदपुर होकर उज्जैन में जुड़ेगी। सिंगरौली से सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर तक, निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर तक, छतरपुर से सागर, विदिशा, राजगढ़ होते हुए आगर मालवा में ये यात्रा जुड़ेगी। वहीं भिंड, दतिया से शिवपुरी-मुरैना से ग्वालियर, शिवपुरी-श्योपुर से शिवपुरी-शिवपुरी से अशोकनगर, गुना, राजगढ़ होकर आगर मालवा में ये यात्रा जुड़ेगी।

मप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ गया है जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकला है। भाजपा के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। इनमें कुछ वे विधायक भी हैं जो पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा की रणनीति है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल जिताऊ विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

मेहनती कार्यकर्ताओं को मिलेगी जिलों की कमान

मप्र कांग्रेस में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने इसके संकेत दे दिए हैं। सभी 52 जिलों के संगठन प्रभारी बदलने के बाद कमलनाथ अब जिलों के अध्यक्षों को बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है उन्हें बदला जा सकता है। बताया जाता है कि करीब 25 से 30 जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर हैं। इनकी जगह पार्टी परिणाम देने वाले और मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका देगी। पीसीसी के सूत्रों के अनुसार आधे जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इनमें निष्क्रिय जिलाध्यक्षों के साथ ही ऐसे जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं जिन्होंने निकाय चुनाव में पार्टी के साथ गड़बड़ी की। ऐसे कांग्रेस नेताओं की छुट्टी तय है। दरअसल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। मप्र कांग्रेस ने कांग्रेस संगठन को मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में 5 नगर निगमों में कांग्रेस को मिली कामयाबी से कार्यकर्ताओं के हौंसले भी बुलंद हुए हैं। इसके बाद कमलनाथ ने प्रदेश में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली है। वे विधायकों से जिलाध्यक्षों का प्रभार भी वापस ले रहे हैं। उनके स्थान पर पार्टी के फुल टाइम वर्कर को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। कांग्रेस के निष्क्रिय जिलाध्यक्षों की छुट्टी होगी। पीसीसी सूत्रों के मुताबिक करीब 25 से 30 जिलों के अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इनमें निकाय चुनाव में गड़बड़ी करने वाले जिलाध्यक्ष भी हैं।

मिशन 2023 से पहले मप्र भाजपा के नेताओं की गुजरात में परीक्षा होने वाली है। भाजपा आलाकमान ने गुजरात में कमल खिलाने के लिए मप्र के 5 मंत्रियों सहित सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग में उतारा है। मप्र के नेताओं को राज्य की सीमाओं से जुड़े गुजरात के विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मप्र के 5 मंत्रियों की लगी स्पेशल ड्यूटी

भाजपा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई है। गुजरात में लगातार जीत का रिकॉर्ड कायम रखने के लिए मप्र सरकार के चार मंत्रियों नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, इंदर सिंह परमार और विश्वास सारंग को मोर्चे पर तैनात किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश से लगभग 1000 कार्यकर्त्ता गुजरात जाएंगे। जबकि करीब 100 पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। भाजपा इन विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर बनाए हुए हैं।

नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। इन चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि मप्र में अगले साल चुनाव हैं, इसलिए यहां के कई नेताओं को गुजरात में चुनाव प्रबंधन और उसके पहले बूथ प्रबंधन की जवाबदारी दी गई है। इसी क्रम में प्रदेश के चार मंत्रियों नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, इंदर सिंह परमार और विश्वास सारंग की केंद्रीय संगठन ने गुजरात विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगा दी है। इसके अलावा सांसद गजेंद्र पटेल को भी गुजरात चुनाव में लगाया गया है। दरअसल, भाजपा विधानसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों से उन कार्यकर्ताओं को पहले ही बुला लेती है, जिन्हें कई राज्यों में चुनाव के दौरान सांगठनिक कार्यों का लंबा अनुभव हो। इन जमीनी कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्र की **सामाजिक, आर्थिक** और भौगोलिक स्थिति के अनुसार रणनीति बनाने में महारत होती है। जानकारों का कहना है कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी सहित बिखरा हुआ कुछ विपक्ष भाजपा के खिलाफ अंदरूनी तौर पर एकजुट है। ऐसे में संगठन की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा सकती।

गुजरात में फिर से कमल खिलाने के लिए एक पदाधिकारी को पांच से छह विधानसभाओं का जिम्मा दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को बाव, घानेरा, डीसा और दियोदर विधानसभा सीटों की जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरह अरविंद भदौरिया को जंबूसर, बागरा, झघडीया, भरूच और अंकलेश्वर, इंदर सिंह को मातर, नंडीयाद, महेमबाद, महुधा, ठासरा, कमडगंज, मंत्री विश्वास सारंग को दांता, झालोद, लीमखेड़ा, दाहोद, गरबाड़ा और देवगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। सांसद गजेंद्र पटेल को दाहोद और इसके आसपास की विधानसभाएं दी गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय भाजपा संगठन ने उप्र समेत कई राज्यों के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी चुनाव में लगाया है। मप्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने कहा कि मप्र के कार्यकर्ता गुजरात में अपने-अपने प्रभार के विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। वहां पांच बूथों पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया हैं। सभी जगह बैठक भी हो गई है। प्रवासी कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी की भूमिका निभाएंगे।

गुजरात भाजपा संगठन की आज चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में हिस्सा लेने मंत्री गुजरात पहुंच गए हैं। मंत्रियों के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मप्र भाजपा ने अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी भेजा है। समन्वय की जिम्मेदारी मप्र भाजपा उपाध्यक्ष जीतू जिराती और पूर्व संगठन मंत्री श्याम महाजन को सौंपी गई है। कार्यकर्ताओं में पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी, पूर्व संगठन मंत्री शामिल हैं। मप्र के मालवांचल से गुजरात की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। **आदिवासी क्षेत्र** में दोनों राज्यों में रोटी-बेटी के संबंध वाले लोगों की संख्या बहुत है। यही वजह है कि पार्टी ने मप्र के नेताओं को गुजरात के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया है।

● राजेश बोरकर

गुजरात को चार जोन में बांटा

गुजरात को भाजपा ने चुनावी तैयारी के हिसाब से चार अलग-अलग जोन में बांटा है। इनमें दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मप्र के कार्यकर्ताओं को सौराष्ट्र का प्रभार सौंपा गया है। सौराष्ट्र में मप्र से दो प्रभारी बनाए गए हैं। एक जीतू जिराती हैं, जिन्हें चुनाव लड़ने से लेकर प्रबंधन का बेहतर अनुभव है। वहीं, पूर्व संगठन मंत्री श्याम महाजन को संगठन का काम सौंपा है। इनके साथ सातों जिलों में दो-दो प्रभारी बनाए गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी दो-दो कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर के साथ इनकी एक बैठक हो गई है। मप्र के झाबुआ और आलीराजपुर से गुजरात के सात जिले दाहौद खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, बढ़ौदा ग्रामीण, बढ़ौदा नगर और आणंद जिले लगे हुए हैं। इन क्षेत्रों में मप्र से ऐसे कार्यकर्ता भेजे हैं, जिनका वहां कहीं प्रभाव या अच्छा संपर्क है। फिलहाल, यह कार्यकर्ता वहां संगठनात्मक कार्यों में मदद के साथ चुनावी जमावट को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। गुजरात के लिए यह प्रारंभिक तैनाती है, इसके बाद वरिष्ठ नेताओं को भी भेजा जाएगा। पार्टी इस बार गुजरात के दामाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वहां के चुनाव प्रचार में लगा सकती है। प्रत्येक विधानसभा में संगठन की दृष्टि से एक प्रभारी रहेगा तो एक अन्य प्रभारी राजनीतिक दृष्टि से समझने वाला रहेगा। प्रदेश के पूर्व विधायक, विधायक और वरिष्ठ नेताओं की 115 लोगों की टीम वहां पहले ही भेजी गई है। दोनों साथ-साथ काम करेंगे। इसके लिए गुजरात के प्रदेश संगठन द्वारा सभी प्रभारियों को बूथ स्तर तक का डाटा उपलब्ध कराया गया है। जिन बूथों पर भाजपा चुनाव हारी है, उसको लेकर भी अलग से रणनीति बनाई जाएगी। पुराने प्रत्याशी कितने वोटों से हारे और जीते, इसको लेकर भी डाटा प्रभारियों को दिया गया है। सभी से कहा गया है कि चुनाव होने तक वहीं रहें और अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में काम करें। हालांकि अभी त्योहारों को देखते हुए कुछ दिनों की छूट मिली है।

कृषि यंत्रीकरण घोटाला

मंदसौर जिले में उद्यानिकी विभाग के कृषि यंत्रीकरण घोटाले में लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन डायरेक्टर सत्यानंद (आईएफएस अफसर) के साथ ही 15 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें कई अधिकारी हैं। जांच में पाया गया है कि मंदसौर के उप संचालक मनीष चौहान ने यंत्रीकरण की राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर करने के बजाय फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और सीधे सप्लायर्स से यंत्र खरीदकर किसानों को दिए गए। इनकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। ऐसे भी कई किसान थे, जिनको खेतों में खड़ा कर फोटो खींच लिए, लेकिन यंत्र नहीं दिए गए। घोटाले की शिकायत मुकेश पाटीदार ने उज्जैन लोकायुक्त में की थी। एकीकृत बागवानी मिशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गड़बड़ी सामने आई थी।

लोकायुक्त पुलिस ने विभाग के पूर्व संचालक सत्यानंद, मंदसौर के तत्कालीन उप संचालक मनीष चौहान, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी राजेश जाटव, पप्पू लाल पाटीदार, बनवारी वर्मा, राजेश मईड़ा, सत्यम मंडलोई, सुरेश धाकड़, दिनेश पाटीदार, निजी फर्म के संचालक सुरेश भाई पटेल, प्रवीण मूलजी पटेल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मंदसौर के कृषि यंत्रीकरण घोटाले की जांच सरकार भी करा चुकी है। इसमें सामने आया था कि अफसरों ने किसानों को डेढ़ लाख कीमत के पावर टिलर की जगह सस्ते पावर विडर और पावर स्प्रेयर बांट दिए थे। इनकी कीमत 21 से 52 हजार रुपए है। यह भी साफ हो गया है कि सारे कृषि यंत्र मेड इन चाइना हैं। उद्यानिकी विभाग ने एमपी एग्रो के एमडी श्रीकांत बनोठ की अध्यक्षता में चार तकनीकी अफसरों की जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सभी जिलों से किसानों को बांटे गए दो-दो कृषि यंत्र पुष्टि के लिए भोपाल बुलवाए थे।

लोकायुक्त को मुकेश पाटीदार निवासी मंदसौर ने शिकायत की थी। इसमें उद्यानिकी विभाग मंदसौर में पदस्थ मनीष चौहान, उप-संचालक उद्यानिकी एवं अन्य द्वारा मंदसौर जिले में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यंत्रीकरण योजना तथा संरक्षित खेती योजना में नियमों के विपरीत कार्य कर भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत की गई थी। लोकायुक्त की जांच में विभाग में संचालित योजनाएं तथा राज्य योजनाएं, एकीकृत बागवानी मिशन योजना यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय औषधि मिशन में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि मंदसौर जिले को तुलनात्मक दृष्टि से योजनाओं में अत्याधिक राशि स्वीकृत की गई। इसमें उप संचालक मनीष चौहान ने केंद्र पोषित योजना में राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करके सीधे यंत्र प्रदाता कंपनी से सांठगांठ कर उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। यही नहीं हितग्राही का चयन भी मनमाने तरीके से किया गया तथा एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को यंत्र प्रदाय किए गए।

इतना ही नहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनार के पौधों एवं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के भुगतान में भी अनयिमताएं पाई गई हैं। इन योजनाओं का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से हितग्राही कृषक के बैंक खाते में भेजना था, जो नहीं करते हुए सीधे पौधा वितरण कंपनी एवं ड्रिप इरीगेशन संयंत्र कंपनी को भुगतान कर दिया गया। योजनांतर्गत प्रदान किए गए अनार के सभी पौधे वर्ष 2017-18 में गर्मी पड़ने से सूख गए तथा किसानों को कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई। उद्यानिकी विभाग ने प्रथम आओ प्रथम पाओ नीति का भी पालन नहीं किया तथा यंत्र प्रदाता कंपनी द्वारा किसानों से सीधे भुगतान प्राप्त किया गया। योजना की शर्तों में द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही अनुदान राशि का भुगतान करना था, लेकिन राशि पौधा वितरित करने के बाद ही कंपनियों को प्रदान कर दी गई।

संरक्षित खेती योजना अंतर्गत पॉली हाउस/ शेडनेट हाउस/ वॉक इन टनल से संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों का पालन भी नहीं हुआ है। हितग्राहियों के खातों में अनुदान राशि का भुगतान न करते हुए किसान एग्रोटेक एवं अन्य कंपनियों के खातों में भुगतान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में नियम विरूद्ध तरीके से अमानक स्तर के कृषि यंत्रों की कथित खरीदी तथा यंत्र प्रदाता कंपनियों एवं अनार पौधा एवं ड्रिप इरीगेशन वितरण कंपनियों को नियम विरूद्ध तरीके से कृषक अनुदान राशि का भुगतान कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई गई।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

इनके खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में सत्यानंद, तत्कालीन संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मप्र भोपाल, मनीष चौहान, उप संचालक, उद्यानिकी विभाग मंदसौर, राजेश जाटव, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं सह प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, पप्पूलाल पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मंदसौर, बनवारी वर्मा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, विकासखंड, सीतामऊ, जिला मंदसौर, राजेश मईड़ा, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड गरोठ जिला मंदसौर, सत्यम मंडलोई, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड भानपुरा, जिला मंदसौर, सुरेश सिंह धाकड़, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मंदसौर, दिनेश पाटीदार, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मंदसौर, प्रोप्राइटर-सुरेश मणिभाई पटेल, फर्म-गणेश ट्रेडिंग कंपनी, जबलपुर निवासी ग्राम आमोद, तहसील पिटलाद, जिला आणंद गुजरात, प्रोप्राइटर प्रवीण भाई मूलजी, फर्म-छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस निहार अस्पताल के सामने, धंधा रोड़, जेवरा सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ, निवासी-कातुलबोर्ड वार्ड नं. 59, मकान नंबर 16/90 हरिनगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, प्रोप्राइटर-मितुलभाई पिता प्रवीणभाई पटेल, फर्म-जेएम इंटरप्राईजेस, हरिनगर दुर्ग, छत्तीसगढ़, मिहिर पण्ड्या, डायरेक्टर, एबीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी, प्रालि, ब्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात, मंगलन शिवदासन, डायरेक्टर, एवीसी एग्रोबॉयोटेक कंपनी प्रालि, ब्लॉक नंबर 347744 सरदार नगर इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी स्टेट, ग्राम छापरा, जिला खेड़ा, गुजरात, शिवसिंह मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट नंबर 75-86 सेक्टर सेकेंड पीथमपुर धार (मप्र) आदि के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

भारत में घटने लगी प्रजनन दर

भारत ने इस मायने में इतिहास बना दिया है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास आखिर वांछित परिणाम दिखा रहे हैं। प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे चली गई है। प्रजनन दर में गिरावट की इस गति का भारत जैसे देश के लिए सकारात्मक अर्थ संकेत हैं, क्योंकि इससे देश की जनसंख्या अब 2030 तक चीन से अधिक नहीं हो सकती है। प्रजनन क्षमता में यह गिरावट सभी समुदायों में देखी जा रही है। नवीनतान आंकड़ों के मुताबिक, हिंदू महिलाओं की कुल प्रजनन दर 1.94 है और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह 2.2 है, जबकि ईसाई समुदाय की प्रजनन दर 1.88, सिख समुदाय 1.61, जैन समुदाय 1.6 और बौद्ध और नव-बौद्ध समुदाय 1.39 है। सीधे शब्दों में कहें, तो यह एक एकल परिवार में बच्चों की औसत संख्या है। प्रतिस्थापन स्तर की उर्वरता उस स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर जनसंख्या बिलकुल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बदल लेती है। इस प्रकार यदि यह स्तर पर्याप्त रूप से लंबी अवधि तक बना रहता है, तो शून्य जनसंख्या वृद्धि होती है। अधिकांश देशों में यह दर लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला है। हालांकि यह मृत्यु दर के साथ मामूली रूप से भिन्न हो सकती है। प्रतिस्थापन स्तर की उर्वरता शून्य जनसंख्या वृद्धि को तभी बढ़ावा देगी, जब मृत्यु दर स्थिर रहे और प्रवास का कोई प्रभाव न पड़े।

भारत में अधिक जनसंख्या एक बड़ी चुनौती रही है और देश में गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी अधिकांश समस्याओं का एक बड़ा कारण है। नमूना पंजीकरण प्रणाली डाटा 2020 के अनुसार, भारत की सामान्य प्रजनन दर (एक वर्ष में 15-49 के प्रजनन आयु वर्ग में प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या) में पिछले एक दशक में 20 फीसदी की गिरावट आई है। गिरावट की इस दर का मतलब है कि भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पछाड़ नहीं पाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, औसत सामान्य प्रजनन दर सन् 2018 से सन् 2020 के बीच 68.7 है, जबकि सन् 2008 सन् 2010 के बीच यह 86.1 थी। गिरती प्रजनन दर को कई संरचनात्मक हस्तक्षेपों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि शादी की उम्र में वृद्धि, महिलाओं में साक्षरता दर में सुधार, और आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों की आसान और व्यापक उपलब्धता आदि।

नमूना पंजीकरण प्रणाली डाटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुरूप है, जिसमें भारत की कुल प्रजनन दर (प्रजनन आयु की प्रति महिला जन्म दर) 2015-16 की 2.2 से गिरकर 2019-2021 में 2.0 हो गई है। हालांकि कुल प्रजनन दर में गिरावट एक समान नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह शहरी क्षेत्रों में 15.6 फीसदी की तुलना में 20.2 फीसदी है। एक ग्रामीण महिला का टीएफआर 2.2 है, जबकि एक शहरी महिला का 1.6 है। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर में गिरावट को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं साक्षरता, आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं की जागरूकता में असमानता है, जिससे विसंगतियां बढ़ रही हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए) में चंडीगढ़ में कुल प्रजनन दर 1.4 से लेकर उप्र में 2.4 तक देखी गई। मप्र, राजस्थान, झारखंड और उप्र को छोड़कर कई राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर (2.1) हासिल कर लिया है। रिपोर्ट बताती हैं कि दो से ऊपर की कुल प्रजनन दर वाले पांच राज्य बिहार, मेघालय, उप्र, झारखंड और मणिपुर थे। हरियाणा, असम, गुजरात, उत्तराखंड और मिजोरम 1.9 पर कुल प्रजनन दर दो थी। 6 राज्य- केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा 1.8 पर थे। इसके अलावा 1.7 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा थे, जबकि इस सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल में टीएफआर सबसे कम 1.6 था।

आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो दशक में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू और कश्मीर ने सभी राज्यों में सामान्य प्रजनन दर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है। अपनी प्रजनन क्षमता में गिरावट के बावजूद भारत में अभी भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। हालांकि बड़ी या तेजी से गिरावट, जनसंख्या वृद्धि दर अनुमानित 1.9 फीसदी प्रति वर्ष है। दुनिया के केवल तीन देशों नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में विकास की उच्च दर है। राष्ट्रीय परिवार के पांचवें दौर के निष्कर्षों के अनुसार, कुल प्रजनन दर, जो कि किसी भी महिला से उसके जीवनकाल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या है; 2015-16 के 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई थी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

सरकारी परिवार नियोजन नीतियों का योगदान

प्रजनन क्षमता में गिरावट का श्रेय साक्षरता, शहरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिक संचार और परिवहन और महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को दिया जाता है। सरकारी परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता ने भी प्रजनन क्षमता में गिरावट में योगदान दिया है। शहरी क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता में तेजी से गिरावट आई है, जो कि 1,00,000 से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों में केंद्रित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के अनुसार, समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (सीपीआर) देश में 54 फीसदी से बढ़कर 67 फीसदी हो गई है। लगभग सभी राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है। परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतों में 13 फीसदी से 9 फीसदी की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। अतीत में भारत में एक प्रमुख मुद्दा बनी रही रिक्ति की अधूरी आवश्यकता अब घटकर 4 फीसदी से भी कम रह गई है। भारत में संस्थागत जन्म 79 फीसदी से बढ़कर 89 फीसदी हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 87 फीसदी जन्म स्वास्थ्य सुविधाओं में होता है और शहरी क्षेत्रों में यह 94 फीसदी है। जनसंख्या वृद्धि स्वास्थ्य और मृत्यु दर में सुधार के लिए जिम्मेदार है। जीवन प्रत्याशा बढ़कर 60 वर्ष हो गई है और शिशु मृत्यु दर घटकर 74 प्रति 1,000 हो गई है।

80 फीसदी पदों पर होगी नई भर्ती

इस दिवाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, किसानों के साथ ही नौजवानों को भी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 1 लाख पदों पर होने वाली भर्ती में नौजवानों को 80 हजार पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार मेलों का निरंतर आयोजन किया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी करने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मप्र में एक लाख से अधिक सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाने के बाद अब सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि विभागों में खाली पड़े 80 फीसदी पदों पर नई भर्ती करें। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों को भरने की जो घोषणा की है, लेकिन इनमें से फ्रेशर्स की भर्ती 80 हजार पदों पर ही की जाएगी। शेष 20 हजार पद पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्या करीब 72 हजार है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लाख पदों में से 20 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि शासन का ध्यान गया है कि 20 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए। साथ ही नियमित पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होने पर शेष पदों को किस प्रकार भरा जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। अत: पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद भी कुछ विभागों ने रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी थी। इसको लेकर जीएडी ने इन विभागों को हर हाल में 12 अक्टूबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के संबंध में निर्देश दिए थे। इन विभागों की ओर से जानकारी भेज दी गई है। रिक्त पदों की संख्या करीब 3 हजार और बढ़ गई है। गौरतलब है कि पूर्व में विभिन्न विभागों की ओर से भेजी गई जानकारी के मुताबिक राज्य संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या 1 लाख 1 हजार 958 थी। स्कूली 11 शिक्षा विभाग में राज्य संवर्ग के सबसे ज्यादा 45 हजार 767 पद रिक्त है। अब यह संख्या बढ़कर करीब 1 लाख 5 हजार हो गई है।

विभागों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा में 263565 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 45767 पद रिक्त हैं। इसी तरह स्वास्थ्य में 50431 पदों में से 14313 रिक्त हैं। जनजातीय कार्य में 23394 पदों में से 7780 रिक्त हैं। वन में 17853 पदों में से 2229 रिक्त हैं। पशुपालन में 8378 पदों में से 1794 रिक्त हैं। पंचायत में 7196 पदों में से 2220 रिक्त हैं। जेल में 5544 पदों में सं 575 रिक्त हैं। महिला-बाल विकास में 4789 पदों में से 588 रिक्त हैं। लोक निर्माण में 4627 पदों में से 750 रिक्त हैं। वाणिज्यिक कर में 4021 पदों में से 1311 रिक्त हैं। राजस्व में 4007 पदों में से 968 रिक्त हैं। आयुष में 3839 पदों में से 1290 रिक्त हैं। वित्त में 3346 पदों में से 1133 रिक्त हैं। श्रम में 2494 पदों में से 762 रिक्त हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार का कहना है कि 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। जिस वर्ग को जितना आरक्षण निर्धारित है, उतना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी विभागों को संविदा पाट आरक्षित कर्मचारियों को 20 प्रतिशत पद करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। विभागों की ओर से कैडर के हिसाब से प्रस्ताव मप्र लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जा रहे हैं। मप्र संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि संविदा कर्मी बीते 5 से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब उन्हें फिर से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होगा, जबकि वे पूर्व में परीक्षा, इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद वे इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे नए सिलेबस के साथ परीक्षा में युवाओं का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, इसलिए परीक्षा की बजाय संविदा कर्मियों को अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए। नगरीय प्रशासन विभाग में संविदा उपयंत्री, अकाउंट एड एक्सपर्ट, फायर बिग्रेड मैनेजर, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छता सहायक आदि पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

● **राकेश ग्रोवर**

30 नवंबर से नगरीय निकायों में होगी संविदा भर्ती

मप्र के नगरीय निकायों में 413 संविदा कर्मचारियों के रिक्त पदों को 30 नवंबर तक भरा जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए समय सीमा दे दी। वहीं रिक्त नियमित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा लेने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की मानें तो 6 महीने या उससे अधिक अवधि में खाली पदों पर नगरीय प्रशासन विभाग भर्ती करेगा। नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी से कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, खासकर तकनीकी काम के लिए कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों की कमी होने के कारण नगर निगम और नगर पालिकाओं में आए दिन समस्याओं का अंबार लगा रहता है। नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी यह बात सामने आई थी जून 2021 में विभाग ने संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तय करते हुए नियम भी जारी कर दिए थे पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब अधिकारियों से कहा गया है कि नगर पालिका संविदा सेवा नियम 2021 के अनुसार तय समय सीमा में संविदा नियुक्ति करें। नगर पालिक निगमों में संविदा के पदों की भर्ती के लिए आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास तथा नगर पालिका परिषद द्वारा नगर परिषद के लिए संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

कोरोना संक्रमण के दौर से लेकर अब तक मप्र सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उससे आज देश की जीडीपी में मप्र का योगदान 3.6 से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड के कठिन दौर में इस साल मप्र की ग्रोथ रेट करेंट प्राइसेज पर 19.76 प्रतिशत रही है। ये देश में सबसे ऊपर है। इसमें आने वाले दिनों में और उछाल आने की संभावना है। क्योंकि मप्र निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

मप्र भरेगा आर्थिक उड़ान

मप्र आज देश में औद्योगिक हब बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी नीतियों के कारण देश-विदेश के उद्योगपति मप्र में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश की औद्योगिक उड़ान में पंख लगाने के लिए सरकार 10 और 11 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है। इसी सिलसिले में गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली और पुणे में देश के प्रमुख उद्यमियों से मप्र में निवेश के संबंध में चर्चा की और उन्हें इंवेस्टर्स समिट में आने का न्यौता दिया। सरकार को उम्मीद है कि इस बार समिट में प्रदेश में औद्योगिक निवेश के रिकॉर्ड प्रस्ताव मिलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में समिट से पहले ही निवेश के प्रस्ताव आने लगे हैं। इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति मिल रही है।

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार की तैयारियों को निवेशकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। करीब दर्जनभर कंपनियों ने अभी से मप्र में निवेश की तैयारी शुरू कर दी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में मप्र निवेश का केंद्र बनेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समिट के पहले इंदौर में प्रस्तावित 6 क्लस्टर को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कोरोनाकाल के बाद अब प्रदेश में जनवरी में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को बड़े स्वरूप में करने की तैयारी है। इसके तहत लाखों के करार होंगे, जिनके लिए अभी से निवेशक कंपनियां तैयार होने लगी हैं। लगभग 12 कंपनियों ने प्रारंभिक रूप से निवेश की ओर कदम बढ़ाए हैं। कुछ निवेशक जमीन देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ चयन कर चुके हैं। कुछ ने अभी निवेश की रूचि दिखाकर सेक्टर तय किए हैं। इन दिनों प्रदेश में औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार हो रहा है। ग्रीन एनर्जी, आर्गेनिक खाद से लेकर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आकार ले रही हैं। भोपाल-राजगढ़ में 250 करोड़ से ग्रीन एनर्जी पार्क बनना है। इसमें 15 टन प्रतिदिन क्षमता का बायोगैस प्लांट, ऑर्गेनिक खाद, 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का कार्बनडाईऑक्साइड कैप्चर प्लांट और 10 मेगावाट क्षमता का केप्टिव सोलर पॉवर प्लांट बनेंगे। हाइड्रोजन व अमोनिया गैस भी बनेगी। वहीं भोपाल-इंदौर-जबलपुर-ग्वालियर-कटनी सहित 7 प्रमुख क्षेत्रों में एयरपोर्ट व सड़क कनेक्टिविटी वाले बड़े लॉजिस्टिक पार्क लाने की तैयारी है। भोपाल-इंदौर कॉरिडोर में आष्टा के समीप बड़े क्षेत्र पर एआई व आईटी हब के लिए प्लान है। पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ से बनना है। बैरसिया-भोपाल में 25.88 करोड़, आष्टा-सीहोर में 99.43 करोड़, धार में 79.43 करोड़, रतलाम में 462 करोड़ और नरसिंहपुर में 47.82 करोड़ की परियोजना है। इनमें 32 हजार करोड़ का निवेश संभावित है। इसके साथ ही 38 हजार रोजगार मिलेंगे।

देश के हृदय प्रदेश में स्थित मप्र में आज औद्योगिक निवेश के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं। मप्र में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। टेक्सटाईल, खाद्य प्र-संस्करण, फार्मास्युटिकल सेक्टर सहित सभी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए मप्र आकर्षण का केंद्र है। यहां सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम और समय-सीमा में पूर्ण करना संभव हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी मप्र, देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है।

इन्वेस्ट के लिए सबसे अच्छी जगह मप्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन मप्र कार्यक्रम में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की और जनवरी में इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का भी न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 550 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने रोडमैप भी बताया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मप्र शांति का टापू है। प्रत्येक उद्यम के लिए यहां स्किल मैन पावर की उपलब्धता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप हमने बनाया है। हमने तय किया है कि 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मप्र को बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र में हमारे मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, इंफ्रा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत उत्तम प्रदेश है। ई-व्हीकल भविष्य की जरूरत है इसलिए हमने मप्र में ईवी पार्क बनाने का फैसला किया है।

भारत को वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को पूर्ण करने मप्र में निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 1 लाख 22 हजार एकड़ का लैंड बैंक, पर्याप्त पानी, बिजली, रोड नेटवर्क, दक्ष मानव संसाधन और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में निवेशकों को किसी भी तरह की समस्या आने नहीं दी जाएगी।

दरअसल, कोरोनाकाल के कारण बीते दो सालों से इंवेस्टर्स समिट नहीं हो सकी है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय मैग्निफिसेंट मप्र के नाम से इंवेस्टर्स समिट हुई थी। 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके तत्काल बाद कोरोना का कहर शुरू हो गया। इस कारण इन्वेस्टमेंट प्लान और समिट की तैयारियां धरी रह गईं। एक साल से स्थिति सुधर रही है। ऐसे में इंवेस्टर्स समिट को लेकर बड़े निवेश का ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। इंवेस्टर्स समिट पहले नवंबर में होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर जनवरी 2023 में कर दिया गया है। इसके तहत मेगा शो होगा। सामान्यत: अब इंवेस्टर्स समिट में एमओयू नहीं घोषित किए जाते हैं। समिट में केवल ईओआई यानी इंट्रेस्ट ऑफ इंवेस्टमेट प्रस्ताव ही घोषित किए जाते हैं। जनवरी की तैयारी के लिए पहले से निवेशकों से बातचीत की जा रही है। प्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से पहले की निवेश के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार अब तक करीब 51 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच चुके हैं। 12 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं, जो सहमति निवेश के लिए दे चुकी हैं। कंपनियों के निवेश प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से कुछ ने जगह भी फाइनल कर दी है। खास बात ये है कि ई-व्हीकल, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में भी इस बार निवेश आना है। इसके लिए प्रारंभिक सहमतियां बनी हैं। वहीं फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और आईटी जैसे सेक्टर भी निवेश के मामले में अभी से फाइनल हो चुके हैं। इन सेक्टर्स में विभिन्न कंपनियों ने रूचि दिखाई है। लगभग छह विदेशी कंपनियों

के प्रस्ताव भी गंभीरता से विचार-विमर्श के स्तर पर हैं। यूएस, कनाडा सहित कई देशों की कंपनियों ने निवेश में रूचि दिखाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दो विदेश दौरे पूर्व में जुलाई में प्रस्तावित थे, लेकिन स्थानीय चुनाव आने के कारण दौरे नहीं हो सके। अब फिलहाल मुख्यमंत्री के पास दौरे मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद और दिल्ली के प्रस्तावित हैं। विदेश दौरे को लेकर नए सिरे से प्लानिंग की जाएगी। इंदौर में प्रस्तावित 6 क्लस्टर पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। यह क्लस्टर अलग-अलग इंडस्ट्री सेक्टर के होंगे। जिसमें लगभग 1 हजार 20 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश होगा। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे इन 6 क्लस्टर में 585 उद्योग स्थापित होंगे। जिससे इंदौर में लगभग 18 हजार 500 लोगों को प्रत्यक्ष व इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रुपए से रोजगार मिलेगा। इंदौर में टॉय क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर को लेकर एमएसएमई विभाग काम कर रहा है। वहीं बहु उत्पाद क्लस्टर, फार्मा पार्क, दाम मिल क्लस्टर प्लास्टिक क्लस्टर को तैयार किया जा रहा है।

देश की राजधानी दिल्ली में टेक्सटाइल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रमुख उद्यमियों से मप्र में निवेश के संबंध में चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और यहां उपस्थित व्यवस्थाओं को उद्यमियों के सामने रखते हुए प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि औद्योगिक इकाई स्थापित करने में जो भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, वो सभी मप्र में उपलब्ध हैं। प्रदेश में लैंड बैंक है, आप उंगली रखिए और एक महीने के अंदर सारी औपचारिकताएं पूरी करके जमीन आवंटित कर दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से मप्र में इन्वेस्ट करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र इन्वेस्ट फ्रेंडली प्रदेश है। निवेशकों की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम पुरानी नीतियों में भी परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि मप्र अद्भुत प्रदेश है। जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, कृषि संपदा, प्रकृति ने मप्र को भरपूर दिया है। सवाल केवल इच्छाशक्ति का था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में मप्र का योगदान 3.6 से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हुआ है। हमारी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही हैं। मप्र में आज चारों तरफ शानदार सड़कें और नेशनल हाईवे हैं। कोविड के कठिन दौर में इस साल मप्र की ग्रोथ रेट करेंट प्राइसेज पर 19.76 प्रतिशत रही है। ये देश में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो मप्र में ओवरऑल साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था थी। हमारे मन में एक जुनून सवार हुआ कि बिन पानी सब सून। आज हम 45 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गए हैं और 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएंगे।

● **कुमार विनोद**

सवा लाख एकड़ जमीन हमारे पास

मुख्यमंत्री ने बताया कि लैंडबैंक हमारे पास तैयार है। 1 लाख 22 हजार एकड़ जमीन अलग-अलग हिस्सों में चिन्हित है। अगर चाहिए तो आपको 1 महीने के अंदर हम दे सकते हैं। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कहां-कहां हमारे पास लैंड के पीसेज हैं। आप मप्र आकर घूमें, पसंद आए तो बाद में देख लें। कंपरेटिवली अगर देखें तो मप्र में मुंबई-पुणे के मुकाबले जमीन सस्ती उपलब्ध है। पीथमपुर के निकट मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए सकारात्मक एवं कंड्यूसिव इकोसिस्टम उपलब्ध है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। मप्र के शरबती गेंहू का विश्वभर में निर्यात किया जा रहा है। विश्व की कई बड़ी कंपनियों की इकाइयां प्रदेश में संचालित हैं। उन्होंने कहा कि पांच महीनों में ही 2021-22 में इसी अवधि की तुलना में गेहूं की दोगुनी मात्रा का निर्यात हो रहा है। हमने अप्रैल-अगस्त 2022-23 के दौरान 43.50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) का निर्यात किया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 116.7 प्रतिशत अधिक था।

हनीट्रैप का जिन्न बाहर आया...

2019 में प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में हडकंप मचाने वाले बहुचर्चित हनी ट्रैप केस का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। पिछले दो वर्ष से शांत पड़े इस मामले में अब ईडी की एंट्री हुई है। दरअसल इस मामले में करोड़ों रुपए की ब्लैकमेलिंग की गई थी। बताया जाता है कि इस मामले में आरोपी रहे दर्जनभर से अधिक लोगों को ईडी ने दिल्ली तलब किया है। जिसमें सूबे की दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेताओं के साथ ही आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी हैं। ईडी के इस कदम से प्रदेश में हडकंप मच गया है।

गौरतलब है कि जब बहुचर्चित हनीट्रैप मामला सामने आया था तो कई अफसरों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। इस मामले के कई सफेदपोशों को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने अब इस मामले में आरोपी बनाए गए दर्जनभर से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर इसी सप्ताह ईडी मुख्यालय नई दिल्ली तलब किया है। इस बात की जानकारी मिलते ही राजनीतिक व प्रशासनिक हल्कों में हडकंप मच गया है।

गौरतलब है कि हनीट्रैप मामले में लंबे समय तक जेल में रही महिलाएं भी जमानत पर छूटकर बाहर आ गई हैं। उन्हें भी ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनके खातों से हुए लेनदेन की विस्तार से जांच की जाएगी। ईडी द्वारा लेनदेन की जांच में कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, जिसके आधार पर ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सूत्रों का कहना है कि पहली बार हनीट्रैप मामले में ईडी की एंट्री हुई है, इससे मामले की गंभीरता का भी पता चलता है। उल्लेखनीय है कि पुलिस महिलाओं के पास से कई सबूत जुटा चुकी है, जिसमें करीब 1 हजार वीडियो और कई गेजेट्स, स्पाय कैमरे और सॉफ्टवेयर हैं। जिसकी मदद से इन शातिर हसीनाओं ने वीडियो बनाए और करोड़ों रुपए ऐठे। अपने इन हाईप्रोफाइल शिकार के जरिए इस गैंग ने करोड़ों रुपए जमा किए। सूत्रों की मानें कि अब तक इनके पास से 90 ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें 20 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस अफसरों के साथ नेताओं के भी वीडियो हैं। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं ने एक दर्जन नेता, 14 आईएएस अफसर, 9 आईपीएस अफसरों को अपना शिकार बनाया।

प्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप केस की जांच कर रही एसआईटी के तत्कालीन चीफ राजेंद्र कुमार ने रिटायरमेंट से पहले हाईकोर्ट को बंद लिफाफा सौंपा था। इस लिफाफे में 40 रसूखदारों की कुंडली बंद है। इसमें कई राजनेता, आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम बताए जा रहे हैं। यदि इन नामों की जांच की जाती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 2019 में नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह ने इंदौर पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी सीडी बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस शिकायत पर पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की को गिरफ्तार किया, जिसके साथ हरभजन सिंह की सीडी थी। इसके बाद उस लड़की से पूछताछ के बाद पुलिस ने श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, आरती दयाल, बरखा सोनी और ड्राइवर अभिषेक ठाकुर की गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन हुआ और भोपाल स्थित आरोपी महिलाओं के ठिकानों पर दबिश देकर लाखों रुपए नकदी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हनीट्रैप के कई वीडियोज थे और इन्हीं वीडियोज के आधार पर एसआईटी ने हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में 40 रसूखदारों के नाम दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक मप्र की सियासत में हड़कंप मचाने वाले हनीट्रैप मामले में पांच महिलाओं ने करीब 20 लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली की है। किसी से 50 लाख तो किसी से तीन करोड़ रुपए तक की वसूली की गई। लाखों-करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आने के बाद मामले की छानबीन आयकर इन्वेस्टीगेशन विंग को भी सौंपी गई थी। इसके अलावा मामले में ईडी ने भी दिलचस्पी दिखाई थी जिसमें मामले की पुलिस जांच रिपोर्ट, वीडियो-ऑडियो के रूप में मौजूद साक्ष्य और दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण भी कराया गया था। यह मामला सितंबर 2019 में इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह द्वारा पलासिया थाने में की गई शिकायत के बाद सामने आया। इसमें इंजीनियर ने कहा था कि कुछ महिलाएं उन्हें अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर तीन करोड़ रुपए मांग रही हैं।

● बृजेश साहू

मानव तस्करी की चार्जशीट से कई राज खुले

भोपाल जिलाकोर्ट में पेश की गई हनीट्रैप केस से जुड़ी मानव तस्करी की चार्जशीट से कई राज खुले हैं। जिस किशोरी को मानव तस्करी का शिकार बनाया गया, उसने आरोपी महिलाओं के मायाजाल की पूरी कहानी बयान कर दी है। किशोरी के अनुसार हनीट्रैप गैंग की आरोपी महिला श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, आरती दयाल और बरखा सोनी अपने ड्राइवर अभिषेक ठाकुर की मदद से सुनियोजित तरीके से मिडिल क्लास लड़कियों को महंगी लाइफ स्टाइल और आर्थिक मदद का झांसा देकर अपने जाल में फंसाती थी। गैंग की आरोपी महिलाओं का ड्राइवर अभिषेक ठाकुर मिडिल क्लास लड़कियों से संपर्क करता था, वह लड़कियों को एनजीओ में जॉब दिलाने का झांसा देता था। अभिषेक के झांसे में आने के बाद लड़कियों को गैंग की आरोपी महिला आरती दयाल से मिलाया जाता था और वह लड़कियों को उनकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देती थी। आरोपी आरती दयाल झांसे में आई लड़कियों को अयोध्या नगर स्थित अपने फ्लैट में रखती थी। इसी फ्लैट पर दूसरी महिला आरोपी श्वेता विजय जैन आती थी और लड़कियों को गैंग के वास्तविक काम के बारे में बताया जाता था और उन्हें समझाया जाता था कि यदि पैसे वाले हमारी या हम जैसी औरतों का दैहिक शोषण करते हैं तो उनको ब्लैकमेल कर उनसे पैसा लेना कोई गलत काम नहीं है। गैंग के झांसे में आई पीड़ित किशोरी जैसी कई लड़कियों के पहले अश्लील फोटो लिए जाते थे। इन फोटो को फिर बड़े लोगों को फंसाने के लिए भेजा जाता था।

सुगम होगी उर्वरक की उपलब्धता

हमारे देश के किसान हमेशा से अर्थव्यवस्था के मेरुदंड रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उर्वरक क्षेत्र में अभिनव उपायों के द्वारा इस मेरुदंड को मजबूती प्रदान करने की ओर अग्रसर है।

इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस क्षेत्र में कई संरचनात्मक बदलाव जरूरी हैं, क्योंकि देश में 45.6 प्रतिशत कार्यबल कृषि में कार्यरत है। किसान कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार महत्वपूर्ण पहल कर रही है, ताकि किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक और कृषि संबंधी अन्य सामग्री सस्ती दरों पर मिले, जिससे वे कृषि उत्पादन को बढ़ाने और अपनी आय में वृद्धि करने के लिए नई तकनीकों को अपनाएं। इन उद्देश्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रहे हैं। पहला है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) और दूसरा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसे वन नेशन, वन फर्टिलाइजर कहा जा रहा है। इसके तहत सभी प्रकार के प्रमुख उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड 'भारत' का उपयोग किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को एक छत के नीचे उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज और कीटनाशक जैसी सभी गुणवत्ता वाली कृषि सामग्री मुहैया कराएंगे। ये किसानों के लिए वन स्टाप शाप के रूप में कार्य करेंगे। इन केंद्रों में खरपतवारनाशक, कीटनाशक, बीज और छोटे कृषि उपकरण जैसे दरांती, स्प्रेयर आदि भी उपलब्ध होंगे। ये केंद्र तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन सहित छोटे-बड़े कृषि उपकरण किराए पर देंगे। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ-साथ नवीनतम एवं सर्वोत्तम कृषि प्रौद्योगिकी और प्रथाओं के बारे में किसानों को जानकारी देंगे।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र तीन स्तरों- ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर काम करेंगे। ग्राम स्तर पर ये किसानों को फसल से जुड़ी पाठ्यसामग्री देंगे, मृदा उर्वरता की जानकारी देंगे, सरकारी अधिकारियों के संदेश तथा भंडारण स्थिति के बारे में बताएंगे, सब्सिडी एवं अधिकतम खुदरा मूल्य आदि की सुविधा प्रदान करेंगे। तहसील स्तर के केंद्रों पर किसानों को नए दौर के उर्वरक एवं सरकारी योजनाओं के संबंध में हेल्पडेस्क, फसल संबंधी परामर्श, कामन सर्विस सेंटर, मृदा एवं कीटनाशक परीक्षण, बीज का नमूना संग्रह, स्प्रेयर, डस्टर एवं ड्रोन के लिए कस्टम हायरिंग की सुविधा मिलेगी तथा मंडी की कीमतों और मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। जिला स्तर के केंद्रों पर किसानों को संपूर्ण उत्पाद शृंखला की जानकारी मिलेगी। मृदा, बीज, जल एवं कीटनाशकों के लिए परीक्षण की सुविधा मिलेगी और खुदरा विक्रेताओं एवं कामन सर्विस सेंटर की क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर खुदरा विक्रेताओं को जानकारी के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक 6 महीने में प्रशिक्षित किया जाएगा। यहां कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विज्ञानी और कृषि विशेषज्ञ खुदरा विक्रेताओं को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए प्रोत्साहन देंगे, नए दौर के उर्वरक समाधान जैसे नैनो एवं जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल और फायदे से जुड़ी जानकारी देंगे तथा नियमित **तौर पर प्रशिक्षित** करेंगे। यहां प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियों को भी किसानों के साथ व्यापक तौर पर साझा किया जाएगा। साथ ही नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी, फसल कीट संक्रमण की चेतावनी और मंडी दर आदि की जानकारी भी दी जाएगी।

वहीं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक और क्रांतिकारी योजना है। अब देश में बेचे जाने वाले सभी प्रकार के प्रमुख उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी (पोटाश) और भारत एनपीके की बिक्री की जाएगी। वन नेशन-वन फर्टिलाइजर किसानों को ब्रांड विशिष्ट पसंद के भ्रम को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि एक खास तरह के उर्वरक के लिए विभिन्न ब्रांडों में कोई उत्पाद विषमता नहीं होती है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि किसी विशेष श्रेणी के उर्वरक में उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुसार समान पोषक तत्व होने चाहिए। उदाहरण के लिए डीएपी या यूरिया में समान मात्रा में पोषक तत्व होते हैं चाहे वह एक कंपनी द्वारा उत्पादित की गई हो या किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। किसान आमतौर पर इस तथ्य से अनजान होते हैं और उस क्षेत्र में कंपनियों द्वारा विकसित मजबूत विपणन रणनीतियों और मजबूत खुदरा विक्रेता नेटवर्क के परिणामस्वरूप कुछ ब्रांडों को पसंद करते हैं। वर्षों से इस ब्रांड वरीयता के परिणामस्वरूप किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति में देरी हो रही है और उर्वरकों की लंबी दूरी की आवाजाही के परिणामस्वरूप माल ढुलाई सब्सिडी में वृद्धि के कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

भारत ने एक अरब से अधिक आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उर्वरक, बीज, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि कृषि सामग्रियों की समय पर आपूर्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। पीएमकेएसके और वन नेशन-वन फर्टिलाइजर, दोनों पहल का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों एवं अन्य कृषि सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जो कि सतत कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के लिए आवश्यक है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

लाखों किसानों को होगा लाभ

हाल ही में मप्र सरकार की ओर से उन किसानों को राहत दी गई है, जिन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से ऋण ले रखा और उनका ऋण बकाया है। ऐसे किसान भी सहकारी समितियों से नकद में खाद व बीज खरीद सकेंगे। इससे राज्य के लाखों किसानों को फायदा होगा। बता दें कि मप्र में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने सहकारी समितियों से कर्ज ले रखा है पर वे इसके सदस्य नहीं है। पहले ये व्यवस्था थी कि सहकारी समितियों यानि पैक्स के सदस्य किसान ही सहकारी समिति से खाद-बीज खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

क्यों हार रहा रुपया...?

डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार कमजोर होना भारतीय जनमानस को आर्थिक रूप से कम, मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक परेशान करता है। जैसे ही रुपए के कमजोर होने की खबर आती है हमें लगता है कि हमारा रुपया नहीं, देश कमजोर हो रहा है। गत दिनों रुपया डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर 82.40 पर पहुंच गया। इस साल रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 10 प्रतिशत लुढ़क चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है और सरकार रुपए के कमजोर होने के लिए कई ऐसे कारण बता रही है जिस पर नियंत्रण करना केंद्र सरकार के बस का नहीं है। देश की मुद्रा के विनिमय मूल्य को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर और सरकार के प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। जनता को समझना पड़ेगा कि कई ऐसे कारण होते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है और उस कारण भी देश की मुद्रा टूटती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ठीक तीन माह पूर्व 18 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि रुपए की गिरावट के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की चढ़ती कीमतें और वैश्विक वित्तीय संकट दोषी है। वित्तमंत्री ने कहा था कि ब्रिटिश पांउड, जापानी येन और यूरो जैसी बड़ी मुद्राएं रुपए से ज्यादा टूटी हैं और भारतीय मुद्रा तो इन मुद्राओं के मुकाबले कुछ मजबूत ही हुई है। सीतारमण का कहना सही था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड 31 दिसंबर 2021 और 15 जुलाई 2022 के बीच 12.27 फीसदी और इसी अवधि में यूरो 11.3 फीसदी टूटा है। जबकि इनके मुकाबले रुपया छह फीसदी ही कमजोर हुआ है। पाउंड के मुकाबले तो रुपए में 10 फीसदी की मजबूती दर्ज हुई है। अपने आंकड़ों से वित्तमंत्री भले ही मोदी सरकार का बचाव कर रही हों, लेकिन इस बार मामला जरा ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है। डॉलर अब 83 रुपए की सीमा लांघ चुका है। इतना कभी नहीं टूटा। इसे सरल भाषा में ऐसे भी समझा जा सकता है, इस समय एक बैरल क्रूड ऑयल करीब 7500 रुपए (91 डॉलर) का पड़ रहा है। एक टन आयातित कोयला करीब 10 हजार से 18 हजार रुपए का हो गया है। जैसे-जैसे रुपया कमजोर होगा ऊर्जा जरूरत की इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाएगी जिसका असर प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई और अन्य ऊर्जा जरूरतों पर पड़ेगा।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहा है जिसके कारण डॉलर की मांग बढ़ रही है और दुनियाभर की मुद्रा कमजोर हो रही है जिसमें रुपया भी शामिल है। जाहिर है गिरते रुपए को लेकर मोदी सरकार चिंतित थी। रुपए की गिरावट थामने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार से रकम निकालकर रुपया खरीदा। फरवरी में रिजर्व बैंक ने इसके लिए 50 अरब डॉलर जितनी बड़ी रकम खर्च की, जिससे मुद्रा भंडार 630 अरब डॉलर से घटकर 580 अरब डॉलर पर आ गया। रिजर्व बैंक का कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक की कोशिश रुपए को नहीं विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की है। लेकिन केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक इससे भलीभांति परिचित है कि रुपए की गिरावट उद्योग जगत में खौफ और नागरिकों में डर पैदा करती है। कमजोर रुपया आयात की लागत बढ़ाकर उद्योगपतियों की कमर तोड़ता है और इसके कारण देश के नागरिकों पर महंगाई की मार पड़ती है।

भारत की थोक महंगाई में 60 फीसदी हिस्सा आयात का है। अगर रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर छोड़ता रहे तो रुपए की गिरावट रुक जाएगी लेकिन फिलहाल रिजर्व बैंक इससे बच रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक जानता है कि यह स्थायी इलाज नहीं है। रिजर्व बैंक इस बात को समझ रहा है कि 2018 तक भारतीय बाजारों से औसत एक अरब डॉलर हर माह निकलकर बाहर जा रहे थे, लेकिन इस साल जनवरी के बाद यह निकासी पांच अरब डॉलर हर माह हो गई है। कारण यह है कि विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में फिलहाल तेज बढ़त की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रिजर्व बैंक जानता है कि बाजार में डॉलर झोंककर भी इस निकासी को नहीं रोका जा सकता। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी जीडीपी का करीब 20 फीसदी है। अगर यह गिरकर 15 फीसदी यानी 450 अरब डॉलर तक चला गया तो बाजार में घबराहट का फैलना तय है। रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात यह भी है कि 2008 के वित्तीय संकट और 2013 में अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ने के दौर में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 फीसदी तक टूटा था। भारत सरकार ने फिलहाल डॉलर के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका में दिया गया यह बयान कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है इसी हताशा को दिखाता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

अमेरिकी डॉलर अब अद्वितीय

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई के बाद ग्लोबल मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर अब अद्वितीय है। अन्य करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत बताने वाला डॉलर इंडेक्स 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। अमेरिकी डॉलर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा 20 फीसदी है। अगर मुद्रा की ताकत के रूप में देखें तो दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडारों में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 2021 में करीब 60 फीसदी था। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत कायम है। इस कारण कहा जाता है कि डॉलर अमेरिका का सबसे मजबूत सैनिक है। वह कभी नहीं हारता। उलटे यह दूसरी करेंसी को बंधक बनाकर वापस अमेरिका के पास लौट आता है। भारत सरकार भले ही डॉलर की आड़ में छिपने की कोशिश कर रही हो लेकिन सरकार को इस बात का यकीन भी है कि मजबूत होता डॉलर और कमजोर होता रुपया आखिर में बेतहाशा मंहगाई लाएगा। इसलिए सरकार मंहगाई रोकने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। इसी के तहत खाद्य सामग्री पर जहां निर्यात पर दिसंबर तक रोक लगा दी है और खाद्यान्न के आयात पर आयात शुल्क में भी कमी कर दी है। ऐसे में इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार के प्रयासों के बाद रुपए का गिरना और मंहगाई का बढ़ना दोनों रुक जाए।

घट गई वन्य प्राणियों की आबादी

हर साल कटते हैं पुर्तगाल के बराबर जंगल

मार्क ने कहा कि हमारे जंगल बढ़ते तापमान और प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। जिस हिसाब से उनकी कटाई हो रही है। प्रदूषण की वजह से तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में अगर सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो धरती का तापमान तुरंत 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम हर साल पुर्तगाल के बराबर जंगल खो रहे हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। सूखा बढ़ता है। बाढ़ और मिट्टी के कम होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिसकी वजह से जंगली जीवों के साथ-साथ इंसान भी खतरे में आ जाता है। इंसान अपने खाने के लिए खेत बनाता है। उसके लिए जंगल काटता है। रहने के लिए शहर बनाता है। खाने का उत्पादन करने के लिए खेत जरूरी हैं। उनके लिए खुले मैदान। मैदान नहीं मिलने पर जंगल काट दिए जाते हैं। खाद्य उत्पादन की वजह से जमीन पर जैवविविधता में 70 फीसदी की कमी आई है। वहीं साफ पानी में यह कमी 50 फीसदी दर्ज की गई है। खेत-शहर बनाने के लिए साफ किए जंगलों की वजह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 30 फीसदी बढ़ गया है।

साल 1970 से लेकर अब तक दुनियाभर से दो-तिहाई वन्यजीव आबादी खत्म हो चुकी है। यानी 69 प्रतिशत जंगली जीव (जानवर और पेड़-पौधे) धरती और समुद्र दोनों से गायब हो चुके हैं। यह डरावनी रिपोर्ट दी है वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड ने। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े और दुखद बदलाव के पीछे तीन बड़े कारण हैं, पहला-जलवायु परिवर्तन, दूसरा जंगलों का खत्म होना और तीसरा प्रदूषण। मजेदार बात ये है कि इंसान हर मिनट 27 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगलों को साफ कर रहा है। उधर, समुद्र से आधे कोरल रीफ्स यानी मूंगे के पत्थर खत्म हो चुके हैं।

ऐसी स्थिति में जमीन और समुद्र दोनों से जीव खत्म तो होंगे ही। क्योंकि इंसानों ने मौसम बदल दिया। उनके रहने की जगह बर्बाद कर दी। शहर बना दिए। प्रदूषण इतना कर दिया कि कई जीव तो जहरीली हवा, दुर्गंध वाली जमीन और सड़ी हुई नदियों की वजह से मर गए। जानवरों और पेड़-पौधों की लाखों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। दिक्कत ये है कि इंसान अपने कपड़े, खाने, दवाओं के लिए इन जीवों का सर्वनाश करता जा रहा है। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में कंजरवेशन एंड पॉलिसी के डायरेक्टर एंड्र्यू टेरी ने कहा कि 69 फीसदी कमी आना बहुत खतरनाक गिरावट है। जंगली जीवों की आबादी में सबसे ज्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में देखा गया है। पिछले पांच दशकों में यहां के कुल जंगली जीवों की आबादी में 94 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। ब्राजील के अमेजन में मिलने वाली पिंक रिवर डॉल्फिन की आबादी 1994 से 2016 के बीच 65 फीसदी कम हो गई।

रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया है कि इस समय वैश्विक स्तर पर पृथ्वी दोहरे संकट से घिरी है। जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के पतन के एक-दूसरे से जुड़े संकट हमारी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हैं। इस रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि वर्ष 1970 से 2018 के बीच लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र में निरीक्षित वन्य जीव-जंतुओं की संख्या में औसतन 94 प्रतिशत की कमी आई है। दुनियाभर में आवास क्षेत्र के पतन और क्षति, उपयोग, आक्रामक जीव-जंतुओं की घुसपैठ, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और रोग वन्य जीव-जंतुओं की संख्या में आई इस गिरावट के मुख्य कारण हैं। इसी अवधि के दौरान इनमें से कई कारकों के चलते अफ्रीका के वन्य जीव-जंतुओं की संख्या में 66 और एशिया प्रशांत में कुल 55 प्रतिशत की कमी आई। जलीय जीव-जंतुओं की संख्या में आई 83 की कमी तो किसी भी प्रजाति वर्ग की संख्या में आई सर्वाधिक गिरावट है। एलपीआर में कछारी वनों की भूमिका का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जिनके संरक्षण व पुनर्स्थापन से जैवविविधता, जलवायु और लोगों के लिए एक अनुकूल समाधान मिल सकता है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद, कछारी वनों का मत्स्यपालन, कृषि और तटीय विकास के कारण 0.13 प्रतिशत की वार्षिक दर से पतन जारी है। आंधियों और तटीय कटाव जैसे प्राकृतिक दबावों के साथ-साथ अति उपयोग एवं प्रदूषण के कारण भी कई कछारी वनों की क्षति होती है।

इन कछारी वनों के पतन के चलते जैवविविधता के आवास क्षेत्र की क्षति होती है तथा तटवर्ती समुदायों को पारितंत्रीय सेवाएं नहीं मिल पातीं। कुछ क्षेत्रों में इससे उन भूभागों की क्षति हो सकती है, जहां तटवर्ती समुदाय रहते हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 1985 से सुंदरवन के कछारी वन के 137 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कटाव हुआ है, जिसके चलते वहां रहने वाले 10 मिलियन लोगों में से कई लोगों की भूमि और पारितंत्रीय सेवाओं में कमी आई है।

इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वभर में देशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों, शासन और संरक्षण के नेतृत्व को मान्यता और सम्मान दिए बिना प्रकृति अनुकूल भविष्य का निर्माण संभव नहीं है। संरक्षण व पुनर्स्थापन के कार्यों, विशेष रूप से खाद्य सामग्री के अधिक से अधिक स्थायी उत्पादन और उपयोग में वृद्धि और सभी क्षेत्रों को समय रहते यथासंभव कार्बन से मुक्त कर इन दो संकटों को कम किया जा सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के महासचिव रवि सिंह ने कहा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन व जैवविविधता की क्षति केवल पर्यावरण की समस्याएं नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, विकास, सुरक्षा और समाज की समस्याएं भी हैं। ऐसे में उनका समाधान भी एक साथ किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संसाधनों, कृषि, प्राकृतिक पारितंत्रों, स्वास्थ्य और आहार श्रृंखला पर पड़ेगा। हमें एक ऐसी सर्व-समावेशी सामूहिक कार्य-पद्धति की जरूरत है, जो सुनिश्चित करे कि मानवीय गतिविधियों की लागत एवं लाभ सामाजिक स्तर पर उचित हों और उनमें सभी की समान हिस्सेदारी हो।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

बुंदेलखंड का लौटेगा गौरव

5 वर्ष पहले तक रानी झांसी का बुंदेलखंड उपेक्षित था। यहां के लोगों ने पहले सपा और बसपा पर विश्वास व्यक्त किया था। इन पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिलने में बुंदेलखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन यहां के लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। चंद क्षेत्रों को विशिष्ट मानने वाली इन दलों की सरकारों ने बुंदेलखंड पर कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की समस्या ने बुंदेलखंड को बदहाल कर दिया। कृषि और पशुपालन दोनों में लोगों को नुकसान हुआ। लोग गांव में मवेशियों को छोड़कर पलायन कर गए। निवेश के अनुकूल माहौल नहीं था। डबल इंजन सरकार से पहले यहां की समस्याओं के समाधान के लिए कोई स्थाई योजना ही नहीं बनाई गई। तात्कालिक प्रयास अवश्य किए जाते रहे।

नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड पर ध्यान दिया। उन्होंने तात्कालिक राहत के साथ दीर्घकालिक कार्ययोजना भी बनाई। किंतु प्रारंभिक तीन वर्षों तक प्रदेश में सपा सरकार थी। इस कारण केंद्रीय योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हो सका। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू हुआ। इससे बुंदेलखंड अपनी बदहाली से बाहर निकलने लगा। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया है। उसके पहले डिफेंस कॉरिडोर निर्माण और उद्योगों की स्थापना कार्य का शुभारंभ किया गया था। पानी के लिए बेहाल रहने वाले बुंदेलखंड में हर घर नल से जल का सपना साकार हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले हमीरपुर के सुमेरपुर में हिंदुस्तान यूनीलीवर की नवनिर्मित इकाई स्प्रे ड्रायड डिटर्जेंट पाउडर संयंत्र एवं वितरण केंद्र का लोकार्पण किया था। यूनीलीवर जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने उप्र को अपनी अल्ट्रा-मॉडर्न फैक्टरी स्थापित करने के लिए चुना। उसके प्रमुख अधिकारी ने स्वीकार किया था कि योगी सरकार के प्रयासों से उप्र में निवेश का बेहतर माहौल कायम हुआ है। इसलिए उद्योग जगत के लोग यहां निवेश के लिए उत्सुक हैं। कंपनी अगले **तीन वर्ष के दौरान** सुमेरपुर में सात सौ करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। लोकार्पित इकाई एक अत्याधुनिक स्प्रे ड्राइड डिटर्जेंट फैक्टरी है। यहां लोकप्रिय लॉन्ड्री ब्रांड सर्फ एक्सेल सहित प्रमुख यूनीलीवर ब्रांड उत्पादों का निर्माण होगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस नई फैक्टरी में ऑटोमेटिक स्टोरेज भी है और यह एक वितरण केंद्र के रूप में भी काम करेगी।

योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बुंदेलखंड में ऊर्जावान प्रतिभाएं हैं और पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। कभी सूखे की मार और पेयजल के लिए तरस रहे इस क्षेत्र में आज बड़ा बदलाव आया है। यहां दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं। आजादी के अमृत वर्ष में हर घर नल का सपना भी पूरा होने जा रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से औद्योगिक विकास की नई राह बनी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे यहां के विकास को रफ्तार देने वाला होगा। राज्य सरकार इसके किनारे औद्योगिक क्लस्टर बना रही है। सुमेरपुर का यह प्लांट उसी कड़ी में एक कदम है। यह डबल इंजन सरकार का ही करिश्मा है कि देश-विदेश के निवेशक उप्र से जुड़ रहे हैं। यही निवेश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। रोजगार सृजन और सामुदायिक विकास का सहज माध्यम भी बनता है। सुमेरपुर जैसे पिछड़े कहे जाने वाले क्षेत्र में यह संयंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगा। बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की भी योगी आदित्यनाथ ने कार्ययोजना बनाई है। योगी सरकार ने उप्र में धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई हैं। इन स्थलों को विश्वस्तरीय प्रारूप में ढाला जा रहा है। अब तो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

बुंदेलखंड ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में अनेक प्राचीन दुर्ग और किले हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले झांसी के आठ, बांदा के चार, जालौन के दो, ललितपुर के सात, हमीरपुर के तीन, महोबा के पांच और चित्रकूट के दो किलों के पुरातात्विक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से परिचय कराती कॉफी टेबल बुक भी तैयार कराई जा रही है। इन किलों के साथ ही ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में अहम ऐलान किया है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर के पर्यटन विकास की कार्ययोजना पर अमल शुरू हो चुका है। संभव है विशाल परिसर वाले कई किलों में बेहतरीन होटल स्थापित किए जाएं। कालिंजर का किला साढ़े पांच सौ हैक्टेयर के विशाल भू-भाग में फैला है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पुनरोद्धार के लिए ठोस प्रयास

सरकार की कोशिश है कि झांसी से बरुआ सागर किले तक जाने के लिए सुगम साधन उपलब्ध कराया जाए। देखरेख के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो रहे बारह एकड़ परिसर वाले टहरौली किला और चार एकड़ परिसर वाली दिगारा की गढ़ी, चिरगांव किला, लोहागढ़ का किला, चम्पत राय महल, रघुनाथ राव महल को पुराना वैभव प्रदान किया जाएगा। इनके पुनरोद्धार के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। कुछ जगह हेरिटेज होटल विकसित किए जाएंगे। बरुआ सागर के समीप तालबेहट किले के नीचे स्थित झीलों पर वॉटर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। मड़ावरा के किले और सौराई के किले पर पर्यटन की दृष्टि से पहुंच मार्ग, साइनेज तथा पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। देवगढ़ दुर्ग परकोटे के नीचे बेतवा नदी में वॉटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। महावीर स्वामी अभयारण्य तथा बानपुर किले को इको-टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। आने वाले दिनों में चरखारी का मंगलगढ़ किला भी पर्यटकों को लुभाता नजर आएगा। मस्तानी महल और बेलाताल पर कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध होगी।

मंदी की आहट

भारत झेल चुका है मंदी

आजादी के बाद सन् 1991 में भारत ने सबसे बड़ी मंदी का सामना किया था। देखा जाए, तो भारत में दो बार मंदी आई है। पहली बार सन् 1991 में और उसके बाद सन् 2008 में। सन् 1991 में आई भयंकर मंदी के समय तो भारत की आर्थिक हालत यह थी कि हमारे पास महज इतनी ही विदेशी मुद्रा बची थी कि सिर्फ तीन हफ्ते के आयात खर्चे पूरे किए जा सकते थे। उस समय भारत कर्ज की किश्तें चुकाने में असमर्थ हो गया था और देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब देश में चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसके बाद दूसरी बार सन् 2008 में बड़ी मंदी का सामना देश ने किया, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस मंदी का कारण हालांकि वैश्विक था और आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि एक जाने-माने अर्थशास्त्री के सत्ता में होने के कारण देश ने इसका बेहतर तरीके से सामना किया था।

दुनिया में एक बार फिर मंदी की आहट दस्तक देती दिखाई दे रही है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब केंद्र सरकार पांच ट्रिलियन इकॉनोमी की तरफ बढ़ने का दावा कर रही है। यदि मंदी आती है, तो निश्चित ही मोदी सरकार के लिए यह बड़ी अग्निपरीक्षा होगी, भले इसके कारण भी सन् 2008 की मंदी की तरह वैश्विक हों। हाल में आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान आरबीआई के 7.5 फीसदी से घटाकर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 फीसदी कर दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दो साल के मुश्किल कोरोनाकाल के नुकसानों से बाहर नहीं निकल पाई है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि शायद भारत को अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले कम संकट का सामना करना पड़े।

वैसे तो दुनियाभर के आर्थिक विशेषज्ञों की मानें, तो आने वाली इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, ब्रिटेन पर होगा और यूरोप पर इस मंदी की गहरी मार पड़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुमान चीन के लिए भी बेहतर नहीं हैं। उनका यह जरूर कहना है कि भारत पर इसका शायद ज्यादा असर न पड़े। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी एक रिपोर्ट में हाल में कहा था कि दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। अर्थव्यवस्था में वैश्विक गिरावट से उपजी मंदी की मार भारत पर कम ही पड़ेगी। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय बाजारों में कोरोनाकाल के दौरान से पहले जैसी तेजी नहीं आ सकी है। वैसे इसके बावजूद देश चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में बेहतर दिख रहा है। साल 2023 में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि भारत की अनुमानित वृद्धि दर 6.1 फीसदी बताई गई है। आईएमएफ के अलावा हाल में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की भी एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि साल 2023 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना करेंगी। रिपोर्ट में टेक कंपनियों के पिछले 5-6 महीने खराब बीतने का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अमेरिकी शेयर बाजार पर गिरावट का दौर है। अमेरिकी टेक कंपनियां गूगल, एप्पल, टेस्ला पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, जबकि दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है।

खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका मंदी का सामना कर सकता है। जाहिर है इसका असर दुनियाभर में पड़ेगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उसने इस संभावित संकट से उबरने की तैयारी की है, जिससे उसके पास इसका मुकाबला करने की क्षमता है। अमेरिका, यूरोप के अलावा चीन का भी आर्थिक मंदी में जाना तय माना जा रहा है। कारण यह भी है कि शून्य कोरोना नीति के चलते चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है। आज भी हालत यह है कि वहां कोरोना का एक भी मामला सामने आ जाए, तो वहां सख्त पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इससे कारोबार ठप पड़ जाते हैं और उद्योग को भी बड़ा धक्का लगता है।

इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर डाला है। दरअसल कोरोना महामारी के भयंकर दो साल के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी दुनिया की आर्थिकी पर विपरीत असर डाला है। वैश्विक निर्यात शृंखला (ग्लोबल सप्लाई चेन) की कमर टूट गई है और कच्चे तेल के भाव अचानक आसमान छूने लगे हैं। इससे दुनियाभर में आवश्यक चीजों का संकट होने से उनके दाम बढ़े हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि रूस और यूक्रेन, दोनों ही गेहूं-जौ जैसे अनाजों के बड़े निर्यातक हैं।

भारत ही नहीं दुनिया के कई देश आज की तारीख में महंगाई से परेशान हैं। ब्रिटेन में तो महंगाई पिछले 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। अमेरिका भी महंगाई पर काबू के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत में हाल में रेपो रेट में लगातार वृद्धि की गई, जिसका मकसद महंगाई पर काबू पाना है, क्योंकि देश में खुदरा महंगाई दर आठ फीसदी से ऊपर है। हाल में स्टिजरलैंड बेस्ड ग्लोबल इंवेस्टमेंट बैंक और दुनिया की टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्रेडिट सुइस जैसी दिग्गज कंपनी का शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया, जिसके बाद आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे भविष्य में वैश्विक मंदी का बड़ा संकेत बताया। इस कंपनी के शेयर 10 अक्टूबर को 10 फीसदी नीचे गिर गए। माना जाता है कि बढ़ती महंगाई के कारण कंपनी खराब वित्तीय स्थिति में फंसी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल भर पहले ही क्रेडिट सुइस का मार्केट कैप 22.3 बिलियन डॉलर था, जो अब घटकर 10.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो इसके शेयरों में 56 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि क्रेडिट सुइस जैसी ग्लोबल कंपनी को ऐसी स्थिति झेलनी पड़ रही है, तो यह ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के ध्वस्त होने के संकेत हैं।

आर्थिक मंदी की सबसे पहली मार जीडीपी के आकार पर पड़ती है और दैनिक उपयोग की चीजें महंगी हो जाती हैं। खर्च बढ़ जाता है और आय गिरने लगती है। इसका असर जनता के खरीदारी की क्षमता पर पड़ता है। इसके अलावा कंपनियां पैसा बचने के लिए कर्मचारियों की छंटनी (ले ऑफ) शुरू कर देती हैं। इसका असर यह होता है कि बेरोजगारी की लाइन और लंबी हो जाती है। हाल के कोरोनाकाल में यह दिखा था। छोटे व्यवसाय (एमएसएमई) ठप पड़ जाते हैं। कच्चा माल भी महंगा हो जाता है और शेयर बाजार में लगा पैसा लोग निकालने लगते हैं।

● **अरविंद नारद**

एक्शन में मामा सकते में अफसरान

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में कुछ अलग अंदाज से सरकार चला रहे हैं। चौथी पारी शुरू करते ही वे एंग्री यंगमैन की भूमिका में आ गए। कभी वे मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कभी अफसरों को डांट फटकार रहे हैं। ये उनकी नई पहचान बन गई! सौम्य, सहज और मिलनसार स्वभाव वाले शिवराज का ये नया चेहरा समझ से परे है। इस बार एक्शन वाले रोल में हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि सरकार बदली-बदली सी नजर आ रही है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र को सुशासित राज्य बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस समय पूरी तरह एक्शन में हैं। मामा के एक्शन को देखकर अफसरान सकते में हैं। वजह यह है कि अफसरों की तनिक भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। पहले छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देने वाले मुख्यमंत्री अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। अफसरों को गलती की सजा तत्काल मिल रही है। इसलिए मंत्रालय से लेकर **मैदानी स्तर** तक अफसर पूरी तरह सजग और सतर्क हैं। मुख्यमंत्री का सिर्फ मूड ही नहीं बदला, उनके व्यवहार में भी बदलाव नजर आ गया। कुछ महीने के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही, अफसरों के प्रति उनकी सख्ती! भाषा में भी और कार्रवाई में भी। वे अब लापरवाहियों को अनदेखा नहीं कर रहे, बल्कि उसके जिम्मेदारों को सामने लाने की कोशिश में है। जिस तरह शिवराज सिंह समस्याओं को इंगित कर रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि अफसर घोर लापरवाही कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी पारी अलग अंदाज से शुरू की। कोरोना संक्रमण के बीच उन्होंने जनता के बीच उपस्थित होकर अपनी लोकप्रियता को सातवें आसमान पर पहुंचाया। वहीं माफिया, अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही भ्रष्ट-कामचोर अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाया जा रहा है। जनता के काम में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री का यह रॉबिनहुड वाला अंदाज जनता को खूब भा रहा है। कभी वे देर रात तक अफसरों से मीटिंग करते हैं, तो कभी अलसुबह उठकर अधिकारियों की क्लास लेते दिखाई देते हैं। सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और अफसरों की खिंचाई करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एंग्री यंगमैन की भूमिका में आ गए हैं। कभी वे मंत्रियों से सवाल-जवाब कर रहे हैं, तो कभी अफसरों को डांट फटकार रहे हैं। ये उनकी नई पहचान बन गई है। सौम्य, सहज और मिलनसार स्वभाव वाले शिवराज का ये नया चेहरा समझ से परे है। इस बार वे एक्शन वाले रोल में हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि सरकार बदली-बदली सी नजर आ रही है। सत्ता के गलियारों में यही चर्चा है, कि 'साहेब' कड़क हो गए हैं। उनके ऐसे मिजाज से सब हैरान भी हैं। आखिर वे क्यों बदलते जा रहे हैं, फिलहाल ये यक्ष प्रश्न है?

दोषी तत्काल होंगे दंडित

अपनी तीन पारियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी-कभार एक्शन मोड में नजर आते थे। लेकिन चौथी पारी में वे शुरू से एक्शन मोड में हैं। मंत्री, विधायक, अधिकारी हो या फिर कर्मचारी वे सबको ताने हुए हैं। अफसरों को फ्री हैंड देने के साथ ही उन पर लगातार लगाम कसी जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोषियों को तत्काल दंडित किया जा रहा है। गत दिनों मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और विधायकों से वर्चुअल संवाद किया और उनसे स्पष्ट कह दिया कि भ्रष्टाचार के प्रति राज्य शासन की **जीरो टॉलरेंस** की नीति है। भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। जहां गड़बड़ होगी वहां दोषियों को तत्काल दंडित किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग में 104 लोगों पर कार्रवाई की गई है और 26 को नौकरी से बाहर किया गया है। जनता को राहत देने के लिए स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। मैदानी पोस्टिंग में कर्मठ और संवेदनशील अधिकारी-कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों को सुशासन का पाठ पढ़ाकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है।

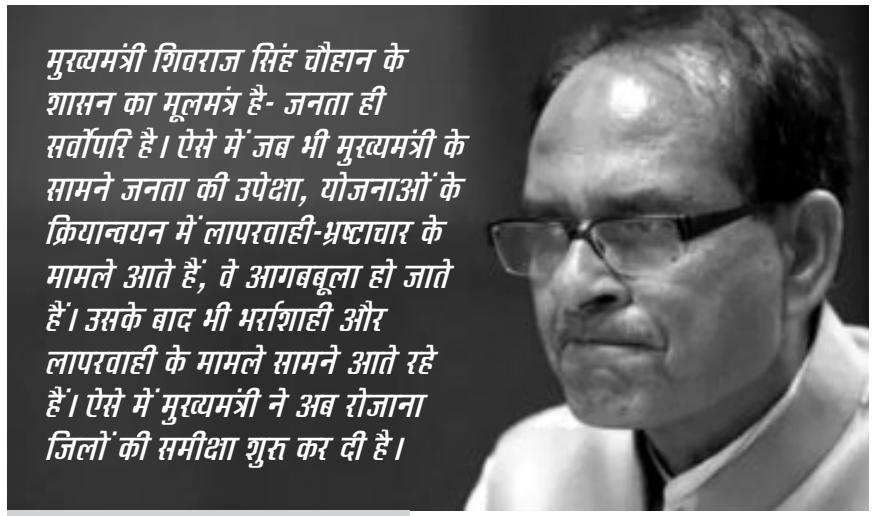

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन का मूलमंत्र है- जनता ही सर्वोपरि है। ऐसे में जब भी मुख्यमंत्री के सामने जनता की उपेक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही-भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, वे आगबबूला हो जाते हैं। उसके बाद भी मनमानी और लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब रोजाना जिलों की समीक्षा शुरु कर दी है।

आखिर क्यों सख्त हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ महीनों से अलग मूड में नजर आ रहे हैं। कभी वे देर रात तक अफसरों से मीटिंग करते हैं, तो अलसुबह उठकर अधिकारियों की क्लास लेते दिखाई देते हैं। सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और अफसरों को खिंचाई करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। सिर्फ उनका मूड ही नहीं बदला, उनके व्यवहार में भी बदलाव नजर आ गया। कुछ महीने के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही, अफसरों के प्रति उनकी सख्ती! भाषा में भी और कार्रवाई में भी। वे अब लापरवाहियों को अनदेखी नहीं कर रहे, बल्कि उसके जिम्मेदारों को सामने लाने की कोशिश में हैं। लेकिन, इसका कारण खोजने की कोशिश नहीं हो रही! जबकि, जिस तरह शिवराज सिंह समस्याओं को इंगित कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि अफसर घोर लापरवाही कर रहे हैं! शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एंग्री यंगमैन की भूमिका में आ रहे हैं। कभी वे मंत्रियों से सवाल जवाब रहे हैं, तो कभी अफसरों को डांट फटकार रहे हैं। ये उनकी नई पहचान बन गई! सौम्य, सहज और मिलनसार स्वभाव वाले शिवराज का ये नया चेहरा समझ से परे है। इस बार एक्शन वाले रोल में हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि सरकार बदली-बदली सी नजर आ रही है। सत्ता के गलियारों में यही चर्चा है, कि 'साहेब' कड़क हो गए। उनके ऐसे मिजाज से सब हैरान भी हैं। आखिर वे क्यों बदलते जा रहे हैं, फिलहाल ये यक्ष प्रश्न है?

दरअसल, प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का बयान देकर सजग किया कि वे समय से पहले चेत जाएं, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। पहले मुख्यमंत्री जहां सिर्फ अधिकारियों को हिदायत देते थे, अब मंत्रियों और विधायकों को हिदायत देने में देर नहीं कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर शिवराज ने एक मंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी अपने मंत्रियों को लेकर ऐसा ही किया था। अब मुख्यमंत्री भी उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को दलालों से दूर रहने को कहा और सबको जनसेवा के नए-नए आईडियों पर काम करने की नसीहत दी। शिवराज ने यह भी कहा था कि वे जब भोपाल में रहेंगे, तो रोज किसी न किसी मंत्री के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, उन्होंने यह किया भी और इसके नतीजे भी सामने आए। शिवराज सिंह के बदले हुए व्यवहार के कारण क्या हैं, इसे लेकर अलग-अलग कारण गिनाए जा रहे हैं। एक साल बाद विधानसभा चुनाव होना है और शिवराज सिंह नहीं चाहते कि उनकी सरकार की कोई भी खामी जनता की नाराजगी का कारण बने और उससे चुनाव नतीजे प्रभावित हों! वे अपनी इमेज जनता के मुख्यमंत्री के रूप में बनाना चाहते हैं, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी और उप्र में योगी आदित्यनाथ की बनी है। भाजपा शासित राज्यों की सरकारें भी बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रही हैं। शिवराज सिंह भी पीछे नहीं रहना चाहते, जिसके चलते उन्होंने अपनी **विनम्र छवि** को त्याग दिया। कुछ हद तक वे खुद को हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसी उप्र में योगी की है।

सुबह फटकार, शाम को विदाई

18 सालों में मात्र सवा साल वे सत्ता से दूर रहे, लेकिन कभी किसी ने उन्हें ऐसे मूड में नहीं देखा। इस वजह से सबको लग रहा है कि कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा है। शिवराज खुद भी बार-बार कह रहे हैं कि वे खतरनाक मूड में हैं। एक मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा था 'सुन लो माफिया, मप्र छोड़ दो,

नहीं तो जमीन में दस फीट गाड़ देंगे!' उनका यह भाषण भी खूब वायरल हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है कि शिवराज चौहान के सिर्फ वचन ही नहीं बदले, उनकी छवि भी बदलाव के रास्ते पर है। ये स्थिति आज या कल की नहीं है! सालभर से धीरे-धीरे उनमें बदलाव आ रहा है। पिछले साल उनका एक **वीडियो** खूब चर्चित हुआ था। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बीच में ही ग्वालियर नगर निगम के आईएएस कमिश्नर को फटकारा और कहा 'बहुत हो गया, अब इनकी छुट्टी कर दीजिए!' शाम होते-होते 2010 बैच के आईएएस संदीप माकिन को हटा दिया गया था। कुछ ऐसा ही अंदाज झाबुआ कलेक्टर और एसपी को हटाने के समय भी दिखाई दिया था। इसके बाद मंच से भी कार्रवाई होती दिखाई दी। लेकिन, इंदौर के एडीएम पवन जैन को लेकर उनका रवैया अभी तक सबसे ज्यादा सख्त दिखाई दिया। एक विकलांग के साथ जनसुनवाई में बदसलूकी करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से इंदौर से हटा दिया गया। दरअसल, ये संकेत है कि यदि अफसरों ने अपनी शैली नहीं सुधारी तो नतीजा क्या होगा!

हाल ही में भोपाल की सड़कों को लेकर उन्होंने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अफसरों की नकेल कस दी। उन्होंने पूछ भी लिया कि इसका जिम्मेदार कौन है, उसे सामने लाया जाए! मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की सड़कों की स्थिति पर भी नाखुशी जाहिर की। दरअसल, मुख्यमंत्री को इस स्थिति तक लाने के लिए वो हालात जिम्मेदार हैं, जो अफसरों ने पैदा किए हैं। जिस तरह की सख्ती शिवराज सिंह इन दिनों दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि वे अफसरों की लापरवाहियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। काफी हद तक ये सही भी है। यदि मुख्यमंत्री को राजधानी की सड़कों को लेकर बोलना पड़े, तो ये सही भी नहीं है। जनता की शिकायत पर मंच से अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश देना उन्हें फटकार लगाना, ये किसी मुख्यमंत्री के लिए आसान हालात नहीं है।

शिवराज की भ्रष्टों पर पैनी नजर

मुख्यमंत्री का एक्शन कई अफसरों पर भारी पड़ने लगा है। इसकी वजह यह है कि शिवराज योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर पैनी नजर रखने के साथ उन पर कार्रवाई करने से भी नहीं चूक रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों से सुबह साढ़े छह बजे ही बजे अफसरों की क्लास लेना शुरू कर दिया है। वे हर रोज दो जिलों के सरकारी अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हैं और उन्हें सख्त हिदायत तो देते ही हैं। साथ में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर जमीनी स्तर पर योजनाओं की जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री आवास से हर जिले में योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया जा रहा है और इस दौरान कई ऐसी जानकारियां उनके पास आ रही हैं जो आसानी से सुलभ नहीं होती, क्योंकि अधिकारी गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने अपना एक अलग से खुफिया तंत्र विकसित कर लिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक जिले के कलेक्टर से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उस इलाके के भ्रष्ट अफसरों की सूची तक उन तक पहुंचा दी और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ज्यादातर शिकायतें आवास निर्माण से लेकर राशन वितरण और पानी व बिजली से जुड़ी आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित करें और भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई भी करें।

शिवराज सिंह खुद भी कई बार अफसरों को हिदायत दे चुके हैं कि आजकल अपन अलग मूड में हैं। अभी तक मुख्यमंत्री की छवि विनम्र शासक की रही। वे बच्चों के लिए मामाजी के नाम से लोकप्रिय हैं और उनके पास आने वाली हर शिकायत पर निर्देश देने में देर नहीं करते! लेकिन, अफसरों के प्रति उनके बयानों से उनके तेवर अलग ही लग रहे हैं। उनकी मॉर्निंग मीटिंग भी सामान्य नहीं होती। वे जिस जिले की समीक्षा करते हैं, पहले वहां की सारी चीरफाड़ कर चुके होते हैं। यही कारण है, कि इन वर्चुअल मीटिंग में कोई अफसर बच नहीं पाता और न झूठ बोलने की हिम्मत कर पाता है। कुछ दिनों पहले पन्ना जिले की समीक्षा में जब कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा अपने जिले की सही जानकारी नहीं दे पाए, तो शिवराज सिंह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि पन्ना कलेक्टर ये बताएं कि अगर 4 महीने तक जियो टैगिंग चलती रहेगी, तो कैसे काम चलेगा। आपके पास या तो जानकारी नहीं है या आप बता नहीं पा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है।

कई जिलों की समीक्षा के दौरान वे सरकारी योजनाओं की धीमी प्रगति से नाखुश हुए। उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन, बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी और धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त की। लेकिन, उनकी इस सख्ती से जनता खुश है। उसे अब लग रहा है कि कोई तो है, जो उनकी बात सुन और समझ रहा है। फिर इसके पीछे कारण कुछ भी हो, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का असर दिखाई दे रहा है! आने वाले दिनों में अफसरों पर और ज्यादा सख्ती दिखाई दे, तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए!

बेईमानों को भेजो जेल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हितग्राहियों को योजना का लाभ वितरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ आम जनता से धोखाधड़ी करने वाले और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी गाज गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तत्काल एक्शन लेते हुए हनुमना में पदस्थ बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर

दिया है। साथ ही उनके कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के अन्य सरकारी स्कीमों की योजना व समीक्षा भी की है। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम करने पर मुख्यमंत्री ने रीवा के सुशासन की तारीफ की है। बता दें कि रीवा 16 महीने से नंबर वन पर बरकरार है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन सबको मेरा बधाई संदेश दिया जाए। वहीं अनुचित राशि आदि मांग ली और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने पर 14 जीआरएफ को पद से हटाया गया। साथ ही कुछ सचिवों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने स्पष्ट किया है कि जनता के लिए जनहितैषी कार्यों पर अतिरिक्त राशि और अनुचित राशि की मांग करने वाले पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन पर एफआईआर कर उन्हें जेल भेजा जाए। मप्र में भ्रष्टाचार और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। रीवा के सुशासन की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि जिले में मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। जिसके लिए रीवा जिला प्रशंसा के योग्य है। इसके अलावा शहरी रीवा नगर निगम के लिए 4300 आवास स्वीकृत किए गए। जिसमें से 800 मकान अभी भी अपूर्ण हैं, इसे तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन पर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब तक जो जानकारी सामने आई है। उसमें कम घरेलू परिवारों को कनेक्शन का लाभ दिया गया है। काम की गति को बढ़ाया जाए, 809 गांव में योजना संचालित है। काम की गुणवत्ता को ठीक किया जाए। जिसमें गांव में योजना लागू है, उस पर निगरानी रखें। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रकरण तैयार किए जाए। अवैध शराब को जब्त किया जाए। प्रदेश में चल रहे हुक्का लाउंज को बंद करने की कवायद भी जारी है। जन सेवा योजना का लाभ दिया जाए। जिस पर जानकारी देते हुए कहा गया कि रीवा में जनसेवा के कुल 2,00,000 आवेदन आए थे। जिनमें 1,93,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

बैठक में ही मंगवाई माफी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गत दिनों पहले उन्होंने एक सभा में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम तेजी से करने के आदेश दिए थे, वहीं मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी को उसकी लापरवाही पर बैठक में ही माफी मंगवाई, क्योंकि अधिकारी ने अपने काम का लक्ष्य पूरा नहीं किया था। मुख्यमंत्री शिवराज जल जीवन मिशन पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी यह वाकया देखने को मिला। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की, इस बैठक में ईई द्वारा गलत तथ्य पेश करने पर मुख्यमंत्री ने बैठक में ही ईई को फटकार लगा दी। उन्होंने बैठक में ही ईई को अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए कहा। जिसके बाद ईई ने बैठक में अपनी गलती पर माफी मांगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि कितने प्रतिशत लक्षित परिवारों तक नल से जल पहुंचने का कार्य हुआ। इसके बारे में पूरी जानकारी दें, जिस पर बताया गया कि लक्ष्य 1.29 लाख का था, जो पिछली बार 102 प्रतिशत पूरा हुआ था। लेकिन इस बार लक्ष्य 9435 का है, जिसमें से अब तक केवल 4 हजार ही लक्ष्य पूरा हुआ है। जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने काम की गुणवत्ता की शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली, जिस पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि 2 जगह पर शिकायतें आईं थी, इन मामलों में दोनों ठेकेदारों को नोटिस दिया है, जबकि एक जगह पेमेंट रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि कितनी योजनाओं से पानी देना शुरू हुआ है? जिस पर ईई ने बताया कि 77 योजनाओं के तहत पानी देना शुरू हुआ। जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी जगह योजनाएं दुरुस्त कराई जाएं। इसको रीचेक कराइए, ग्रामीणों की संतुष्टि का स्तर नहीं बढ़ा तो क्या फायदा। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आप लोग सभी काम बिना लापरवाही और तय समय सीमा में पूरा करें।

भ्रष्टाचार की खबरों पर तुरंत बत्ती जले

मप्र के अफसरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की खबरों पर तुरंत बत्ती जले और तुरंत एक्शन लें, वरना मैं एक्शन ले लूंगा। कोई भी चीज अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातों की मार्केटिंग भी करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब जमाना बदल गया है। हर चीज जनता के बीच जाना चाहिए। विभाग के अफसर गंभीरता से लीजिए। सभी सुन लें। यदि आपके विभाग की खबर छपी है तो तुरंत एक्शन लीजिए। यदि गलत हो रहा तो एक्शन लें, वरना मैं एक्शन ले लूंगा। कोई भी चीज अनदेखी नहीं करें। मुख्यमंत्री ने भोपाल नगर निगम में 500 रुपए लेने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार की कोई खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों से यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। जिले में अच्छे काम हो रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि उन्हें जनता को बताएं। इससे अच्छा मैसेज जाएगा। पिछले दिनों पुलिस ने बेहतर काम करते हुए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। कहीं गड़बड़ है तो एक्शन लें, नहीं है तो खंडन करें। मुख्यमंत्री कोई ट्वीट कर दें, सोशल मीडिया पर कोई बात कह दें तो जिले से भी ट्वीट हो। सोशल मीडिया से दूर न रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास गतिविधियों के संबंध में मंत्री और विधायकों से निवास कार्यालय से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति महारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जनता को राहत देने के लिए स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। गड़बड़ करने वाले दोषियों को तत्काल दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग में हमने 104 लोगों पर कार्रवाई की और 26 को नौकरी से बाहर किया गया है। मैदानी पोस्टिंग में कर्मठ व संवेदनशील अधिकारियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

24 घंटे में कलेक्टर-एसपी बदले

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक्शन मोड में नजर आ रहे है। झाबुआ के गालीबाज एसपी अरविंद तिवारी को हटाने के बाद उन्होंने कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी हटा दिया। 24 घंटे के भीतर झाबुआ जिले के दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इंदौर संभाग की राजस्व अपर आयुक्त रजनी सिंह को कलेक्टर की कमान सौंपी गई है। मप्र के प्रशासनिक गलियारों में पिछले दो दिनों में भूचाल सा आ गया है। इसकी वजह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड है। शुरुआत मालवा अंचल के झाबुआ जिले से हुई। गत दिनों मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटा दिया। उनकी जगह इंदौर संभाग में अपर आयुक्त राजस्व के तौर पर नियुक्त रजनी सिंह को झाबुआ कलेक्टर बना दिया गया। इससे एक दिन पहले जिले के एसपी अरविंद तिवारी को पहले हटाने के आदेश दिए फिर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। एसपी ने एक छात्र को गाली दी थी। जिसका ऑडियो मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। परीक्षण कराने पर ऑडियो में अरविंद तिवारी की ही आवाज पाई गई। बताया जाता है कि ऑडियो में एक छात्र सुरक्षा की मांग कर रहा था। जिस पर एसपी गाली देने के साथ उससे अभद्र भाषा में बोल रहे थे।

बताया जा रहा है कि गत दिनों मुख्यमंत्री झाबुआ जिले के दौरे पर रहे। आदिवासी इस जिले में आम जनता से जुड़ी कई शिकायतें हुई। इसके साथ ही कई दिनों से जिले के विभिन्न विभागों के लचर रवैये की वजह से सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। मुख्यमंत्री के झाबुआ प्रवास के दौरान शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित कई हितग्राहियों ने भी कलेक्टर की शिकायत की। अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाए थे। पिछले तीन महीनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही

विभिन्न जिलों की समीक्षा करते देखे गए हैं। जिसमें जहां कमियां नजर आ रही थी, उसके बारे में संबंधित विभाग के अफसरों को भी चेतावनी दी जाती रही थी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के दर्जनभर से ज्यादा जिले के कई अफसर, मुख्यमंत्री के निशाने पर हैं। सरकारी योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन ना होना और जनता से जुड़ी लंबित शिकायतें प्रमुख हैं। दरअसल पिछले एक महीने में सरकारी अफसरों की हद दर्जे की लापरवाही के कई बड़े मामले सामने आए हैं। जिसमें हाल ही में पोषण आहार वितरण योजना से संबंधित अकाउंटेंट जनरल की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी रही। इसके बाद जबलपुर जिले में करोड़ों रुपए के यूरिया परिवहन में सामने आई गड़बड़ी से प्रदेश सरकार अभी तक विपक्ष के आरोपों से घिरी है। जानकर बताते हैं कि ऐसे ही कई बड़े मामलों के बाद मुख्यमंत्री ने अब तय कर लिया है कि सरकारी महकमों में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार हमारे हिसाब से चलेगी

सरकार के ढाई साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, जिसे दिक्कत हो बता दे। बदलने में देर नहीं लगेगी। साथ ही, सभी मंत्रियों को भी वीकली एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गत दिनों मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और आला अफसरों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कोविड की 500 से ज्यादा बैठकें कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प लें, जो भी सुधार की जरूरत है, उसे करें। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, एसपी व अन्य अफसरों को साफ शब्दों में कहा कि मैंने जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन करें। शिवराज ने कहा कि मैं भी परिश्रम की पराकाष्ठा करता हूं, आप भी प्रदेश को बेहतर बनाने में कसर नहीं छोड़ें।

मुख्यमंत्री ने चार तरह के एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। वीकली एक्शन प्लान में बताना होगा कि वह किस सप्ताह में क्या करेंगे। इसके अलावा मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी तैयार करने कहा है। यह प्लान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में डालेंगे, ताकि गुणवत्ता पूर्ण और समय पर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवनी, शहडोल, रतलाम, रायसेन में प्रभावी कार्रवाई की है। महिला अपराध, बेटियों से जुड़े अपराधों के मामले हमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है।

मुख्यमंत्री शिवराज बोले- जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में

गुना में पुलिसकर्मियों के बलिदाल की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में नजर आए थे। उन्होंने अपने आवास पर प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। जिसमें कलेक्टर-आयुक्त, पुलिस अधीक्षक-पुलिस महानिरीक्षक जुड़े। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिसमें दम हो वही फील्ड में रहे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। कलेक्टर और आयुक्त को इसमें पुलिस का साथ देना है। शिकार कोई एक दिन नहीं होता, शिकारी-गोकशी करने वालों, जुआ-सट्टा चलाने वालों, ड्रग्स का धंधा करने वालों और अवैध शराब बेचने वालों को बर्बाद कर दें। सीईओ जिला पंचायत विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जन कल्याण के कार्यों और योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा- एक बार फील्ड के अधिकारियों से बात कर लें, जो फील्ड में कुछ करके दिखा सके, वही रहेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस चाहिए। एक्शन में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि अपराध हो ही नहीं। बैठक में मुख्यमंत्री के तेवर तीखे नजर आए। वह बोले सुबह 7 बजे बैठक बुलाने का मकसद यह है कि आप 10 बजे से काम में लग जाएं। यह बैठक जनता की जिंदगी में नई सुबह की तरह हों। उन्होंने कहा- कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूं। पुलिस का काम जनता के लिए शांति स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण की जल्द ही फिर से समीक्षा की जाएगी। वहीं अधिकारियों को स्वस्थ रहने के लिए योग, ध्यान, वाक करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि आपका अधिकारी और मेरा मुख्यमंत्री होना तभी सार्थक है जब जनता के कल्याण के काम हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईओ जिला पंचायत अमृत सरोवर, आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण आवास सहित जल संरचनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली चोरों पर कड़ी कार्रवाई करें।

मालामाल होंगे किसान!

छत्तीसगढ़ में धान की फसल उगाने वाले किसानों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साल नए किसानों ने खरीफ सीजन में धान की फसल बेचने के लिए पंजीयन करवाया है। इससे एक बात तो साफ की छत्तीसगढ़ में किसानों की धान की खेती करने में रूचि लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों को देशभर में सबसे ज्यादा धान पर एमएसपी मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी के बाद किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए खेती से दूर हो चुके किसान भी अब खेती करने में रूचि दिखा रहे हैं। इसलिए हर साल धान बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2018 से 2022 तक किसानों की संख्या 17 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गई है। इसके अलावा खेती का रकबा भी 25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है।

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं। राज्य में इस साल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। इसके पहले किसान पंजीयन का कार्य भी लगातार जारी है। कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक पंजीयन किया गया। अभी तक 24 लाख 5 हजार 288 हजार किसानों का पंजीयन कैरी फारवर्ड किया गया है और इसमें इस साल 95 हजार नए किसानों ने पंजीयन कराया है। इस साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस साल राज्य सरकार ने किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया है। इसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। धान खरीदी के लिए भारत सरकार की नए बारदाना नीति के अनुसार 50-50 के अनुपात में नए और पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा चावल के लिए प्राप्त 2 लाख 97 हजार गठान में से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। अभी तक 2 लाख 37 हजार गठान का इंडेट जारी किया गया है। इसमें से 1 लाख 45 हजार गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं बाकी 48 हजार गठान नए जूट बारदाने पिछले साल का उपलब्ध है। वहीं राज्य के मिलर्स समिति के पास मौजूद 2 लाख 53 हजार गठान पुराने बारदाने हैं। इसके अलावा बारदानों की कमी होने पर जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। कबीरधाम जिले में भी खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन खरीदी के पूर्व समितियों ने धान खरीदी में सूखत लागू करने सरकार से मांग की है। समिति प्रबंधकों का तर्क है कि किसानों से खरीदे गए धान का समय पर उठाव नहीं होने से सूखत आती है। इसके लिए समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और रिकवरी की जाती है।

समिति प्रबंधकों का तर्क है कि धान में सूखत आना प्राकृतिक घटना है। किसानों से 17 प्रतिशत नमी में धान खरीदी का पैमाना तय है। वहीं खरीदे गए धान का 72 घंटे में उठाव का अनुबंध होता है। लेकिन परिवहन करते समय धान में नमी 10 प्रतिशत रह जाती है। यानी 7 प्रतिशत तक नमी में कमी आती है, तो इसके लिए समितियों को जिम्मेदार बताया जाता है। जबकि धान का परिवहन समय पर नहीं होने और सूखत की जवाबदेही विपणन संघ की होनी चाहिए। मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पिछले दिनों समिति कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। धान खरीदी में समिति को हम्माली, मजदूरी, चौकीदार, सुतली, भूसा, लाइट व्यवस्था और कांटा बांट इत्यादि के लिए प्रासंगिक व सुरक्षा खर्च के रूप में 12 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। वर्ष 2007-08 के बाद इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि 15 साल में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। वर्ष 2007 में हम्माली दर 2 रुपए प्रति क्विंटल था, आज हमालों द्वारा 8 से 10 रुपए लेते हैं। भूसा 1 रुपए से 5 रुपए हो गया है। बोरा सिलाई के लिए सुतली 25 रुपए किलो था, वह 120-130 रुपए हो गया है। पिछले साल करीब 4 लाख टन धान खरीदी हुई थी। समितियों को प्रति क्विंटल धान खरीदी की दर से कमीशन दिया जाता है, जो अभी तक नहीं मिला है। वहीं ट्रक यूनियन कवर्धा से अनुबंध कर केंद्रों से धान का उठाव हुआ था। लेकिन अधिकांश ट्रक स्वामियों को परिवहन भाड़ा नहीं मिल सकता है। कमीशन और परिवहन भाड़ा का करोड़ों रुपए अटका हुआ है। बताया जा रहा है राज्य स्तर पर ईडी के छापे में उच्चाधिकारी पर कार्रवाई के चलते भुगतान नहीं हो सका है।

● रायपुर से टीपी सिंह

अब अरहर, मूंग एवं उड़द भी खरीदेगी सरकार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरूआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी से किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों के पास अब विकल्प होगा कि उन्हें जहां ज्यादा मूल्य मिलेगा वहां वे अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के माध्यम से अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग की फसल 7755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य में 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक और अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष में 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। दीवाली से पहले लिए गए सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।

खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के वैसे ही परिणाम सामने आए, जैसे अपेक्षित थे। आशा के अनुरूप मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसान जीत दर्ज की। उनकी जीत का प्रमुख कारण रहा यह अलिखित संदेश कि वह गांधी परिवार की पसंद हैं। इस संदेश की पुष्टि तभी हो गई थी, जब अशोक गहलोत की जगह खड़गे को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि वह इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ रहा है।

जहां खड़गे को करीब साढ़े नौ हजार मतों में से 88 प्रतिशत मिले, वहीं शशि थरूर को 12 प्रतिशत। 12 प्रतिशत वोट इसलिए कम नहीं, क्योंकि इसके पहले जब सीताराम केसरी और सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थीं, तब उन्हें चुनौती देने वाले नेताओं को इतने मत नहीं मिले थे। शशि थरूर को एक हजार से अधिक मत मिलना यह बताता है कि कांग्रेस के कई प्रतिनिधि यह नहीं चाहते कि पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ बनी रहे। ये प्रतिनिधि पार्टी में उन बदलावों के हामी भी दिख रहे, जिनकी वकालत थरूर कर रहे थे।

खड़गे की जीत इसीलिए हुई, क्योंकि गांधी परिवार के चारों तरफ जो मंडली है, वह इसी कोशिश में है कि यह परिवार पार्टी पर पहले की तरह काबिज रहकर प्रभावी बना रहे। खुद खड़गे इसी मंडली के सदस्य हैं। इसी मंडली ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने से रोका, क्योंकि उनके समर्थक विधायकों ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करने से इनकार कर दिया था कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का फैसला अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करें। इसे एक तरह से गांधी परिवार के खिलाफ गहलोत का विद्रोह माना गया। इस विद्रोह के बाद वह गांधी परिवार के विश्वासपात्र नहीं रह गए। ज्ञात हो कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की सूरत में गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता। वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान शशि थरूर ने जिन अनियमितताओं की ओर संकेत किया, उन्हें खारिज कर दिया गया। पता नहीं उनकी आपत्ति कितनी उचित थी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उन्हें गांधी परिवार का भरोसा हासिल नहीं था और यह पहले से स्पष्ट था कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इस परिवार की पसंद खड़गे ही हैं। 80 वर्षीय खड़गे के पास अच्छा-खासा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन अभी यह पता नहीं कि वह कांग्रेस में किस तरह जान फूकेंगे। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह सामंजस्य बनाकर चलेंगे, लेकिन उन्हें उन कांग्रेसियों के साथ भी सामंजस्य बनाना पड़ेगा जो यह नहीं चाह रहे कि राहुल गांधी अपने हिसाब से कांग्रेस को संचालित करें।

खड़गे की स्थिति सीताराम केसरी से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि जिस समय वह अध्यक्ष बने तब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार नहीं थीं। जब वह सक्रिय होने के लिए तैयार हुईं तो केसरी को अपमानजनक

खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। उन्हें कर्नाटक से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित लगभग हर जगह चरम पर पहुंची आंतरिक गुटबाजी पर लगाम लगानी होगी। चूंकि आम चुनाव की उलटी गिनती एक तरह से शुरू हो गई है, अतः कांग्रेस के पक्ष में अविलंब कोई कारगर अभियान छेड़ना होगा। भाजपा विरोधी किसी संभावित गठजोड़ को आकार देने में विपक्षी नेताओं को भी साधना होगा। यह सब आसान नहीं है।

खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़

बतौर अध्यक्ष खड़गे क्या कर सकते हैं, इसके जवाब कई पहलुओं पर निर्भर करते हैं। एक यह कि खड़गे अपनी भूमिका को कितना विस्तार दे पाते हैं। दूसरा यह कि खड़गे की पारी के दौरान गांधी परिवार का क्या रुख रहता है? अभी तक के संकेत यही दर्शाते हैं कि गांधी परिवार पार्टी पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता और उसका यही रवैया अध्यक्ष के रूप में खड़गे की भूमिका एवं सीमा का निर्धारण करेगा। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बदलाव के हिमायती थरूर जैसे नेता खड़गे को किस प्रकार सहयोग करते हैं। स्मरण रहे कि कोई भी कप्तान तभी सफल हो सकता है, जब उसे अपनी टीम की क्षमताओं का पूरा समर्थन मिले। खड़गे का रिपोर्ट कार्ड भी इसी आधार पर तैयार होगा। कई चुनौतियां नए कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं। हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात में पार्टी की हालत पतली दिख रही है। आम आदमी पार्टी उसका विकल्प बनने एवं भाजपा को मुख्य चुनौती देने के लिए भरसक जोर लगा रही है।

ढंग से जबरन किनारे कर दिया गया। ऐसा करने वाली गांधी परिवार की वह मंडली ही थी, जिसने अंतिम क्षण तक यह कोशिश की कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनें। जब वह इसके लिए तैयार नहीं हुए तो वह खड़गे को आगे लाई। मल्लिकार्जुन खड़गे इसीलिए अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि वह किसी के लिए और विशेष रूप से राहुल गांधी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। उनके अध्यक्ष बन जाने के बाद भी राहुल पहले की तरह पार्टी को पर्दे के पीछे से उसी तरह चलाएंगे, जैसे सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए चला रहे थे। राहुल गांधी भले ही यह कह रहे हों कि वह वही करेंगे जो खड़गे उनसे कहेंगे, पर उनकी क्या मजाल कि वह राहुल को कुछ निर्देश दे सकें या फिर उनके किसी फैसले से असहमत हो सकें। हैरानी नहीं कि खड़गे राहुल को पर्दे के पीछे से पार्टी चलाने में मदद करें। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। वह कांग्रेस के गिरते हुए वोट बैंक और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा पाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है।

उम्मीद यही है कि राहुल गांधी उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे यानी फैसले वही लेंगे। यह वह तथ्य है, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अच्छी तरह परिचित हैं और नेता भी। इस स्थिति में इसकी भी संभावना नहीं कि खड़गे कोई नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि एक तो वह पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी संचालन में गांधी परिवार की सलाह लेने में संकोच नहीं करेंगे और दूसरे अभी तक वह वही लाइन लेते रहे हैं, जो राहुल गांधी खींचते रहे हैं। क्या अध्यक्ष के रूप में खड़गे राहुल गांधी को इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि वह किसी नए विमर्श को अपनाएं? प्रश्न यह भी है कि क्या वह अपने स्तर कोई नया विमर्श खड़ा करने के साथ राहुल गांधी को इसके लिए सहमत कर सकते हैं कि वह गुजरात और हिमाचल में चुनाव प्रचार करने जोर-शोर से उतरें और इस दौरान उनके द्वारा खड़े किए गए विमर्श से जनता को परिचित कराएं? ध्यान रहे कि अभी तक राहुल गांधी ने जो भी विमर्श खड़े करने की कोशिश की, उसमें वह नाकाम ही रहे।

यदि राहुल गांधी अपनी राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने तक ही सीमित रखते हैं तो एक ऐसे नेता की उनकी यह छवि और पुख्ता होगी कि वह परिवार विशेष का सदस्य होने के नाते देश पर शासन करना अपना अधिकार समझते हैं। इन दिनों वह भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग उन्हें देखने-सुनने अवश्य आ रहे हैं, लेकिन वह कोई वैकल्पिक विचार या एजेंडा नहीं रख पा रहे हैं। इसके बिना कांग्रेस की बात बनने वाली नहीं है। गांधी परिवार पर निर्भर रहना कांग्रेस की मजबूरी है। इसे खड़गे भी समझते होंगे कि तमाम कमजोरियों के बाद भी गांधी परिवार और विशेष रूप से राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं, जिनका जनता में कुछ प्रभाव है। ऐसे में खड़गे की एक जिम्मेदारी राहुल गांधी की छवि का निर्माण करना भी है। क्या वह यह काम कर सकेंगे? अभी न तो इसके आसार दिखते हैं और न ही इसके कि खड़गे कांग्रेस में ऐसे नेता तैयार कर सकेंगे, जिनका अपना मजबूत जनाधार भी हो और राष्ट्रीय पहचान भी। कांग्रेस पिछले कुछ हफ्तों में एक साथ बेहतरीन और बदतरीन दौर से गुजरी है। बेहतरीन इसीलिए कि उसे लंबे समय के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष मिला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को बढ़िया प्रतिक्रिया मिल रही है। इससे कांग्रेस समर्थकों में उत्साह का संचार हुआ है। बदतरीन इस कारण कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना यथास्थितिवाद का ही उदाहरण है। वह उम्मीद जगाने और आवश्यक सुधारों का सूत्रपात करने वाला चेहरा नहीं दिखते। वहीं भारत जोड़ो यात्रा अभी अपने शुरुआती दौर में है और दक्षिण में कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ों से गुजर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे भी उसमें उत्साह की यही निरंतरता कायम रहेगी और उसे इसी प्रकार समर्थन मिलेगा या नहीं?

जो भी हो, नए अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले आम चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी का सांगठनिक ढांचा कामचलाऊ व्यवस्था का शिकार था। अस्वस्थ होते हुए भी सोनिया गांधी पार्टी की प्रमुख प्रभारी बनी हुई थीं। खांटी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले खड़गे 2019 से पहले कोई चुनाव नहीं हारे थे। वह कई बार विधायक और सांसद रहे। कर्नाटक के गृहमंत्री रहे। केंद्र सरकार में रेल और श्रम मंत्रालय संभाले। लोकसभा और राज्यसभा में नेता-प्रतिपक्ष का दायित्व संभालने के साथ ही पार्टी के लिए कई राजनीतिक संकट सुलझाए। ऐसे में उनकी राजनीतिक समझ और अनुभव को लेकर कोई संदेह नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वह कांग्रेस पार्टी को उसके सबसे मुश्किल दौर से उबार पाएंगे? इसका उत्तर काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि अध्यक्ष के रूप में खड़गे अपना कद किस प्रकार गढ़ते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह गांधी परिवार की मेहरबानी से ही अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में क्या वह पार्टी के प्रथम परिवार की छाया से बाहर निकलकर अपनी मर्जी से टीम बनाने के साथ ही पार्टी को अपने हिसाब से चला सकते हैं? उन अहम सुधारों को सिरे चढ़ा सकते हैं, जो पार्टी की खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए आवश्यक हो चले हैं?

● **विपिन कंधारी**

अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रही कांग्रेस

कांग्रेस इस समय अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। वह कभी इतने लंबे समय तक लगातार केंद्र की सत्ता से बाहर नहीं रही। पिछले पांच साल से उसने किसी बड़े राज्य की सत्ता भी हासिल नहीं की। आम आदमी पार्टी जैसे नए दल उसकी राजनीतिक जमीन हथिया रहे हैं। इस बीच पार्टी में गांधी परिवार का प्रभाव भी कमजोर पड़ने के संकेत मिले हैं। भले ही खड़गे परिवार की पसंद के रूप में अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन यह सब आसान नहीं रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पहली पसंद थे, लेकिन उन्होंने परिवार के विरुद्ध ही एक प्रकार का राजनीतिक विद्रोह कर दिया। फिर नए अध्यक्ष के लिए करीब आधा दर्जन नाम चले और अंत में खड़गे का नाम तय हुआ। चुनाव में शशि थरूर को जितने मत प्राप्त हुए, वह भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इतने वोट तो शरद पवार, राजेश पायलट और जितिन प्रसाद जैसे दिग्गजों को भी नहीं मिले थे, जो दशकों से राजनीति में सक्रिय रहे। थरूर महज तीसरी बार के सांसद हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि पार्टी में क्रांतिकारी सुधारों को लेकर थरूर का जो राजनीतिक दर्शन है, उसके साथ सहमति जताने और बदलाव चाहने वालों की संख्या भी अच्छी-खासी है।

देश के दो प्रमुख राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले 35-40 दिनों में चुनाव होने हैं। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन दोनों राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल का ही एक मैच माना जा रहा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। दोनों राज्यों में भाजपा व कांग्रेस के राजस्थानी नेताओं की इन चुनावों में खास भूमिका है। भाजपा भीड़ को खींचने की क्षमता रखने वाले राजस्थानी नेताओं का उपयोग कर रही है, वहीं अभी तक कांग्रेस हिमाचल प्रदेश पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है। गुजरात जैसे बड़े और राजनीतिक-आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य पर फिलहाल अभी तक उसका ज्यादा फोकस नहीं हुआ है। लगातार ढाई दशक से सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जहां गुजरात में अपना होमवर्क और फील्डवर्क पूरा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस तुलनात्मक रूप से होमवर्क और फील्डवर्क में अभी बहुत पीछे दिखाई दे रही है।

जीत की लय बरकरार रहेगी?

भाजपा ने साल 2022 की शुरुआत बंपर जीत के साथ की थी, 5 राज्यों में से 4 में सत्ता हथिया कर पार्टी ने ये साबित कर दिया था कि 2024 के लिए वह पूरी तरह तैयार है, बेशक उस चुनाव को सेमीफाइनल की संज्ञा दी गई, लेकिन वह तो चुनावी चक्र की महज एक शुरुआत थी। 2024 में होने वाले आम चुनाव तक भाजपा को ऐसी कई परीक्षाएं देनी हैं। हिमाचल और गुजरात चुनाव इसका अगला चरण हैं। दोनों ही प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, ऐसे में यहां जीत दर्ज करना पार्टी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने की वजह से दोनों नेताओं की साख भी दांव पर है। हिमाचल में चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान हो चुका है और गुजरात में घोषणा बाकी है, हालांकि चुनावी समर में उतरे सभी योद्धा अपने तरकश के तीरों का इस्तेमाल कर वार-पलटवार में जुटे हैं।

2024 में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले भाजपा के सामने जीत की लय बनाए रखना चुनौती है, 2022 की शुरुआत में से पांच में चार राज्यों में सरकार बना चुकी भाजपा के हौंसले बुलंद हैं, हिमाचल और गुजरात में यदि पार्टी जीत जाती है तो उसे आगे आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि चुनावी मौसम की फिजा 2023 में भी जारी रहेगी। दरअसल मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में मार्च माह में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके दो माह बाद ही कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं। जहां भाजपा को एक बार फिर खुद को साबित करना होगा। अगले साल दिसंबर के वक्त तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मप्र जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होने हैं, इनमें मप्र को छोड़ दें तो कहीं भाजपा की सरकार नहीं है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों का गृह राज्य है, ऐसे में यहां जीत या हार को सीधे-सीधे दोनों नेताओं से जोड़कर देखा जाएगा। राज्य में 1995 से भाजपा सत्ता में है, खुद प्रधानमंत्री मोदी 13 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद 2001 में उन्होंने प्रदेश की सत्ता संभाली थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि मोदी के दिल्ली जाने के बाद भाजपा कुछ कमजोर हुई है, 2017 के चुनाव में इसके कुछ संकेत भी मिले थे, हालांकि उस समय भाजपा के कमजोर प्रदर्शन की वजह पाटीदार आंदोलन को माना गया था।

भाजपा अपने प्रचार अभियान में बड़ी दमदारी से कहती है कि डबल इंजन सरकार का लोगों को डबल फायदा मिल रहा है, आम चुनाव तक भाजपा को कई बार डबल इंजन की परीक्षा से गुजरना होगा। उप्र-उत्तराखंड और गोवा में भाजपा अपनी डबल इंजन ताकत को सिद्ध कर चुकी है, हिमाचल और गुजरात में भी पार्टी डबल इंजन सरकार के फायदे गिना रही है। राज्य के साथ ही केंद्र सरकार के कामों को भी बताया जा रहा है।

40-50 सीटों पर भाजपा का खास फोकस

पार्टी सूत्रों की मानें तो जल्द ही अमित शाह इसको लेकर गुजरात के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गुजरात की 40-50 सीटें ऐसी हैं, जहां पार्टी खुद के सर्वे में कमजोर नजर आ रही है। इन सीटों को अपने पाले में लाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। यहां पर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ज्यादा रैलियां करवाने की तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी आदिवासी सीटों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। प्रदेश में आदिवासियों के लिए 27 सीटें रिजर्व हैं। साल 2017 में पार्टी सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी। दो सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिली थीं, बाकी की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बहुत ज्यादा जनाधार वाले नेता नहीं है। ऐसे में पार्टी ने तय किया है कि इस चुनाव में भी वो प्रधानमंत्री के चेहरे और अमित शाह की रणनीति के बलबूते ही जनता के बीच जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। जिसमें से बहुमत के लिए 92 सीटों पर जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। 2017 चुनाव में भाजपा को 99 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस को 77 सीट पर जीत हासिल हुई थी।

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल और गुजरात में रैलियों के दौरान हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता के सामने डबल इंजन सरकार की ताकत को दमदारी से रखा है।

गुजरात और हिमाचल में भाजपा मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। हर गली-मोहल्ले में प्रधानमंत्री मोदी के ही पोस्टर लगे हैं, खासकर गुजरात एक्सपो के दौरान के सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के ही पोस्टर नजर आ रहे थे। ऐसे में उन राज्यों को गंवाना जहां पर भाजपा पहले से सत्ता पर काबिज है, सीधे-सीधे पार्टी की कमजोरी का संदेश देगी, यदि किसी राज्य में भाजपा सत्ता से बेदखल होती है तो लोकसभा चुनाव पर इसका गलत असर जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लोगों के बीच उस धारणा को भी बल मिलेगा कि मोदी के चेहरे पर लड़कर भी भाजपा हार सकती है।

गुजरात में भाजपा पिछले 27 साल से काबिज है, इसलिए यहां तो ज्यादा मुसीबत नहीं, लेकिन हिमाचल में सत्ता परिवर्तन का मिथक पार्टी के लिए मुश्किल बना हुआ है, पार्टी मिशन रिपीट के तहत किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है, इसके अलावा गुजरात में भी लगातार छठवां चुनाव जीतकर सबसे लंबे समय तक किसी राज्य में सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, अब जल्द ही गुजरात की घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा के पास अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। सूत्रों की मानें तो एक बार फिर गुजरात में भाजपा की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उठा ली है। चुनाव आयोग ने गत दिनों जैसे ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया उसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई। गौर करने वाली बात ये है कि इस बैठक में हिमाचल नहीं, बल्कि गुजरात भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक आनन-फानन में बुलाई गई ये बैठक गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी। जानकारी के अनुसार 5 घंटे लंबी चली इस बैठक में गुजरात के सिंहासन को बचाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार भी गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर ही लड़ेगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मिलकर पूरी रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। खबर है कि 5 घंटे की मैराथन बैठक में गुजरात की रणनीति तय कर ली गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर संभावना जताई जा रही है कि जल्द चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। ऐसे में बचे हुए 10-12 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं।

कर्मचारियों और किसानों की नाराजगी दूर करना प्राथमिकता गुजरात में पिछले दिनों कई सरकारी कर्मचारी और किसान संगठन अपने मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में विरोध प्रदर्शन करने वालों में शिक्षक, क्लास-4 के सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, किसान, वन रक्षक और अन्य संगठन शामिल थे। ये ग्रेड पे बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से कुछ को शांत करने में भूपेंद्र पटेल सरकार कामयाब रही है, लेकिन कुछ संगठनों में नाराजगी अभी भी देखी जा रही है। यही वजह है इसके जल्द निपटारे के लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं। आप के वादों और कांग्रेस के खामोश प्रचार से निपटना गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने की संभावना है।

भाजपा-कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी जोरशोर से गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल पानी, बिजली फ्री देने के साथ-साथ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लोकलुभावन वादे भी कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात की जनता इन वादों के झांसे में ना आए इसके लिए भाजपा ने केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं को जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों को गिनाने का जिम्मा सौंपा है। गुजरात गौरव यात्रा इसी की एक शुरूआत है। वहीं कांग्रेस की खामोशी भी भाजपा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के खामोश प्रचार से सतर्क रहने की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गांव-गांव जाकर बैठक कर रही है। वो खबरों में नहीं दिख रहे और भाषण नहीं कर रहे इससे भ्रमित ना हों। इससे निपटने के लिए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क करने और घर-घर जाकर प्रचार करने की बात कही है।

● इन्द्र कुमार

राजस्थान के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर

राजस्थानवासियों, राजनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच राजस्थान के बाहर उप्र और गुजरात के चुनावों को लेकर हमेशा खास उत्सुकता और रुचि बनी रहती है। राजस्थान में लाखों परिवार ऐसे हैं, जिनका कोई ना कोई सदस्य गुजरात में जरूर रहता है। एक से दो लाख राजस्थानी लोग मेडिकल, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार आदि के लिए रोजाना गुजरात आते-जाते हैं। ऐसे में प्रदेशवासियों की गुजरात चुनाव में खासी रुचि रहना स्वाभाविक है। इसे देखते हुए भाजपा ने राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गुजरात चुनाव से जोड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक तो पार्टी में पिछले एक महीने से राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल अपना ध्यान हिमाचल प्रदेश पर शिफ्ट किया हुआ है। ऐसे में गुजरात चुनावों में कांग्रेस के राजस्थानी नेता भी ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस ने राजस्थान के वरिष्ठ नेता व पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा को चुनाव का प्रभारी बनाया हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं। उनके अतिरिक्त गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 17 मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया हुआ है। इस बीच दो बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात का दौरा किया है, लेकिन फिलहाल उनकी कोई बड़ी सभा या रैली वहां नहीं हुई है।

उद्धव के सामने भाजपा की रणनीतिक हार...

कुछ लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा ने पलटी क्यों मार ली। उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और निशान छीनने की मेहनत के बाद आखिर अंधेरी ईस्ट से भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया। नाम वापसी के आखिरी दिन भाजपा ने अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल को मैदान से क्यों हटा लिया। पहले तो यह समझ लें कि भाजपा और शिंदे गुट ने यह आश्चर्यचकित कर देने वाला फैसला अचानक नहीं किया है। यह सोची-समझी पहले से बनाई गई रणनीति के तहत ही हुआ है। भाजपा की पहली रणनीति यह थी कि उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और चुनाव निशान धनुष बाण छीना जाए। इसमें वे कामयाब रहे। दूसरी रणनीति यह थी कि शिवसेना के दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी रुतुजा लटके वहां से उपचुनाव न लड़ सके, क्योंकि वह चुनाव लड़ेगी तो दो कारणों से उसकी जीत तय थी। एक तो यह सीट मराठी बाहुल्य की है, दूसरे सहानुभूति के चलते उसकी जीत सुनिश्चित थी। इसलिए भाजपा और शिंदे शिवसेना की कोशिश थी कि ऋतुजा लटके का महानगरपालिका से इस्तीफा मंजूर नहीं हो, तब उद्धव ठाकरे को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। लेकिन ऋतुजा लटके हाईकोर्ट चली गई, जहां उसका इस्तीफा मंजूर करने का निर्देश जारी हो गया।

भाजपा-शिंदे शिवसेना की यह दूसरी रणनीति हाईकोर्ट ने नाकाम कर दी। तब पीछे हटने की तीसरी रणनीति अपनाई गई। यहां यह समझना भी महत्वपूर्ण है **अंधेरी ईस्ट सीट पर** गुजरातियों की संख्या बहुत कम है। यह इलाका मराठियों और उत्तर भारतीयों का गढ़ है। ऐसे में अंधेरी सीट पर गुजराती बनाम मराठी के बीच जंग होती तो भाजपा-शिंदे सेना के लिए मुकाबला भारी पड़ जाता। शिवसेना के रमेश लटके यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। इसकी एक वजह यह थी कि वह तीन बार स्थानीय नगरसेवक रहे थे और उनका अपने इलाके में अच्छा जनसंपर्क था। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह मराठी वोटरों का एकजुट होकर उनके पक्ष में वोटिंग करना रहा था। इसी कारण उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उपचुनाव में उतारकर सहानुभूति हासिल करने का दांव चला।

2014 में जब भाजपा शिवसेना अलग-अलग चुनाव लड़ी थी तो भाजपा ने मराठी वोटों के सियासी समीकरण को तोड़ने की बड़ी कोशिश की थी। रणनीतिक रूप से उसने इस सीट पर अपने उत्तर भारतीय उम्मीदवार सुनील यादव को चुनाव मैदान में उतारा था, ताकि उत्तर भारतीय और मराठियों को अलग-अलग किया जा सके, लेकिन 2014 की मोदी लहर के बावजूद शिवसेना उम्मीदवार रमेश लटके जीते थे। सुनील यादव पांच हजार वोट से हार गए थे। जब उत्तर भारतीय नहीं जीत पाया, तो गुजराती मुरजी पटेल के जीतने का तो सवाल ही नहीं था। 2019 में भाजपा-शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब मुरजी पटेल भाजपा में थे और उन्होंने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन वह साढ़े छह हजार वोटों से हारे थे। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़कर इतने कम अंतर से हार बड़ी हार नहीं है। लेकिन अब रमेश लटके की पत्नी की जीत सुनिश्चित थी, खासकर तब जब कांग्रेस और एनसीपी भी उनके समर्थन में थी।

कांग्रेस का भी इस सीट पर 30-35 हजार वोट है। जो पिछले दोनों चुनावों में बरकरार था। मुरजी पटेल के जीतने की बात तो दूर, वह टक्कर देने की स्थिति में भी नहीं थे। वह टक्कर देने की स्थिति में भी तब आते, जब उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार ऋतुजा लटके की बजाय कोई और होता। इसलिए भाजपा और शिंदे शिवसेना पहले से बनाई रणनीति के तहत परंपरा का बहाना बनाकर मैदान से हट गए। जैसे ही ऋतुजा लटके का नामांकन भरना तय हुआ, भाजपा-शिंदे गुट ने राज ठाकरे को सही वक्त पर इस्तेमाल किया। जिन्होंने भाजपा को चिट्ठी लिखकर उम्मीदवार को मैदान से हटाने का आग्रह किया। फिर शिंदे गुट के एक विधायक प्रताप सरनाईक का बयान आया और फिर उसके पीछे-पीछे शरद पवार का बयान आया। शरद पवार ने भाजपा को याद दिलाया कि 2014 में भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद एनसीपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, ताकि उनकी बेटी को चुना जा सके। हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा किसी भी हालत में मराठी बनाम गुजराती नहीं बनाना चाहती थी। शरद पवार ने एक तरह से यह बयान देकर भाजपा की मदद ही की।

● **बिन्दु माथुर**

शिवसेना के गढ़ में चुनाव

सत्ता में बदलाव के बाद यह पहला बड़ा चुनाव था और यह शिवसेना के गढ़ में होने वाला था। अगर भाजपा यह चुनाव हार जाती तो बीएमसी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ता। बीएमसी चुनावों से पहले भाजपा यह नहीं चाहती कि किसी भी तरह यह संदेश जाए कि एकनाथ शिंदे का सत्ता में आना मुंबई ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए परंपरा एक बहाना है, इस परंपरा का पिछले साढ़े तीन साल में ही पालन नहीं हुआ था। कोल्हापुर, पंढरपुर और देगलुर-बिलोली के उदाहरण हमारे सामने हैं, इन तीनों सीटों पर उपचुनाव में मृतक विधायक की पत्नी या बेटा चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। भाजपा व शिंदे गुट शिवसेना ने सोची समझी रणनीति के तहत पीछे हटने का कदम उठाया है, बड़ी जीत के लिए कई बार छोटी हार स्वीकार करनी पड़ती है। भाजपा नेता आशीष शेलार के बयान से इसे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह फैसला सोचसमझ कर लिया गया है। भाजपा के मुंबई कार्यकर्ता अगले दो-तीन महीनों में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखे, इस ऊर्जा का इस्तेमाल तब किया जाएगा। बीएमसी पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का दबदबा है। 2017 के बीएमसी चुनावों में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार शिवसेना में दो-फाड़ के बाद भाजपा को सत्ता अपने हाथ में आने का मौका नजर आ रहा है।

राजस्थान बना राजनीति का अखाड़ा!

कांग्रेस में मुख्यमंत्री के विवाद के चलते राजस्थान देशभर में चर्चा का गढ़ बना हुआ है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम और फिर राजस्थान में 25 सितंबर को विधायकों के इस्तीफों ने राजस्थान को गपशप का केंद्र बना दिया। पूरे देश की निगाहें राजस्थान पर हैं, क्योंकि अगले पल राजस्थान की राजनीति में क्या होना है, ये कोई नहीं जानता? मगर क्या होना है ये सब जानना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में ये उठापटक चंद दिनों से नहीं है। दरअसल पिछले कई वर्षों में राजस्थान में सियासी घमासान चलता ही रहा है। पार्टी कोई भी हो, राजस्थान की राजनीति में हलचल थमती नहीं है। राजस्थान की राजनीति आज केंद्रीय राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यही वजह है कि अब से कुछ वर्षों पहले तक राजनीतिक परिपेक्ष्य से एक सुस्त प्रदेश के रूप में पहचाना जाने वाला राजस्थान आज देश की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है।

राजस्थान में 1993 के बाद से राजनीति में एक ट्रैंड चलता आया है। हर पांच साल में सरकार बदलती है और अपने पांच साल पूरे भी करती है। मगर 2018 में बनी कांग्रेस सरकार को लेकर लगातार अस्थिरता रही। मार्च से ही पहले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के दो पदों पर रहने पर सवाल उठने लगे। उसके बाद जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने विद्रोह किया और अपने समर्थित विधायकों के साथ **मानेसर** चले गए। उस दौरान जैसे-तैसे स्थितियां संभली। मगर सरकार को लेकर अनिश्चितता बनी रही। अभी हाल ही में विधायकों के इस्तीफे के बाद भी हालात वैसे ही नजर आने लगे। राजस्थान में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस दोनों में लीडरशिप बेहद मजबूत है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ऐसे नेता हैं जिन्हें सेंट्रल लीडरशिप ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकती। दोनों का अपनी-अपनी पार्टी में राजनीतिक कद ऐसा है कि अपने बूते राजनीतिक स्थितियों को बदल सकने में सक्षम हैं। ऐसे नेता देश के अन्य किसी राज्य में दोनों ही पार्टियों में नहीं हैं जो अपनी सेंट्रल लीडरशिप को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसा टू-पार्टी स्टेट है। जहां भाजपा को वर्तमान हालातों में सबसे ज्यादा चुनौतियां मिलती रही हैं। पिछले दो चुनाव से लगातार 25-25 सांसद जीतने के बावजूद भाजपा यहां कांग्रेस की जड़ों को हिला नहीं पाई। जितना उसने अन्य राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उस मुकाबले राजस्थान में भाजपा कुछ भी नहीं कर पाई। अगर आपसी गुटबाजी को साइड कर दें तो यहां जमीन पर अब भी कांग्रेस की जड़े मजबूत हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अन्य राज्यों के मुकाबले यहां भाजपा को टफ कॉम्पीटिशन देती है।

राजस्थान में दोनों पार्टियों में लगातार गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर कलह देखने को मिलती रही है। कांग्रेस में यह सामने आ चुकी है। वहीं भाजपा में यह अंदरखाने नजर आती है। कांग्रेस में जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच लगातार तनाव देखने को मिलता है। वहीं भाजपा में वसुंधरा राजे समर्थित एक अलग खेमा है। वहीं सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया समर्थित अलग खेमा है। इसके अलावा सेंट्रल लीडरशिप की पसंद होने के चलते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव के भी अपने समर्थक हैं। जिनके बीच लगातार मतभेद सामने आते रहते हैं। राजस्थान की दोनों ही पार्टियों में प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे हैं। कुछ जहां वर्तमान में अहम पदों पर हैं तो कुछ पार्टियों के भविष्य के सबसे मजबूत दावेदार हैं। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला राजस्थान से ही हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस में सचिन पायलट देशभर के युवा नेताओं में सबसे प्रभावशाली और प्रचलित चेहरा हैं। वहीं वंसुधरा राजे देशभर की महिला नेताओं में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां भाजपा को संघर्ष करना पड़ा है। एक ओर जहां देशभर में मप्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा ने सत्ता पलटकर सरकार बनाई। मगर 2020 में भाजपा राजस्थान में बगावत के बावजूद कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा दो बार राज्यसभा चुनावों में भी भाजपा ने अपनी कूटनीति से जीत हासिल करनी चाही। मगर दोनों बार ही वे सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में जहां भाजपा की **सेंट्रल लीडरशिप** को चैलेंज करने वाले नेता नहीं हैं। मगर राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर भाजपा की लीडरशिप को वसुंधरा राजे के आगे झुकना पड़ा है। फिर चाहे वो राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष का चयन हो या फिर 2018 विधानसभा में टिकट बांटने का। यही वजह है कि भाजपा के लिए राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

एकमात्र राज्य जहां सरकार रिपीट होने की उम्मीद

कांग्रेस के लिए राजस्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस शासित सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा राजस्थान ही वह राज्य है जहां कांग्रेस की जड़ें अब भी मजबूत हैं। यहां कांग्रेस की अच्छी पकड़ और मजबूत योजनाओं के बूते कांग्रेस सरकार रिपीट करने के बारे में सोच रही है। इसके अलावा अगर आपसी लड़ाई ना हो तो यहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉ. सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेता और कई मजबूत नेता भी मौजूद हैं। जिनकी कमी कांग्रेस को अन्य राज्यों में खलती है। राजस्थान में थर्ड फ्रंट भी तेजी से मजबूत हो रहा है। यहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के पास 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। इसके अलावा यहां आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय ट्राइबल पार्टी भी प्रभाव रखती है। उसके पास दो विधानसभा सीटें हैं। हालांकि अब भी थर्ड फ्रंट के रूप में कोई पार्टी खास प्रभावित नहीं कर सकी है। इसलिए अन्य पार्टियां लगातार यहां अपनी संभावनाएं तलाशती हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अब राजस्थान में पैर जमाना शुरू कर दिया। आप पार्टी 2023 में यहां अपना खाता खोलने की तैयारी कर रही है।

राम नाम से राजनीतिक पुनर्जागरण

पंद्रह लाख छिहत्तर हजार दीयों की जगमग। उल्लास, उत्साह, भक्ति का संगम। रोम-रोम में झुरझुरी पैदा करता आनंद। गर्वित भाव से ऊर्जित चेहरे। धमनियों में तीव्र होता रक्त उद्वेग। भिंची हुई मुट्ठियां। सुनहरे अतीत का समृद्ध भाव। जय श्रीराम के जयकारे की गूंज। यह चित्र है अयोध्या की नई राजनीतिक पुनर्जागरण यात्रा का, जिसकी शुरुआत 1949 में बाबा राघवदास और महंत दिग्विजय नाथ ने जन्मभूमि पर राम परिवार की मूर्ति स्थापना के साथ की थी। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे। उसी अयोध्या, जिसे ऐतिहासिक एवं पौराणिक होने के बावजूद आजाद भारत में सत्तर सालों तक अपने और श्रीराम के वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ा। कोर्ट-कचहरी, राम भक्तों की खून से सनी लाशों को देखने का दर्द सहते हुए बरसों उजाड़ रहना पड़ा।

आजादी के बाद से अयोध्या ने सियासत में भेदभाव के कई रंग देखे। राम की जिस अयोध्या को देश की आजादी के बाद ही मुक्त हो जाना था, उसे अपनी मुक्ति के लिए सात दशक लंबा इंतजार करना पड़ा। वह भी तब, जब राम केवल नाम नहीं बल्कि भारत की जनभावनाओं के प्रतीक हैं। लोक के जीवन एवं भाव में समाहित हैं। अयोध्या के साथ राम को भी अपने अस्तित्व की परीक्षा देनी पड़ी, जिनका प्रभाव भारत में ही नहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, थाइलैंड तक किसी ना किसी रूप में है। लोक के मन में विराजमान जिस राम का नाम बड़े से बड़े आक्रांता खत्म नहीं कर पाए, उस राम के नाम पर भारत की सेकुलर सियासत ने प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। अयोध्या में मोदी ने जब कहा, एक समय था राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था, राम के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाए जाते थे। तब मोदी उसी धर्म निरपेक्ष **सियासत पर निशाना** साध रहे थे, जिसने जनभावनाओं के खिलाफ राम और अयोध्या को अछूत बनाकर रख दिया था। मोदी ने कहा कि अयोध्या जिन दीपों से दिप्त हैं, भावनाओं से भव्य हैं, आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। तब वह उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे, जो पिछले सत्तर सालों से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे।

दरअसल, देश आजाद होने के बाद ही अयोध्या की राजनीतिक पुनर्जागरण की यात्रा शुरू हो जानी चाहिए थी, जब कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए बाबा राघव दास को उतारकर पहली बार हिंदुत्व की सियासत की शुरुआत की थी। बाबा राघव दास ने जनमानस से वादा करते हुए संकल्प लिया था कि चुनाव जीतने के बाद रामजन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन हिंदुत्व और अयोध्या उत्थान की यह पहली परीक्षा सफल रही। बाबा राघवदास ने आचार्य नरेंद्र देव को 1312 वोटों से हराने के बाद अपने संकल्प को पूरा करते हुए गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ समेत कुल पांच संतों के साथ मिलकर 22-23 दिसंबर 1948 की रात में विवादित परिसर का ताला खोलकर भगवान राम की मूर्ति रखवा दी और भजन-कीर्तन शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ नए भारत में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन और राजनीतिक पुनर्जागरण का आंदोलन। बाबरी ढांचा में मूर्ति रखे जाने की जानकारी जब प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखकर मूर्ति हटवाने का निर्देश दिया। पंत ने फैजाबाद जिले के तत्कालीन डीएम केके नायर को मूर्ति हटवाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने बवाल की आशंका जताते हुए मूर्ति हटवाने से इनकार कर दिया। नेहरू के निर्देश पर गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुबारा पंत को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री नेहरू चाहते हैं कि मूर्ति हटवाने का कोई विकल्प तलाशा जाए। पंत ने एक बार फिर डीएम पर मूर्ति हटाने का दबाव डाला। एक बार फिर मूर्ति हटवाने से इनकार करते हुए केके नायर ने अपने पद से इस्तीफा देकर समूची सरकार को सकते में डाल दिया। बाबा राघव दास, अवैद्यनाथ की मूर्ति स्थापना और केके नायर के बलिदान से शुरू हुए आंदोलन की राजनीतिक ताकत को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर से चुनाव लड़ते हुए महसूस किया। उन्होंने अनुभव किया लोकमानस में गहरे पैठे राम के खिलाफ जाकर राजनीति में टिकना मुश्किल है। राम के बिना देश का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण संभव नहीं है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

राम के नाम पर राजनीति शुरू

इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन ने धार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण से आगे बढ़कर राजनीतिक पुनर्जागरण का रूप ले लिया। इस आंदोलन में बाद में कई नायक उभरे। भाजपा को साधु-संतों का भी साथ मिला। वाजपेई को गोरक्षपीठ महंत अवैद्यनाथ का भी सहयोग मिला, जिन्होंने 1984 में देश के सभी पंथों के शैव-वैष्णव, धर्माचार्यों को एक मंच पर श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया, और 7 अक्टूबर को सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए धर्मयात्रा निकाली। संयोग है कि गोरक्षपीठ राममंदिर आंदोलन के राजनीतिक पुनर्जागरण सहयात्री रहा है। 1949 में मंदिर में मूर्ति रखी गई तब महंत दिग्विजयनाथ की सहभागिता रही। 1986 में राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया तब महंत अवैद्यनाथ मौजूद रहे। राममंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ शिलान्यास के सहभागी बने। राम के नाम पर 1948 के उपचुनाव में हिंदुत्व के सफल राजनीतिक प्रयोग के बाद कांग्रेस ने प्रकारांतर कम्युनिस्टों के दबाव में राम मंदिर के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान को हिंदू-मुसलमान का मुद्दा बना दिया और संविधान में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण वाली कट्टरपंथी राजनीति की नींव रखी, जबकि कांग्रेस के दिग्गज महात्मा गांधी तक सुराज और राम राज्य की बात खुलकर करते थे।

कब आएगी बिहार में बहार

ऐसे कई सवाल हैं, जो आज तक अनसुलझे हैं और उन्हें सुलझाने के लिए जो आत्मबल चाहिए, वहां के राजनीतिज्ञों में उसकी घोर कमी है। ये अपनी कुर्सी पाने से पहले जनता को गफलत में रखते हैं और सत्तासीन हो जाने के बाद उनका दुख जानने, उनकी उम्मीदों को पूरा करने, अपने वादे पर अमल करने की बातें जानबूझकर भूल जाते रहे हैं। इसीलिए जब वहां के युवा बेरोजगारी से आजिज आकर बिहार से पलायन करते हैं और अन्य राज्यों, विशेषकर बड़े शहरों में जाते हैं, तो वही युवा बिहार की दुर्दशा के लिए विषवमन करते हैं।

स्वाभाविक है, दूर तक गलत संदेश जाता है और बिहार की छवि खराब होती है। परिणाम यह होता है कि बाहर से आकर कोई उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाता। सरकारी लापरवाही से स्थानीय सारे उद्योग-धंधे बंद हो गए और युवा दूसरे राज्यों में रोटी के चक्कर में अपमान का घूंट पीते रहे। यह एक उदाहरण है कि 1945-1947 में बिहार में 33 बड़ी-बड़ी चीनी मिलें थीं, आज 10 मिलें हैं। यहां की जमीन गन्ने की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन हम गन्ना नहीं उगा सकते, क्योंकि मिलें बंद हैं। रैयाम दरभंगा, लोहट मधुबनी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर, गरौल वैशाली, बनमनखी पूर्णिया की पांच चीनी मिलें बंद हैं। बनमनखी चीनी मिल की संपत्ति को कबाड़ में बेचा जा रहा है। 118 एकड़ में फैले इस चीनी मिल की दुर्दशा पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सकरी तथा समस्तीपुर वाले मिल को सरकार ने बंद कर दूसरा उद्योग लगाने के लिए दे दिया है, लेकिन क्या वे उद्योग लगाए जा सकेंगे? लोहट मिल बंदी के खिलाफ पुर्जों को कबाड़ में बेचने के विरोध में मधुबनी जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन जारी है। यही हाल जूट मिलों का है। भारत में जूट का 40 प्रतिशत तक उत्पादन करने वाले बिहार के तीनों मिल बंदी के कगार पर हैं, क्योंकि जूट की खेती अब यहां के किसान नहीं करते हैं। रही बात कागज उद्योग की, तो सैकड़ों एकड़ जमीन में फैले अशोक पेपर मिल हायाघाट आज बंद है और विषैले सांपों का जंगल बन गया है।

बिहार के सहरसा-मधेपुरा हाईवे पर सहरसा से पांच किलोमीटर पूरब बैजनाथपुर कागज मिल को पचास एकड़ में बनाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बनने के बाद आज उसकी संपत्ति कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। इस उद्योग के निर्माण का कार्य सत्तर के दशक में शुरू किया गया था, उसमें रोजगार की उम्मीद लगाए आज तक सिर पीटते जीवन गुजार रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी ने इसका दौरा किया और कहा है कि इस जमीन का उपयोग कृषि उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री बनाने के लिए किया जाएगा। 12 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी रैली में कहा था, 'ज्यादा बड़ा उद्योग वहां लगता है, जो समुद्र के किनारे के राज्य होते हैं। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके।' मुख्यमंत्री की बातें पढ़े-लिखे युवाओं को हतोत्साहित ही कर रही हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वादा तो यही था कि यदि उनकी सरकार बनी तो लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कृत संकल्पित होगी। लेकिन हां, यदि भाजपा के नजरिए से देखें तो यह चुनावी जुमला कहलाता है, लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं। उनकी बातों पर तो विश्वास अभी तक युवाओं का है और उपमुख्यमंत्री के रूप में जिस आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट देखने के लिए युवाओं को कुछ इंतजार करना ही होगा।

सरकार अभी बनी है, इसलिए इस नई सरकार को कुछ समय देना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन मिलों से लाखों लोग अपने परिवार की जीविका चला रहे थे, उनका क्या होगा जो अब बंद हो चुकी हैं। चीनी और कागज की जो मिलें बंद हो गई हैं, क्या उन्हें फिर से चालू करने का प्रयास वर्तमान सरकार करेगी? यदि उन्हें फिर से नियमित नहीं किया जाएगा तो फिर किस योजना के तहत बिहार की वर्तमान सरकार रोजगार मुहैया करा सकेगी? यदि सरकार की सोच सच में अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने की है तो सबसे पहले उसे उन सभी चीनी मिलों, कागज मिलों को चालू कराना होगा, क्योंकि जहां घर-घर में सभी बेरोजगार हो, वहां कोई किस प्रकार अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेगा।

बिहार में पंद्रह वर्ष लालू प्रसाद यादव ने यदि विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया होता और उसके बाद के पंद्रह वर्षों में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की ओर लगाया होता तो जो स्थिति आज वहां हो गई है, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। वैसे, यह तो राजनीति में सत्ता पाने के लिए हर दल दूसरे दल को नीचा दिखाने का, भारत ही नहीं विश्व में प्रयास होता ही रहता है, लेकिन बिहार के राजनीतिज्ञ इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार यदि विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राष्ट्र अथवा राज्य का विकास न हो, लेकिन बिहार के राजनेता केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही कुछ करते हैं और उन्हें जनता से कोई लेना-देना नहीं होता।

● **विनोद बक्सरी**

रोजगार देने में भाजपा बाधक है

जनता से उनका लेना-देना केवल चुनाव के समय ही होता है, जब उनका स्वार्थ सिद्ध होना होता है। जो भी हो, बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, वहां की सभी बंद मिलें फिर से शुरू हों, उसके हूटर बजे, इसके प्रयास होने चाहिए। ऐसा करने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने और अपमान का घूंट पीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्हें राज्य और वहां के युवाओं का विकास करने से भाजपा टांग खींचती है। बिहार का विकास पिछले वर्षों में इसलिए भी अवरुद्ध हुआ, क्योंकि देश के किसी भी उद्योगपति ने वहां अपना उद्योग लगाने में रुचि नहीं दिखाई। इसके कई कारणों में एक कारण यह भी है कि उनके मन में यह भय है कि बिहार में उनकी और उनके उद्योग की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। विपक्षियों ने प्रचारित किया है कि बिहार में जंगल राज है, वहां कानून-व्यवस्था नामक कुछ भी नहीं है, बिहार को जमकर बदनाम किया है। वैसे, नीतीश सरकार ने पिछले कुछ सालों में आम लोगों की जिंदगी की जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, उन्हें पूरा करने के प्रयास में सड़क और बिजली को ठीक कर दिया है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी ने सब पर पानी फेर दिया है।

शी जिनपिंग पूरी तरह तानाशाह

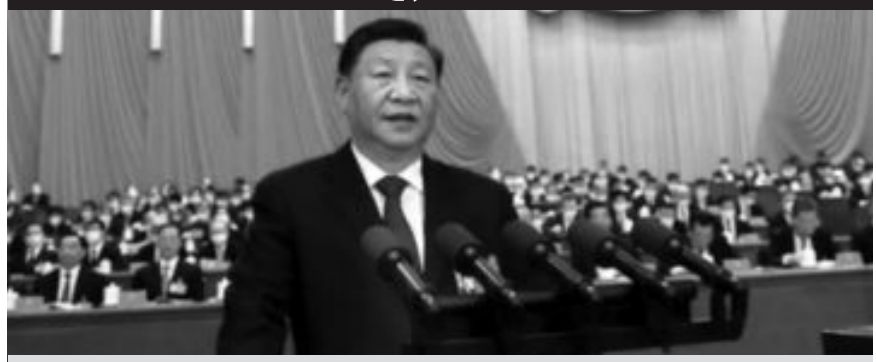

भारत के लिए चुनौतीपूर्ण

भारत के लिए इसका मतलब है कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और उनके बीच की सीमा के अन्य हिस्सों पर अपने दावों पर कायम रहेगा। आने वाले वर्षों में दोनों सेनाओं के बीच सीमा तनाव और संघर्ष की संभावना है। जापान, वियतनाम और ताइवान के साथ भी ऐसे ही हालात होंगे। दूसरा लक्ष्य, एक नई वैश्विक विश्व व्यवस्था बनाने और अमेरिका से आगे निकलने का है। इससे निकट भविष्य में इन दोनों के बीच टकराव की वास्तविक संभावना है। यदि शी सफल होते हैं तो वह चीन को विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लेंगे। शी के लिए इन उद्देश्यों को हासिल करना आसान नहीं होगा। खासतौर पर उनके द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर। सेहत के मामलों को छोड़ दिया जाए तो शी के चरित्र, व्यक्तित्व और मानसिक मजबूती से पता चलता है कि वह इस दिशा में काम करेंगे। अपनी नीतियों के लिए पार्टी का समर्थन हासिल करने के बाद, शी किसी भी नीति से आसानी से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह मामला आर्थिक हो या फिर सुरक्षा या चीन की आक्रामक मुद्रा का हो।

शी जिनपिंग अब पूरी तरह तानाशाह बन गए हैं। चीनी कानून को तोड़ते हुए वे तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। अब शासन और सेना दोनों उनके हाथ में है। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में चीनी राजनीति पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पकड़ और मजबूत होकर उभरी है। पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति में शी के चार नए सहयोगियों को जगह दी गई, जबकि दो लोग पहले से ही इसके सदस्य हैं। चीन की सत्ता पर शी की अगुवाई वाली इसी सात सदस्यीय समिति का कब्जा है। इनका इस संस्था पर एकतरफा दबदबा है, जो चीन के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है। यहां तक कि अपनी बुलंदी के दौर में माओत्से तुंग को भी प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा था। बो सिलाई और शन झेनकाई जैसे पिछले प्रतिद्वंद्वियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजने के बाद शी के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं रह गई है। बीते समय के खेमे वाली व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया गया है। शी के पूर्ववर्ती, जियांग जेमिन और हू जिंताओ का अब कोई प्रभाव नहीं है। जियांग कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, जबकि हू को अंतिम दिन सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों पर मतदान करने से पहले ही बैठक से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि उनको जबरन बाहर निकाले जाने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन इस घटना से शी का प्रभुत्व रेखांकित होता है। शी के दो सहयोगियों के शीर्ष पदों पर आने का रास्ता साफ करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग और उप प्रधानमंत्री वांग यांग का **समय से पहले रिटायर होना** भी इसी तरफ इशारा करता है। ली की जगह शी के करीबी सहयोगी ली कियांग ने ली है, जिनकी इस साल शंघाई में कोविड-19 के लिए कठोर लॉकडाउन नीति की वजह से काफी आलोचना हुई थी। वह अब देश में दूसरे नंबर के नेता हैं। एक संवैधानिक संशोधन में यह बताया गया है कि अब शी की बातों का पालन करना, पार्टी के सभी सदस्यों का दायित्व है। वहीं, चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इन दोनों नेताओं की पदोन्नति के पीछे शी के प्रति वफादारी को कारण बताया है।

कम्युनिस्ट पार्टी ने समूची सत्ता शी के हाथों में सौंप दी है और कहा है कि चीन में एक-व्यक्ति के शासन की वापसी जरूरी है। शी अपने दौर से पहले अक्सर कमजोर नेतृत्व की आलोचना किया करते थे और अब कांग्रेस में भी उन्होंने वही किया। पार्टी की नजर में मजबूत नेतृत्व ही मजबूत देश की एकमात्र गारंटी है। शी का यह पसंदीदा जुमला है जिसे वे अमेरिका के सामने तनकर खड़े होने और धीमी अर्थव्यवस्था जैसी घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी मानते हैं। हालांकि, बाजार की प्रतिक्रिया इस पर उल्टी रही। हांगकांग में चीनी स्टॉक ने 2008 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की और विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड संख्या में चीनी कंपनियों के शेयर बेच दिए। अतीत में चीनी नेताओं ने मौजूदा विश्व व्यवस्था की व्याख्या चीन के लिए रणनीतिक अवसर का दौर पेश करने के रूप में की है। शी ने उस व्याख्या को बदल दिया। वे इसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया की तस्वीर के रूप में पेश करते रहे हैं जिसमें संघर्ष और लड़ने के जज्बे की जरूरत है। इन दोनों वाक्यांशों को संविधान में भी जोड़ा गया। पार्टी और सेना की पूरी कमान के साथ, शी अब अपने पांच साल के तीसरे कार्यकाल में उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे-जैसे शी अपनी विदेश नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे वे भारत, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विरोध के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में बड़ी बाधाओं का सामना करेंगे। ये देश चीन को क्षेत्रीय अधिपति बनने देना आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और यक्रेन के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनाव पहले से ही बहुत अधिक है। सीसीपी के सदस्य इस बात से आशंकित हैं कि तनाव के बढ़ने से चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगभग 40 मिलियन सीनियर सीसीपी कैडर और उनके परिवारों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करेगा।

महान चीनी राष्ट्र के कायाकल्प और चीन को वैश्विक प्रभाव के साथ एक प्रमुख शक्ति बनाने के साथ-साथ एक जैसे भाग्य का समुदाय बनाने के लिए दुनिया को प्रभावित करना, शी की सोच है। इन्हें संविधान में भी शामिल किया गया है। 'शताब्दी के दो' लक्ष्यों के रूप में, पहले लक्ष्य में चीन की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना शामिल है, इसमें उन क्षेत्रों को पुनर्प्राप्ति की इच्छा है जिन्हें दावे के मुताबिक शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों द्वारा असमान संधि लागू करके ले लिया गया था। धीमी होती अर्थव्यवस्था और चीन के उद्यमियों की आशंकाओं को नजरअंदाज करते हुए शी ने चीन के फिनटेक और रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए नियमों को कड़ा करना जारी रखा और साझा समृद्धि की बात कही। उन्होंने असंतोष और विरोध को सामाजिक व्यवस्था व स्थिरता के लिए खतरा के रूप में दिखाया है। इन्हें रंग क्रांति के माध्यम से सीसीपी को गिराने के अमेरिकी प्रयासों के संकेत के रूप में चित्रित किया है। उनकी विदेश नीति की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि इससे चीन की 'मजबूत' राष्ट्र की आत्म-धारणा कमजोर होगी। शी के नेतृत्व में, अगले पांच वर्ष कठिन और तनावपूर्ण होंगे और इस क्षेत्र व दुनिया के लिए इसके परिणाम महत्वपूर्ण होंगे।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

ऋषि सुनक की ताजपोशी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ऋषि सुनक को मिलने पर स्वाभाविक ही भारत में खुशी की लहर है। सुनक की जड़ें अविभाजित भारत से जुड़ी हैं। वे धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। इस तरह औपनिवेशिक सत्ता के बरक्स एक भारतीय मूल के व्यक्ति का ब्रिटिश हुकूमत के शीर्ष पर पहुंचना समय के पलटने के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचीं तब भी ऐसा ही गर्व अनुभव किया गया। सुनक से भारत की उम्मीदें सहज ही जुड़ी हुई हैं। मगर ब्रिटेन की सुनक से उम्मीदें दूसरी हैं। वहां के सांसदों ने उनमें एक ऐसे दक्ष प्रशासक के गुण देखे हैं, जो एकता और स्थायित्व की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। लिज ट्रस पैंतालीस दिनों में ही वहां की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को संभालने से हार मान बैठीं। दरअसल, इस वक्त ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के मामले में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई वहां चरम पर पहुंच चुकी है और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा मामलों में उसे अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल साबित हो रहा है। बिजली के दाम आम लोगों की क्षमता से बाहर निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के पास दो ही आसान रास्ते हैं कि वह करों में बढ़ोतरी और खर्चों में कटौती करे। मगर ये दोनों कदम जोखिम भरे हैं। सुनक वित्तमंत्री रह चुके हैं और उनके पास अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के कुछ नुस्खे हैं, जिन पर वहां के लोगों को भरोसा है। हालांकि किसी भी नए शासक के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, जिसे घुमाकर एकदम से खराब अर्थव्यवस्था को सुधार दे।

बेशक सुनक के पास कुछ बेहतर उपाय हो सकते हैं, मगर उनके लिए ब्रिटेन को वर्तमान स्थितियों से बाहर निकालना आसान काम नहीं होगा। फिर देश की स्थिति संभालने के साथ-साथ उन पर **पार्टी की छवि सुधारने** का दारोमदार भी है। अगर उनकी सरकार खर्चों में कटौती का फैसला करती है, तो आम लोगों में विद्रोह फूट सकता है। अभी स्थिति यह है कि लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बड़ी संख्या में छोटे कारोबार बंद हो गए और होते जा रहे हैं, पाउंड की कीमत चिंताजनक स्तर पर गिर चुकी है, वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लोगों को चिंता है कि सर्दी में घर गरम करने के लिए वे बिजली का खर्च कैसे जुटाएंगे। मगर व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाकर वे इस दलदल से शायद जल्दी बाहर निकल सकें।

पिछले कुछ सालों में भारत और भारतीय मूल के लोगों के प्रति वहां के नागरिकों में कुछ नकारात्मक भावनाएं भरनी शुरू हो गई थीं, जिन्हें सुनक दूर करने में कारगर साबित होंगे। अभी लेस्टर में हुए सांप्रदायिक दंगों से भी वहां के उदारवादी लोकतांत्रिक ताने-बाने को चोट पहुंची है। सुनक ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को पूरी मजबूती के साथ लागू रखेंगे और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। सुनक युवा हैं और पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस तरह उनसे बेहतर प्रबंधन की उम्मीदें अधिक हैं। वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए जिन बदलावों की सलाह दी थी, उन्हें नहीं माना गया और वही हुआ, जिसकी आशंका उन्होंने जताई थी। अब उन्हें उन सुझावों पर अमल का मौका है। निसंदेह उनमें ब्रिटेन को आर्थिक दलदल से बाहर निकालने और उसे सामाजिक रूप से बिखने से रोकने का माद्दा नजर आता है।

सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारत से लेकर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों में जश्न का माहौल है। इन सबके बीच इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने भी अपने दामाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। हमें उन पर गर्व है- नारायण मूर्ति दरअसल ऋषि सुनक को ब्रिटेन की कमान मिलने पर पीटीआई को ईमेल के जरिए पहली प्रतिक्रिया देते हुए नारायण मूर्ति ने कहा, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि वो ब्रिटेन के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले ऋषि सुनक ने कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व पद की दौड़ में जीत हासिल की और अब वो ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। बता दें कि एक फार्मासिस्ट मां और डॉक्टर पिता के बेटे सुनक की शिक्षा इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक विनचेस्टर और फिर ऑक्सफोर्ड में हुई थी। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक कंपनी में तीन साल काम किया और बाद में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड से एमबीए किया, जहां उनकी मुलाकात इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई। साल 2009 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की दो बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। ब्रिटेन में टोरी लीडरशिप का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया है। ऋषि सुनक का दो महीने के अंदर ही यूके का प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के भीतर हुए चुनाव को हारकर फिर जीत जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

● **कुमार विनोद**

इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं जियॉर्जिया मेलोनी

राइट विंग नेता जियॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। इसी के साथ इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नई सरकार का गठन हो गया है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद

इटली में ये पहली बार है जब राइट विंग का कोई नेता प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेगा। जॉर्जिया की पार्टी इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी की समर्थक हैं। अप्रवासियों को शरण नहीं देना और समलैंगिकों का विरोध और उन्हें हक नहीं देना जॉर्जिया के चुनावी एजेंडे थे। जियोर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ। वह एक इतालवी पत्रकार और पॉलिटिशियन हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया था। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट नाम दिया गया था। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने इसके यूथ विंग में काम किया।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

जेल में पति से अकेले में मिल सकेगी पत्नी

जब किसी आपराधिक मामले में कोई पुरुष जेल की सलाखों के पीछे जाता है तो उस पर आश्रित रहने वाला पूरा परिवार बिखर जाता है। खासकर उक्त पुरुष की पत्नी को सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। इसको देखते हुए देश में एक बड़े बदलाव की कवायद शुरु हुई है, इसके तहत अब महिलाएं जेल में पति के साथ कुछ दिन बिता सकती हैं।

जेल की सलाखें भी अब वंश बढ़ाने की गवाह बनेंगीं। जेल में बंद पति या पत्नी अपने लाइफ पार्टनर से एकांत में मिल सकेंगे। चौंकिए मत, यह पहल पंजाब सरकार ने की है और इसकी वजह है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसी साल पहुंचे कुछ मामले। कोर्ट में पहला मामला मार्च 2022 में गुरुग्राम की एक महिला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची। उसकी पिटीशन दूसरे केसों से कुछ अलग थी। महिला ने जेल में बंद पति से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत मांगी थी। महिला ने दलील दी कि वह जेल में बंद पति से अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है। महिला ने कहा कि उसके पति को गुरुग्राम कोर्ट ने हत्या और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया। 2018 के बाद से ही वह भोंडसी जिले की केंद्रीय जेल में बंद है।

दूसरा मामला जनवरी 2022 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पत्नी ने अपने पति से अलग कमरे में मिलने का समय मांगा। उसने संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला दिया, जिसमें उसे इसका अधिकार मिला है। तीसरा मामला जसवीर सिंह ने **याचिका दायर कर कहा था** कि उसे अपना वंश आगे बढ़ाना है। पत्नी के गर्भवती होने तक उसे जेल में साथ रहने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। इसी जसवीर सिंह बनाम पंजाब सरकार के केस में हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाकर इस बारे में नीति बनाने को कहा था।

जिसके बाद पंजाब सरकार ने अहम पहल की। यहां की जेल में कैदियों को जीवन साथी संग अकेले में कुछ समय बिताने की इजाजत दी जा रही है। इसके लिए जेल में अलग कमरा बनाया गया है। फिलहाल यह सुविधा इंदवाल साहिब, नाभा, लुधियाना और बठिंडा महिला जेल में शुरू की जा चुकी है। इसे सभी जेलों में शुरू करने की तैयारी है। लेकिन यह सुविधा अभी हर अपराधी के लिए नहीं है। कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सजा काट रहे कैदियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। जेल अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कैदी पहले जेल प्रशासन को एप्लिकेशन देता है। अर्जी मंजूर होने के बाद अच्छे आचरण वाले कैदियों को दो घंटे तक अपने जीवनसाथी के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए जेल प्रशासन ने अलग कमरे तैयार किए हैं, जिनमें अलग डबल बेड, टेबल और अटैच बाथरूम भी होगा।

इस तरह की मुलाकात से पहले पंजाब सरकार ने कुछ नियमों की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। इसमें सबसे पहले शादी का प्रमाण-पत्र है। इसके लिए सबसे पहले पति-पत्नी होने का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण-पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। जिसमें एचआईवी, यौन संचार रोग (एसटीडी), कोरोना संक्रमण व अन्य ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जेल प्रशासन दो घंटे का समय देगा, जिस पर पति-पत्नी अकेले में समय बिता सकेंगे।

पति-पत्नी के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए पंजाब सरकार ने गल-वकड़ी प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। यह सुविधाएं ऊपरी तीन जेलों के अलावा अमृतसर में शुरू की गई है और जल्द ही लुधियाना में भी शुरू होने वाली है। जिसमें एक हॉल में कैदी अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ एक घंटे के लिए मुलाकात कर सकता है। एक साथ बैठकर वे खा-पी सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं।

जेल में बंद कैदियों के साथ बाहर उनका परिवार भी सजा भोगता है। जेल से बाहर घर संभाल रही पत्नी को मानवाधिकारों के तहत वंशवृद्धि का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत महिला ही नहीं, हर किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के बाहर कई देशों में जेल में बंद कैदी एक अलग कमरे में अपने जीवन साथी से मिलते हैं। अमेरिका, फिलीपींस, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में ये सुविधा दी जाती है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

जेल अफसरों को उम्मीद, कैदी सुधरेंगे

सीनियर अधिकारी ने बताया कि जेल में लंबे समय से मौजूद कैदियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। पत्नी या परिवार से मिलने की ललक, कैदियों को बदलने के लिए मजबूर करेगी। जेल विभाग को उम्मीद है कि उसकी इस पहल से पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और कैदी भी खुद को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जेलें असल में सुधार ग्रह में भी बदल सकती हैं। दरअसल, साल 2015 में फिरौती और उसके बाद बर्बरता से की गई नाबालिग की हत्या के मामले में फांसी और उम्र कैद की सजा भुगत रहे पति-पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। जिसके बाद कोर्ट ने जेल में कैदियों के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने और फैमिली विजिट की व्यवस्था करने के लिए सरकार को जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

अबला कौन?

सुबह-सुबह माया कामवाली बाई ने समाचार दिए कि कमलाकर की पत्नी चल बसी। पड़ोस का मामला है बैठने जाना होगा। सरिता ने सवेरे खाने के साथ ही रात के लिए बच्चो के नाश्ता बना दिया और बेटी को बता दिया कि मुझे आने देर होगी शाम को क्योंकि ऑफिस के बाद कमलाकर जी के यहां बैठक में जाना है तो भाई का ध्यान रखे दादी को भी नाश्ता कराकर समय पर दवा दे देना। बैठक में पंडित गीता पाठ कर रहा था वो भी बैठ गई, पर पंडित के पाठ से ज्यादा औरतों की काना फुसियां ज्यादा सुनाई दे रही थी कि बेचारा कमलाकर दो बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा ऑफिस और घर, बच्चे, अकेला क्या-क्या देखेगा, शादी कर देनी चाहिए। अभी जुम्मा-जुम्मा दो दिन हुए और बेचारी को गए और शादी। खैर छोड़ो, उसको घर की चिंता थी बैठक खत्म हो तो घर जाए बच्चे अकेले हैं। मोहंत के जाने के बाद सास ने गम में बिस्तर पकड़ लिया, दो बच्चो के साथ उनकी भी पूरी जिम्मेदारी और ऑफिस भी (फुल टाइम मेड रखने की हैसियत नहीं, माया से सफाई-बर्तन के काम करवाने में भी कितनी कतरब्योंत खर्चे में करनी पड़ती है।

माया की काम के साथ जुबान भी फुर्ती से चलती है। आते ही मोहल्ले के समाचार सुनानी शुरू हो जाती है। आज उसी ने बताया कमलाकर ने अपनी साली से शादी करली, मैं चोंक गई अभी तो पंद्रह दिन ही हुए हैं। हां मेम साब वो तो सही है पर बेचारे अकेले क्या-क्या देखते घर, ऑफिस और बच्चे? फिर खुद ही चुप हो गई क्योंकि वो खुद भी तो दोहरी जिमेदारी निभा रही है। मैं सोचने को मजबूर हो गई की बेचारा कौन अबला कौन?

- गीता पुरोहित

सौगात...

विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की कार हिंदुस्तानी जमीन पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। शहर के दोनों तरफ तने सफेद कपड़ों की दीवार देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा, आखिर इन सफेद दीवारों के पीछे ऐसा क्या है जो यहां का प्रशासन हमें दिखाना नहीं चाहता? सर! इन दीवारों के पीछे सस्ते वोटों की खेती है जहां सरकार कुछ रुपयों और शराब नामक खाद देकर अपने लिए वोटों की बंपर फसल उगाती है।

लेकिन इसमें छिपाने वाली बात क्या है? पूरी दुनिया में सभी नेता अपने-अपने चुनाव प्रचार में इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं।

सर, यही तो राज की बात है। दुनिया में महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन यहां के वोटों की कीमत फिक्स है चंद रुपए और शराब...और इनकी कीमत न बढ़ने पाए इसलिए ये नेता वोट लेने के बाद इन्हें देते हैं गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा व नारकीय जीवन की वो सौगात जो इन कपड़े की सफेद दीवारों के पीछे छिपा दी गई हैं।

राजकुमार कांदु

शब्द

जितना जरूरी बस, उतना बोलें
सोच विचार कर ही, मुंह खोलें
कभी-कभी चुप, रहना ही अच्छा
सिर्फ मुस्करा दें, जुबां न खोलें।

बोलने वालों को, ध्यान से सुनें
जांचें, परखें, फिर विश्लेषण करें
अच्छी बातों की, करें सराहना
नकारात्मकता को, है नकारना

अनर्गल बातों, से मुंह मोड़ लें
सोच विचार कर ही, मुंह खोलें।

प्रभावी ढंग से, कहें बात अपनी
भाषा मर्यादित हो खुशबू वतन की
छलके विश्वास और इरादे हों नेक
सबका हो सम्मान, झलके विवेक

हो सत्य का सम्बल, शब्द अलबेले
सोच विचार कर, ही मुंह खोलें।।

दूसरों की भावना का ध्यान रखिए
कडुए वचनों से, बचकर ही रहिए
निकले हुए बोल, वापस न आते
ग्लानि से भरकर, ह्रदय अकुलाते

ताला जुबां का, सलीके से खोलें
सोच विचार कर, ही मुंह खोलें।।

सच्ची और मीठी, बातें ही बोले
नाहक किसी का, दिल न टटोलें
अपनी उपलब्धियों के गुण न गाएं
उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं

महफिल में जाएं, न बने बड़बोले
सोच विचार कर, ही मुंह खोलें।

जिंदादिली, खुशमिजाजी, अपनाएं
गैरों को भी अपना, दोस्त बनाएं
वाद-विवाद में, ले सहभागिता
करें ज्ञान संग्रह, न हिचकिचाएं

परेशानियों के, पिटारे न खोलें
सोच विचार कर, ही मुंह खोलें।

जितना जरूरी, बस उतना बोलें
सोच विचार कर ही, मुंह खोलें।

- नवल अग्रवाल

बराबरी की पिच... जमकर खेलो बेटियों!

आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पुरुषों की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है। अब देश के लिए खेलने वाली महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर सैलरी मिलेगी। अभी तक पुरुष और महिला खिलाड़ियों की सैलरी में जमीन-आसमान का अंतर होता था।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय अनुबंधित महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत बोर्ड महिला क्रिकेटरों को भी अब पुरुष क्रिकेटरों के समान प्रत्येक टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपए मैच फीस देगा। इससे पहले महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक एक दिवसीय और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए एक लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि टेस्ट मैच की फीस 4 लाख रुपए थी।

बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा, 'इस फैसले से क्रिकेट की प्रगति और विकास का मंच तैयार होगा। यह महिला क्रिकेट और खेल के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।' बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक फैसला है और हम भारतीय क्रिकेट के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं।' इस फैसले की क्रिकेट जगत ने प्रशंसा की है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह खेल को लैंगिक समानता की ओर पहुंचाने के लिए महज एक कदम है। पुरुष क्रिकेटरों को केंद्रीय अनुबंध में ए कैटेगरी में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि महिलाओं के लिए यह राशि 50 लाख रुपए है। क्रिकेटर मिताली राज ने कहा, 'यह ऐतिहासिक कदम है। महिला क्रिकेट के लिए नया सवेरा है। समान मैच फीस और महिला आईपीएल महिला क्रिकेट को वहां ले जाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं, जहां पुरुष क्रिकेट आज है।'

इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड क्रिकेट समान मैच फीस लागू करने वाला पहला बोर्ड था, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में काम कर रहा है। सच में यह एक ऐतिहासिक फैसला है। वरना यह बात सभी को पता है कि महिला खिलाड़ियों को वह स्टारडम कभी नहीं मिला जो पुरुष खिलाड़ियों को मिलता है। ना ही लोगों के अंदर महिला खिलाड़ियों को लेकर वह क्रेज रहा है जो पुरुष खिलाड़ियों के लिए होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिताली राज हैं। जिन्हें लेडी सचिन तेंदुलकर तो कहा गया, जबकि उनके लिए उनका नाम की काफी होना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि बेटियां कुछ अच्छा करें तो आप उन्हें गर्व से बोल दो कि, ये तो हमारा बेटा है। वैसे ही अगर महिला खिलाड़ी अच्छा खेल रही है तो उसे लेडी सचिन बना दो। अरे बेटी को बेटी ही कहो और मिताली को उसके नाम से ही बुलाओ, ना कि उसे किसी और के नाम की उपाधि दो।

ऐसे तो वह हमेशा उस नाम के नीचे ही दबी रहेगी। मिताली राज यानी महिला क्रिकेट की सचिन तेंडुलकर लेकिन क्यों? वह मिताली हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट जगत में रिकॉर्ड बनाए हैं। वे आज की युवा महिलाओं की आदर्श हैं। उनकी पहचान किसी और के नाम से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी इतनी जगह बना ली है कि उन्हें किसी महान खिलाड़ी का नाम देने की जरूरत ही नहीं है। लेडी सचिन नाम देने से अगर उन्हें कोई नुकसान नहीं है तो फायदा भी नहीं है।

महिला खिलड़ियों की बात कर लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उन्होंने एहसान कर दिया हो। लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर खत्म हो गया है, लेकिन यह अंतर महिला और पुरुष क्रिकेट जगत में हम सरेआम देख सकते हैं। दोनों के खेल के तरीके में ही अंतर है तो बाकी का तो छोड़ ही दीजिए।

पुरुष और महिला खिलाड़ियों की सैलरी में जमीन-आसमान का अंतर होता है। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज को बीसीसीआई ने बी ग्रेड लिस्ट में रखा था। उस वक्त मिताली की सालाना इनकम 30 लाख रुपए थी, जबकि पुरुष टीम के कप्तान विराट कोहली ए+ ग्रेड में थे और उनकी एक साल की सैलरी 7 करोड़ रुपए थी। इस रिपोर्ट के अनुसार तो विराट को मिताली से 23 गुना से ज्यादा सैलरी मिलती थी। सबसे बड़ा अंतर तो यही हैं। इसी तरह पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में महिला खिलाड़ियों का इंक्रीमेंट भी कम होने की बातें भी सामने आई हैं। इस हिसाब से अब भारत में महिला खिलाड़ियों के लिए एक नई शुरुआत होगी, जिसे पूरी दुनिया देखेगी और अपनाएगी। सोचिए जिन खिलाड़ियों ने फीस में भेदभाव का सामना किया होगा वे आज कितना खुश होंगी। हो सकता है कि वे अपने समय को याद कर भावुक भी हो रही होंगी। सच में इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बदौलत हम अपने देश में महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। इस फैसले के बाद लोग अपनी बेटियों को क्रिकेट जगत में भेजने का मन बनाएंगे। समाज में बराबरी देख, शायद अब लोगों को बेटियां बोझ न लगें। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि एक एहसास है जिसे आज हर देशवासी महसूस कर रहा है। इसे कहते हैं सही मायने में जेंडर इक्वालिटी।

● **आशीष नेमा**

गोविंदा ने जाहिर की थी रेखा के साथ डेट पर जाने की इच्छा, कहा था- मैं बहुत बड़ा फैन हूं

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की दीवानगी देखने लायक है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर कोई उन्हें पसंद करता है। रेखा के चाहने वालों की कमी नहीं है। बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वह जहां जाती हैं वहां लोगों को अपना दीवाना बना लेती हैं।

कई बॉलीवुड सेलेब्स उनके साथ डेट पर जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसमें गोविंदा से लेकर राकेश रोशन तक कई सेलेब्स शामिल हैं। सिमी ग्रेवाल के शो में बॉलीवुड सेलेब्स अपने दिल की बात खुलकर रखते नजर आते थे। ऐसे ही एक एपिसोड में गोविंदा और राकेश रोशन ने अपने दिल की बात जाहिर की थी। सिमी ग्रेवाल के शो में एक बार गोविंदा और राकेश रोशन से पूछा गया था कि दुनियाभर में कोई एक ऐसा शख्स बताइए जिसके साथ आप डेट पर जाना चाहते हैं। गोविंदा और राकेश रोशन दोनों ने ही रेखा का नाम लिया था। दरअसल, सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर अपने टॉक शो का एक वीडियो शेयर किया था। सिमी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मेरी फैंटसी डेट। थ्रोबैक। वीडियो में सिमी अपने सिग्नेचर व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं और अपने गेस्ट से सेम सवाल पूछती नजर आ रही हैं। वह हर किसी से पूछ रही हैं कि हर दुनियाभर में आपको किसी के साथ डेट पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे। इस पर गोविंदा ने जवाब दिया- मैं बहुत बड़ा फैन हूं रेखा जी का। उनके साथ मैं डेट पर जाना चाहूंगा।

...जब करीना कपूर का फूटा गुस्सा, संजय लीला भंसाली को कह दिया था कन्फ्यूज्ड

करीना कपूर खान की गिनती आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है। करीना लगभग हर बड़े स्टार और उन फिल्ममेकर्स के साथ काम कर चुकी हैं, जिनके साथ अन्य हीरोइनें काम करने के सपने देखती हैं। लेकिन करीना को एक डायरेक्टर के साथ काम न कर पाने का मलाल शायद आज भी है। यह हैं संजय लीला भंसाली।

दरअसल, करीना कपूर ने देवदास की रिलीज से दो साल पहले यानी 2000 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी थी, जिसमें वह अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई थीं। फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन करीना को नोटिस किया गया था। उसी दौरान जब संजय लीला भंसाली ने करीना को देवदास के लिए अप्रोच किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। पर यह खुशी तब गम में बदल गई जब करीना को फिल्म से हटा दिया गया। करीना देवदास के लिए पारो के रोल में एक स्पेशल फोटोशूट भी कर चुकी थीं। कई साल पहले दिए एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने इस बारे में पूछे जाने पर भंसाली पर खूब गुस्सा निकाला था।

करीना ने कहा था, संजय लीला भंसाली एक कन्फ्यूज डायरेक्टर हैं। वह ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते। उनके जिंदगी में कोई सिद्धांत नहीं हैं।

फिल्म के सेट पर शाहरुख खान के गाल पर पड़ा था जूही चावला का झन्नाटेदार थप्पड़

जूही चावला की सुर्खियों से पुरानी यारी रही है। वह फिल्में करें ना करें, सुर्खियां वह बनाती रहती हैं। जूही चावला और शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान की फिल्म राम जाने में भी उनके साथ जूही चावला थीं। 'अंजाम', 'बाजीगर' और 'डर' के अलावा शाहरुख खान इस फिल्म में भी निगेटिव किरदार में नजर आए। बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी किसी सीन के डिस्कशन के दौरान गुस्से में आकर जूही चावला ने शाहरुख खान को थप्पड़ मार दिया था। जूही चावला शुरू से ही गर्म मिजाज की रही हैं और बताते हैं कि उनकी सेकेंड इनिंग्स में ये गुस्सा ही उनके कैरियर में बार-बार बाधा बनता रहा है। दोनों की दोस्ती सिर्फ फिल्मी नहीं है बल्कि दोनों एक-दूसरे के सुख दुख में भी काम आते हैं। बताते हैं कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में जेल में थे तो जूही चावला उनकी जमानतदार भी नबीं। रेड चिलीज से पहले शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड कम्पनी को शुरुआत की थी। फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में शाहरुख खान और जूही चावला ने साथ काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब जूही ने शाहरुख को एक थप्पड़ जड़ दिया।

बहुत सारे जिज्ञासु जो दूर-दूर से इस साहित्यिक महाकुंभ में गोता लगाकर मुक्ति की चाह में आए थे उनकी प्रतिभा भी गजब की थी। होनहार बिरवान के होत चिकने पात उक्ति यहां चरितार्थ होती दिखाई दी। कुछ जिज्ञासु संचालकों के सुर में सुर मिलाकर उनका अभिनंदन करने लगे थे।

चाटुकारिता के ज्ञान की नितांत आवश्यकता

पिछले दिनों एक साहित्यिक महाकुंभ में गोता लगाने का अवसर मिला। जब कभी कोई साहित्यिक समागम होता है और मैं नहीं जा पाती तो खुद को कोसती हूं। यह पछतावा होता है कि मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, लेकिन जब कभी चली जाती हूं तो भी अपने आपको कोसती हूं कि मैं यहां क्यों आई? इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आयोजन ऑनलाइन ही था। घर बैठे ही मुक्ति मिल रही थी। सो, मैंने भी ठान लिया कि इस बार महाकुंभ से ज्ञान की गठरी समेट लूंगी।

दूर-दूर से साहित्यिक मनीषी आए थे। बहुत दिनों पहले से ही उनके नाम के पोस्टर लगाए गए थे। उनके दर्शन से कृतार्थ होने को सब लालायित थे। मैंने भी समय पर महाकुंभ में उपस्थिति दर्ज कराई। इस साहित्यिक महाकुंभ में उन्हीं विद्वानों और मनीषियों को बुलाया गया था, जो आयोजकों से परिचित थे या उनके मित्र थे। विषय की विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसको जो आता था उसको वही बोलना था।

महाकुंभ का प्रारंभ ढोल-नगाड़े के साथ हुआ। सरस्वती वंदना के गायन के लिए भी संचालक महोदय की मित्र को ही बुलाया गया था, जिनके सुर-ताल में कोई सामंजस्य होना आवश्यक नहीं था। जब सभी मनीषी जुटे थे तो चिंतन-मनन करके निष्कर्ष तो निकालना ही था तो सबने अपने-अपने दायित्व का निर्वाह बड़ी निष्ठा से किया। अनेक साहित्यिक विमर्शों के साथ ही नई शिक्षा नीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। बड़े मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक कॉलेज में चाटुकारिता का विषय अवश्य पढ़ाया जाए। सबका एकमत से यही कहना था कि आज के इस दौर में चाटुकारिता के ज्ञान की नितांत आवश्यकता है।

यह सभी क्षेत्रों में काम आता है। जल्द ही मुझे पता चला कि आजकल साहित्यिक प्रतिभा से अधिक साठगांठ की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। यदि आप अच्छे वक्ता हैं और आयोजकों से परिचित नहीं हैं तो आपकी प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है। यदि आप आयोजकों से परिचित हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो सकते हैं तो आप हर गोष्ठी का संचालन कर सकते हैं। यदि आप सम्मान दिलाने वाले गुट से जुड़े हैं या उनका शुल्क दे सकते हैं तो किसी भी राज्य से आपको सम्मान मिल सकता है। इसके लिए जरूरी काम करना आवश्यक नहीं है।

यही नहीं कई दिनों तक आपके नाम के पोस्टर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर घूमते रहेंगे। इसके साथ मुझे यह भी पता चला कि साहित्यिक जगत में अनेक संप्रदाय हैं और गठबंधन के अनेक विभाग हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपका गठबंधन किसके साथ और कितना मजबूत है। मंच पर एक दिव्य व्यक्तित्व वाले महात्मा विराजमान थे, पर उनके आसपास शिष्यों का जमावड़ा न के बराबर था। अधिकांश जिज्ञासु आयोजकों और संचालकों के आस-पास ही मंडरा रहे थे। शायद वे किसी गठबंधन से संबंधित नहीं थे।

बहुत सारे जिज्ञासु जो दूर-दूर से इस साहित्यिक महाकुंभ में गोता लगाकर मुक्ति की चाह में आए थे, उनकी प्रतिभा भी गजब की थी। होनहार बिरवान के होत चिकने पात उक्ति यहां चरितार्थ होती दिखाई दी। सुना है कि कुछ जिज्ञासु तो पहले दिन से ही संचालकों के सुर में सुर मिलाकर उनका अभिनंदन करने लगे थे। आदर से पैर पखारने लगे थे। कहते हैं कलियुग में हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। उन्हें भी फल तुरंत मिला और वे भी साहित्यिक महाकुंभ के किसी न किसी समिति के पदाधिकारी बन गए। उन्हें अनेक प्रमाण पत्र और पुरस्कार मिल गए। यही नहीं, कई शोधार्थियों को तो रिसर्च पेपर लिखने का ठेका भी मिल गया। शायद इसे ही कहते हैं- एक हाथ ले, एक हाथ दे।

मेरे पाप की गठरी बड़ी भारी थी। मुझे चाटुकारिता करनी नहीं आई और न ही मैं अवसरवादिता के गुण में दक्ष थी। शायद इसीलिए मुझे मोक्ष नहीं मिला, लेकिन मन में एक संतोष का भाव अवश्य आया। जो दो-चार साहित्यिक मूल्य मिले, उन्हीं को ग्रहण कर अपने मन को आह्लादित कर लिया।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

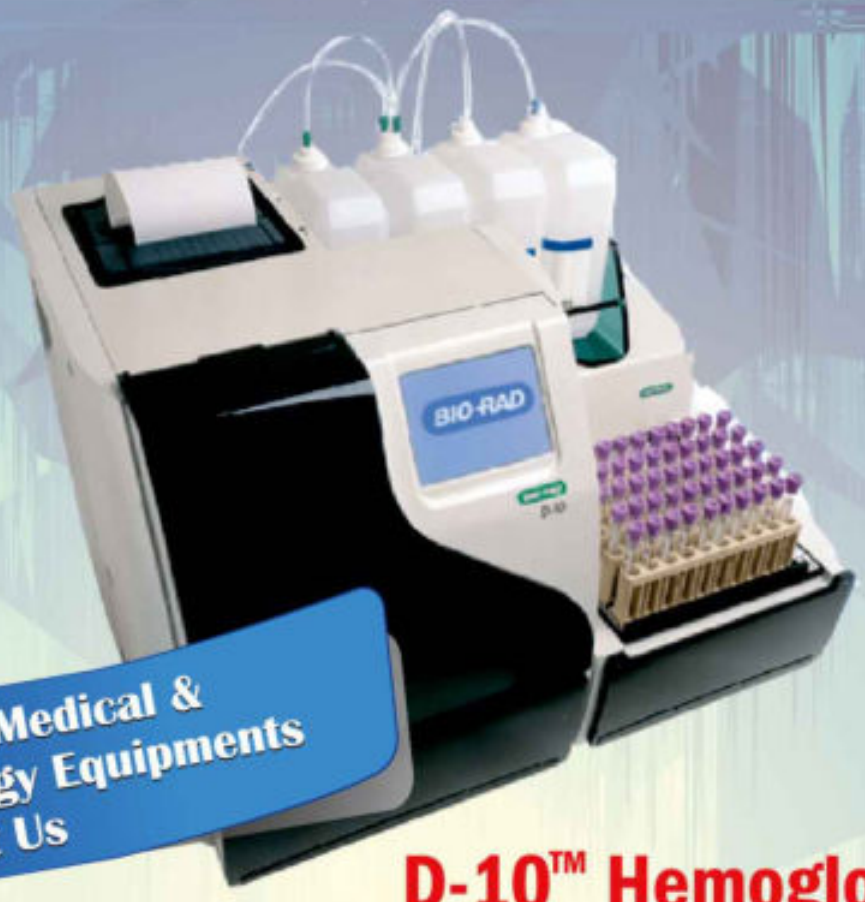

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं इसलिए कोयला निकालते हैं

कोल इण्डिया Coal India

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अनुषंगी कम्पनी

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CCLRanchi | CentralCoalfieldsLtd | centralcoalfieldsltd | Central Coalfields Limited | cclranchi